चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

मोदी से सब डरते हैं

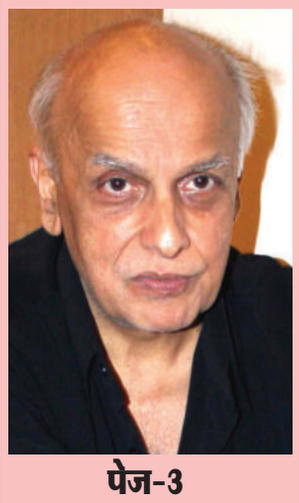

पेज-3

नीतीश को जगदानंद की सलाह

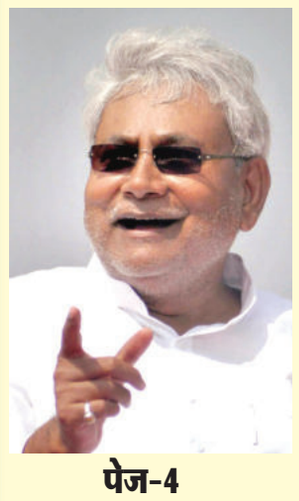

पेज-4

मुसलमानों को दिखी उम्मीद की एक नई किरण

पेज-7

साई की महिमा

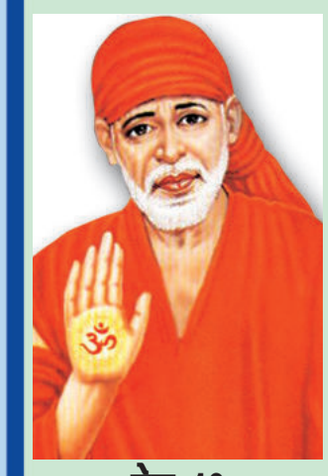

पेज-12

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 17 अक्टूबर–23 अक्टूबर 2011 | मूल्य 5 रुपये

टाटा स्टील और झारखंड सरकार की लूट

सरकारी बाबू घूस लेते पकड़ा जाए तो नौकरी जाएगी, आम आदमी क़ानून तोड़े तो जेल जाएगा, बड़े अधिकारी भी कभीकभार क़ानून के हत्थे चढ़ जाए तो शायद उन्हें सजा मिल जाए, लेकिन अरबपति उद्योगपतियों का हर गुनाह माफ! क्या फ़र्क़ पड़ता है, वे खुलेआम क़ानून का मजाक उड़ाएं, सरकारी नियम-क़ायदे तोड़ें. क्या मजाल कि कोई उन पर हाथ डाल दे, क्योंकि सरकार उनकी जेब में होती है. अब टाटा को ही देखिए कि उन्होंने झारखंड की खनिज संपदा हथियाने और उससे अरबों-खरबों कमाने के चक्कर में किस कदर नियमों की अनदेखी की है. बावजूद इसके टाटा को झारखंड सरकार की सरपरस्ती हासिल है. क्या है यह घालमेल, पढ़िए चौथी दुनिया की इस ख़ास रिपोर्ट में.

फोटो–प्रभात पाण्डेय

शशि शेखर

झारखंड खनिज संपदा से भरा पड़ा है. फिर भी वहां ग़रीबी है, नक्सलवाद है, बेरोज़गारी है और भुखमरी भी. बावजूद इसके कि इस राज्य में टाटा से लेकर मित्तल ग्रुप तक का अरबों का व्यापारिक साम्राज्य कायम है. समृद्धि की कौन कहे, ज़्यादातर वाशिंदों को दो वक़्त की रोटी भी मयस्सर नहीं. वजह यह कि अरबपति औद्योगिक घराने इनकी हक़मारी कर रहे हैं, अपनी जेबें भरने की ख़ातिर इन ग़रीबों के पेट पर लात मार रहे हैं. चौथी दुनिया की ख़ास पड़ताल इस राज्य की बदहाली के पीछे की एक बड़ी वजह को उजागर करती है. साफ़ है कि कैसे नियमों की अनदेखी करते हुए बड़े-बड़े औद्योगिक समूह यहां की खनिज संपदाओं का न सिर्फ़ दोहन कर रहे हैं, बल्कि आर्थिक रूप से उनका शोषण भी. मामला झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम ज़िले के अंतर्गत आने वाले नोवामुंडी में लौह अयस्क खनन पट्टा से जुड़ा है, जहां टाटा को खनन पट्टा मिला हुआ है. ***1980 में, जब एकीकृत बिहार हुआ करता था, टाटा (टिस्को) ने नोवामुंडी स्थित लौह अयस्क खान के नवीकरण के लिए फॉर्म जे के तहत बिहार सरकार के साथ क़रार किया. यह पट्टा अगले 32 साल के लिए टाटा को मिल गया. इस क़रार में स्पष्ट लिखा था कि इस खान का इस्तेमाल कैप्टिव माइनिंग के लिए होगा और यहां से निकाले गए अयस्क का इस्तेमाल जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के लिए ही किया जाएगा.*** नियमानुसार, अयस्कों की बिक्री भी नहीं की जा सकती थी और न किसी अन्य कंपनी को खनन के काम में शामिल किया जा सकता था, ख़ासकर राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना. इस प्रकार के करार का मक़सद राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल राज्य में ही किया जाना होता है, ताकि इससे स्थानीय स्तर पर विकास हो सके और स्थानीय लोगों को रोज़गार मिल सके.

लेकिन इन नियम-क़ायदों से टाटा को क्या लेना-देना. लिहाजा, टाटा ने खुलेआम करार के नियमों का उल्लंघन किया. इस बात की पुष्टि राज्य सरकार (झारखंड) के ज़िला खनन पदाधिकारी, चाईबासा कार्यालय द्वारा 28 जुलाई, 2005 को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को जारी वैधानिक कारण बताओ नोटिस करती है, जिसमें ***साफ लिखा है कि नोवामुंडी में टाटा के 4479 वर्ग मील में फैले लौह अयस्क क्षेत्र का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा 8 एवं 9 जुलाई को किया गया और टाटा द्वारा मिनरल कंसेशन रूल्स 1960 और खनन पट्टा की शर्तों के गंभीर उल्लंघन की सूचनाएं आई हैं. खनन पट्टा क्षेत्र के ब्लॉक 6 के 22 हेक्टेयर क्षेत्र पर राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना टाटा ने सिर्फ़ सेल-परचेज एग्रीमेंट करके फ्यूचरिस्टिक स्टील प्रा. लि. और आधुनिक स्टील लि. को आपसी सहमति से खनन के लिए दे दिया.*** ज़िला खनन पदाधिकारी चाईबासा ने टाटा स्टील को साफ़ तौर पर इंगित किया है कि आपने राज्य सरकार से अनुमति लिए बिना भारी मात्रा में लौह अयस्क की बिक्री बाहरी प्रतिष्ठानों को की है. जबकि ऐसा करना मिनरल कंसेशन रूल्स एक्ट 1960 के नियम 37 और खनन पट्टा संविदा के भाग 7/17, 9/2,3 का उल्लंघन है और यह कृत्य दंडनीय है. टाटा स्टील को इस नोटिस का जवाब 60 दिनों के भीतर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर देने को कहा गया.

इस नोटिस का जवाब टाटा की तरफ से 28 अक्टूबर, 2005 को दिया गया, जिसमें टाटा स्टील की चोरी और सीनाज़ोरी साफ़ नज़र आई. टाटा ने नियम 37 के उल्लंघन के आरोप से ही इंकार कर दिया. हालांकि 3 दिसंबर को दिए गए जवाब में टाटा ने लौह अयस्कों की बिक्री बाहरी प्रतिष्ठानों से करने की बात स्वीकारी. टाटा का कहना था कि अधिक उत्पादन की वजह से बिक्री करनी पड़ी. ***टाटा ने अपने जवाब में जो कुछ लिखकर दिया, उसके मुताबिक़ (25 अक्टूबर, 2005 का पत्र-प्वाइंट नंबर-इ) माइनिंग लीज में अयस्कों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं है, जबकि नवीकरण (1980) फॉर्म जे में साफ़-साफ़ लिखा है कि अयस्कों का इस्तेमाल सिर्फ़ जमशेदपुर स्थित कारखाने के लिए किया जाना है. अब सवाल उठता है कि माइनिंग लीज सही है या 1980 में नवीकरण फॉर्म जे में टाटा द्वारा दर्ज कराए गए तथ्य.*** बहरहाल, अब यह पूरा खेल बिना किसी सरकारी कार्रवाई के निर्बाध रूप से आगे बढ़ रहा था. एक बार फिर ज़िला खनन पदाधिकारी, चाईबासा ने एक पत्र 22 फरवरी, 2008 को झारखंड सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव को लिखा कि टाटा स्टील द्वारा राज्य सरकार के मिनरल कंसेसन रूल्स 1960 के वैधानिक आवेदन पत्र फॉर्म एवं नवीकरण फॉर्म जे में आवेदित कैप्टिव प्रयोग के लिए मिले पट्टे से लौह अयस्क की बिक्री एवं निर्यात किए जाने की सूचना पहले ही राज्य सरकार को दी जा चुकी है, लेकिन

(शेष पृष्ठ 2 पर)

क्या केंद्र सरकार को जानकारी थी?

अप्रैल 2009 में फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज दिल्ली ने भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को पत्र लिखकर टिस्को द्वारा लौह अयस्क की बिक्री के बारे में सूचित किया और इस पर अपना विरोध जताया. भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने यह पत्र अपने मातहत काम करने वाली संस्था इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस को भेजा. फिर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के चीफ मिनरल इकोनॉमिस्ट ने जून 2009 में झारखंड सरकार के खनन निदेशक को पत्र लिखकर इस संबंध में सारी जानकारी मांगी थी.

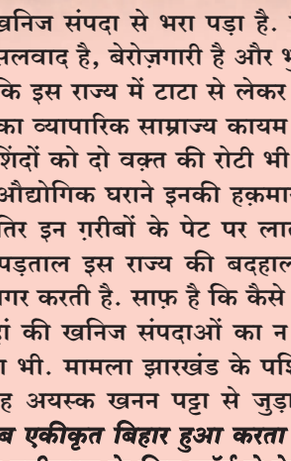

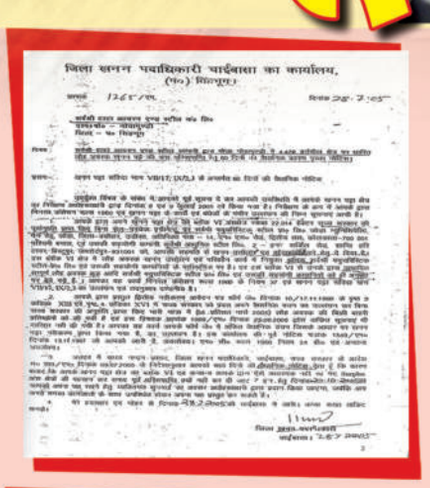

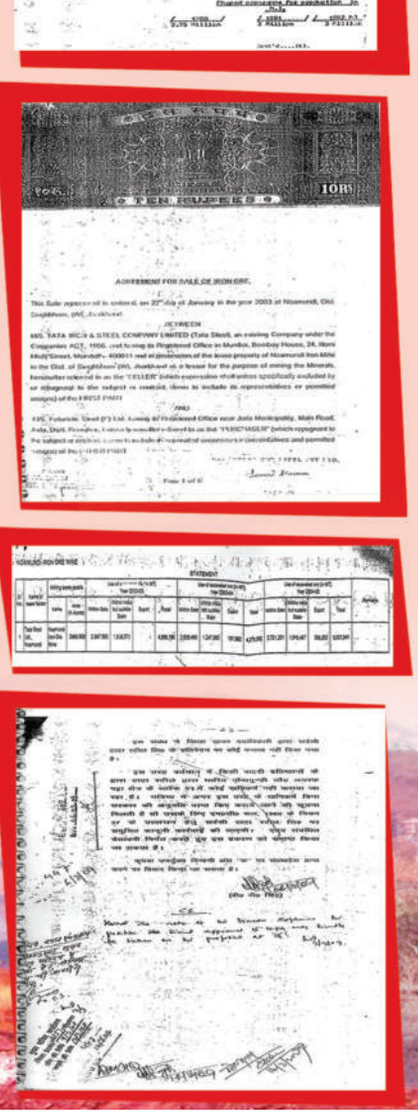

आधुनिक और टी मुखर्जी

बीते सितंबर महीने में आयकर विभाग ने आधुनिक ग्रुप के 27 ठिकानों पर छापा मारा. छापे में आधुनिक ग्रुप के संचालक अग्रवाल बंधुओं से कई दस्तावेज ज़ब्त किए गए. इस दौरान अग्रवाल बंधुओं से जुड़े टी मुखर्जी के ठिकानों पर भी कार्रवाई हुई. यह टी मुखर्जी पहले टिस्को से ही जुड़े थे, अब आधुनिक के साथ हैं. इस छापेमारी से यह जानकारी मिली कि आधुनिक ग्रुप खनन की मात्रा की सही जानकारी सरकार को नहीं देता था. अग्रवाल बंधुओं ने टाटा स्टील के टी मुखर्जी की सहायता से पहले स्क्रैप का कारोबार शुरू किया था. आज इसी आधुनिक ग्रुप का करोड़ों का कारोबार है. जाहिर है कि इस ग्रुप के आगे बढ़ने में टी मुखर्जी का भी योगदान कुछ कम नहीं रहा होगा.

जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है, लेकिन उस पर अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं हुई है. टी एस विजयन ने पांच साल पूरे करने के बाद इस पद पर सेवा विस्तार लेने से मना कर दिया.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

माया‌वती की मनमानी

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती को इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि उनके राज्य में पुलिस प्रमुख का पद रिक्त है. बीते अगस्त माह में डीजीपी कर्मवीर सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद आर के तिवारी ने कार्यभार संभाला है, लेकिन अभी तक किसी को स्थायी रूप से पुलिस प्रमुख नहीं बनाया गया है. इसके पीछे कारण कुछ और बताया जा रहा है. मायावती इस पद पर किसी ऐसे अधिकारी को नियुक्त करना चाहती हैं, जो उनके प्रति वफादार हो. यही कारण है कि बहुत सारे योग्य अधिकारियों के बावजूद वह इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं कर रही हैं. जानकारों का कहना है कि मायावती इस पद पर डीजीपी (विशेष) बृजलाल को नियुक्त करना चाहती हैं, लेकिन इस पद के लिए जिस वरिष्ठता की आवश्यकता है, उसके लिए बृजलाल को कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा.

प्रोन्नति की प्रतीक्षा

पंजाब पुलिस के अधिकारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. वहां के डीजीपी पी एस गिल के अनुसार, पंजाब पुलिस के तीस अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा का ग्रेड मिल सकता है. ऐसा करीब एक दशक के बाद हो रहा है कि इतने अधिक राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की प्रोन्नति भारतीय पुलिस सेवा के स्तर पर की जाएगी, लेकिन देरी इस कारण हो रही है कि जो लोग सीधे डीएसपी बने हैं और जो प्रोन्नति के माध्यम से डीएसपी बने हैं, उनके बीच थोड़ा विवाद है. सरकार का फैसला ही इस विवाद को समाप्त कर सकता है. जिन अधिकारियों की प्रोन्नति होनी है, उनमें बी एस सिद्धू, मुनीश चावला, अमर सिंह चाहल, एम एस चीना का नाम शामिल है. पंजाब पुलिस के बाबुओं को इसका बेसब्री से इंतजार है.

जीवन बीमा को अध्यक्ष का इंतजार

पी जे थॉमस की नियुक्ति से हुई किरकिरी से सरकार सावधान हो गई है. अब वह किसी भी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति के पहले इस बात का ध्यान रखती है कि थॉमस वाली घटना फिर से न घट जाए. जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है, लेकिन उस पर अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं हुई है. टी एस विजयन ने पांच साल पूरे करने के बाद इस पद पर सेवा विस्तार लेने से मना कर दिया. अभी जीवन बीमा निगम में दो अंतरिम अध्यक्ष आर के सिंह और डी के मेहरोत्रा हैं. सूत्रों के अनुसार, इस पद पर नियुक्ति में देरी होने का कारण यह है कि जिन लोगों को बहाल किया जा सकता है, उनमें कुछ लोगों को विजिलेंस से क्लीयरेंस नहीं मिल पाई है. इसका प्रभाव इस पद पर नियुक्ति के लिए होने वाले साक्षात्कार पर पड़ रहा है. अब देखते हैं कि कब तक यह पद अध्यक्ष का इंतजार करता है.

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

जेएस बने सतपाल और सुप्रिया

वर्ष 1983 बैच के आईइएस अधिकारी सतपाल चौहान को गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है. उन्होंने के सी जैन की जगह ली, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं. इसी प्रकार 1991 बैच की आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है.

सरकार को अतिरिक्त प्रभार

वर्ष 1975 बैच के आईएएस अधिकारी जवाहर सरकार को सूचना एवं प्रसारण सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. यह पद रघु मेनन की सेवानिवृत्ति से खाली हुआ है.

35 अधिकारियों को सचिव का दर्जा

वर्ष 1978 बैच के अधिकारियों के लिए खुशखबरी है. इस बैच के 35 आईएएस अधिकारियों को सचिव का दर्जा दिया गया है. इसके लिए फाइल पीएमओ में जा चुकी है.

चार नए सचिव बनाए जाएंगे

सूचना प्रसारण मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को सचिव की तलाश है. इन पदों पर नियुक्ति का निर्णय शीघ्र होगा.

टाटा स्टील और झारखंड सरकार की लूट

पृष्ठ एक का शेष

इस पर किसी तरह के आदेश की प्रतीक्षा है. ***इस पत्र में चेतावनी दी गई थी कि यदि टाटा स्टील के कारनामों के ख़िलाफ़ कठोर निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले समय में झारखंड सरकार द्वारा अनुशंसित सभी 21 मामलों के आवेदक इस मामले का उदाहरण लेकर खनिज की बिक्री करेंगे और नियम–क़ायदों को तोड़ेंगे.***

इस पूरे प्रकरण में एक जो मज़ेदार बात है, वह यह कि एक ज़िला स्तर का पदाधिकारी गड़बड़ियों को पकड़ता है, सरकार को बार–बार सूचित करता है, घपलों की चेतावनी देता है, लेकिन ऊपर बैठे अफ़सरशाहों और सरकार की पेशानी पर बल नहीं पड़ते. वे उद्योगपतियों के जर ख़रीद गुलामों की तरह टाटा स्टील की कारगुज़ारियों को मौन सहमति देते रहे. होता यह है कि झारखंड सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक–खनन बी बी सिंह इस पूरे प्रकरण से जुड़ी एक रिपोर्ट मार्च 2009 को बनाते हैं. इस रिपोर्ट के बिंदु संख्या 4 में ज़िला खनन पदाधिकारी चाइबासा के उस पत्र का ज़िक्र तो करते हैं, जिसमें टाटा द्वारा लिखित इक़रारनामा के तहत फ्यूचरिस्टिक और आधुनिक स्टील को नोवामुंडी खान के ब्लॉक 6 में खनन की अनुमति देने और लौह अयस्क की बिक्री बाहर करने की बात है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते, बल्कि टाटा स्टील का पूरी तरह बचाव करते नज़र आते हैं. ज़रा आप भी ग़ौर करें कि इस रिपोर्ट के अंश क में बी बी सिंह ने क्या लिखा है. ***वह लिखते हैं, इस तरह वर्तमान में किसी बाहरी प्रतिष्ठानों द्वारा टाटा स्टील द्वारा धारित नोवामुंडी लौह अयस्क पट्टा क्षेत्र के ब्लॉक 6 में कोई खनिक कर्म नहीं कराया जा रहा है. भविष्य में अगर इस तरह के खनिक कर्म बिना सरकार की अनुमति प्राप्त किए कराए जाने की सूचना मिलती है तो उसके लिए मिनरल कंसेशन रूल्स 1960 के नियम 37 के उल्लंघन हेतु सर्वश्री टाटा स्टील लि. पर समुचित क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी. एतद् संबंधित चेतावनी निर्गत करते हुए इस प्रकरण को समाप्त किया जा सकता है. कृपया उपर्युक्त टिप्पणी अंश पर राज्यादेश प्राप्त करने पर विचार किया जा सकता है.***

फोटो–प्रभात पाण्डेय

इस पत्र की भाषा हैरतअंगेज है. यकीन नहीं होता कि यह रिपोर्ट किसी वरिष्ठ अधिकारी ने तैयार की है. बी बी सिंह द्वारा टाटा स्टील को दी गई झिड़की कुछ ऐसी है, जैसे किसी बच्चे ने कोई छोटी–मोटी लापरवाही कर दी हो और स्कूल टीचर ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया हो. बहरहाल, बदले हुए घटनाक्रम के बाद बी बी सिंह 20 मई, 2009 को टाटा स्टील को भी पत्र लिखकर सूचित करते हैं कि लिखित इक़रारनामा के तहत फ्यूचरिस्टिक एवं आधुनिक स्टील को खनिक कर्म करने देने के टाटा के निर्णय को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है और भविष्य में यदि फिर ऐसा हुआ तो समुचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी यानी टाटा स्टील को और ग़लतियां करने की सरकारी इजाज़त मिल गई. क्या यह कुछ वैसा ही नहीं हुआ कि हत्या के किसी आरोपी को यह कहकर रिहा किया जा रहा हो कि चलो तुम्हारा एक ख़ून तो माफ़ है, पर यदि दोबारा तुमने किसी की जान ली तो तुम्हें सज़ा दी जाएगी. यह सही है कि हत्या जैसे गंभीर मामले से इस प्रकरण की तुलना उचित नहीं है, लेकिन झारखंड जैसे राज्य में जहां करोड़ों ग़रीबों के जीने का सहारा उनकी खनिज संपदा है, ऐसे में उसकी लूट उनकी ज़िंदगियों से खेलने के बराबर है. यह बात वाकई हैरान कर देने वाली है कि जब सरकारी दस्तावेज में बड़े–बड़े अधिकारी यह स्वीकार कर रहे हों कि टाटा स्टील ने ग़लती की, तो फिर ग़लती की सज़ा देने के बजाय माफ़ी क्यों?

shashishekhar@chauthiduniya.com

रिपोर्ट के अंश क में बी बी सिंह ने लिखा है कि वर्तमान में किसी बाहरी प्रतिष्ठानों द्वारा टाटा स्टील द्वारा धारित नोवामुंडी लौह अयस्क पट्टा क्षेत्र के ब्लॉक 6 में कोई खनिक कर्म नहीं कराया जा रहा है. भविष्य में अगर इस तरह के खनिक कर्म बिना सरकार की अनुमति प्राप्त किए कराए जाने की सूचना मिलती है तो उसके लिए मिनरल कंसेसन रूल्स 1960 के नियम 37 के उल्लंघन हेतु सर्वश्री टाटा स्टील लि. पर समुचित क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

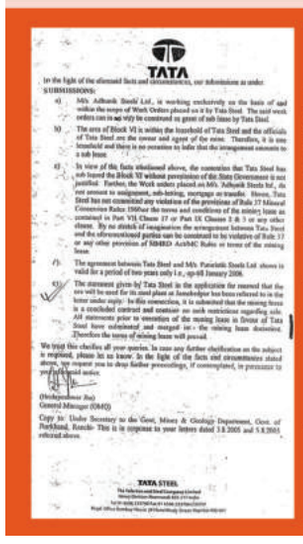

EXPORT OF IRON ORE FROM NOAMUNDI IRON MINE OF TATA STEEL (Figures in tonnes)

Year	Qty
2008-09 (till Jan'09)	NIL
2007-08	NIL
2006-07	NIL
2005-06	39643.900
2004-05	506427.790

Stopped Export of Ore from middle of 2005-06 onwards.

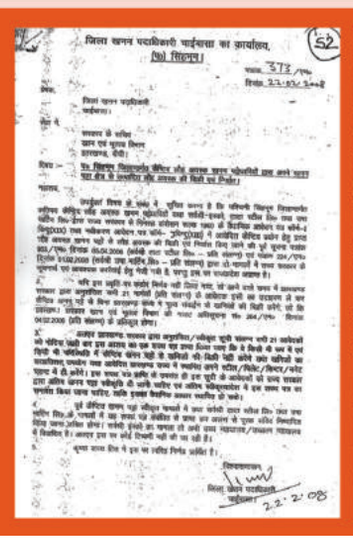

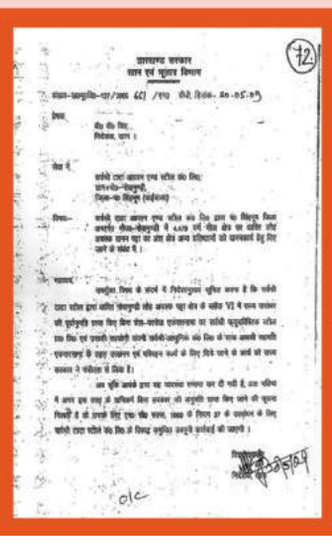

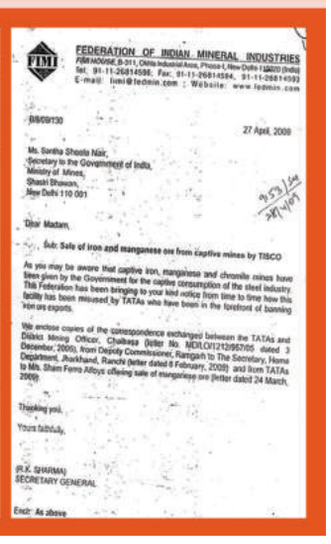

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 32
दिल्ली, 17 अक्टूबर–23 अक्टूबर 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर) (उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/011–23418962
0120–6450888, 0120–6452888
0120–6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120–4783999
+91 9266627366
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.
समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

जो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बोलने का साहस करता है. उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है और अगर तब भी वह हथियार नहीं डालता तो इस प्रकार के एक्शन लिए जाते हैं.

मोदी से सब डरते हैं: महेश भट्ट

गुजरात के आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 2002 के दंगों के सिलसिले में नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ बयान देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया. देश भर से कई हाथ उनके समर्थन में उठे. प्रसिद्ध फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने भी दिल्ली आकर संजीव भट्ट की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ अपना विरोध दर्ज कराया. चौथी दुनिया उर्दू की संपादक *वसीम राशिद* ने इस संबंध में उनसे विस्तार से बातचीत की. पेश हैं प्रमुख अंश:

आप किस बुनियाद पर संजीव भट्ट का साथ दे रहे हैं?

दिल किसी पर क्यों यक़ीन करता है, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है. संजीव की बातों पर यक़ीन इसलिए है, क्योंकि गुजरात में उनके साथ जो हो रहा है, वह पहली बार नहीं हुआ और न आख़िरी बार होगा. 2002 के बाद हमने भाजपा की एलिमीनेशन पॉलिसी देखी है, जिसके द्वारा वहां हर उस व्यक्ति को टारगेट किया जाता है, जो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बोलने का साहस करता है. उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है और अगर तब भी वह हथियार नहीं डालता तो इस प्रकार के एक्शन लिए जाते हैं. हरेन पांड्या को मार दिया गया और फिर उन्हें भी, जिन्हें पांड्या को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया था.

ऐसा क्यों है कि एक आईपीएस अधिकारी पीड़ितों के हक के लिए लड़ता है और लोग उसका साथ देने के बजाय ख़ामोश रहते हैं?

वहां की ज़मीनी सच्चाई यह है कि वहां का आईपीएस अधिकारी डरा हुआ है. किरण बेदी ने एक टीवी शो में ख़ुद कहा कि जब उन्होंने देखा कि किसी कांस्टेबिल के बयान पर एक आईपीएस अधिकारी को जेल भेज दिया गया तो उन्होंने गुजरात फोन किया और एक पुलिस अधिकारी दोस्त से पूछा कि वहां क्या हो रहा है, संजीव को क्यों गिरफ्तार किया गया, सच्चाई क्या है, तो उसने जवाब दिया कि वह मोबाइल पर यह बात नहीं कर सकता. ऐसे डर के माहौल में भला कौन अधिकारी या व्यक्ति संजीव के साथ खड़ा होने की हिम्मत कर सकता है.

कहने का मतलब यह कि गुजरात एक फ़ासिस्ट राज्य बन चुका है?

जी हां, फासिस्ट राज्य! 2002 में आपने इस राज्य का फ़ासिस्ट रंग देख लिया. अब यह विकास की आड़ में बहुत कुछ छिपाना चाहता है. आंकड़े दिखाए जाते हैं, पूंजीवादियों को खड़ा किया जाता है, कभी टाटा को खड़ा कर दिया, कभी अंबानी को. हां, विकास बहुत हुआ है, यह भी एक सच्चाई है. लेकिन दूसरी सच्चाई वह भी है, जिसकी ओर संजीव भट्ट इशारा कर रहे हैं, तीस्ता शीतलवाड़ ने भी कहा था, मल्लिका साराभाई ने भी आरोप लगाए थे, शबनम हाशमी भी कह रही थीं. ये लोग जब बोलते हैं तो वहां के लोग यह कहते हैं कि ये सभी मोदी के विरोधी हैं. दरअसल यह एक पुराना खेल है, जो आज भी चल रहा है. अगर हमें सच्चाई जाननी है तो न्यायालय से अपील करनी होगी. यहां मुलजिम़ भी मोदी हैं और बचाव भी मोदी कर रहे हैं, यह कैसे हो सकता है?

क्या आपको नहीं लगता कि देश में खुद को धर्मनिरपेक्ष साबित करने के लिए मोदी का विरोध करना एक फैशन बन चुका है?

आप ही बताएं कि ऐसे लोग हैं कितने, गिनती के चार-पांच. मोदी के ख़िलाफ़ बोलने का साहस किसमें है. लोग तो यह कहते हैं कि मोदी के खिलाफ मत बोलो, क्योंकि वह अगर केंद्र की सत्ता में आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसीलिए ख़ामोश होकर बैठना बेहतर है. उनके ख़िलाफ़ बोलने का मतलब शेर के पिंजरे में जाकर उसे ललकारना है.

संजीव पर एक आरोप यह भी है कि उन्होंने कांग्रेसी नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची?

जो आदमी दूसरे राजनीतिक दल का प्रतिद्वंद्वी होता है, उसे कहा जाता है कि वह विपक्ष का बैठाया हुआ प्रतिनिधि है. आरोप लगाना और मज़ाक उड़ाना पुराना रवैया है. अन्ना हज़ारे के बारे में भी कांग्रेस ने बार-बार कहा कि वह आरएसएस के आदमी हैं. वह हैं या नहीं, यह तो आने वाला कल बताएगा. मेरे पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं है, जिससे मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकूं कि इस लड़ाई में कांग्रेस उनका साथ दे रही है या नहीं. अभी तक कांग्रेस के किसी आदमी ने उनके लिए कुछ बोला नहीं है.

जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उसमें पुलिस ने एक ईमेल का जिक्र किया है, उससे किस तरह रहस्य खुल सकते हैं?

देखिए, यह लड़ाई वही लड़ सकता है, जिसके पास न पाने के लिए कुछ है न गंवाने के लिए. मुझे संजीव एक ऐसा चेहरा लगता है, जिसके पास न कोई ऐसा अतीत है, जिसकी वह पर्दापोशी करे और न उसके पास ऐसी कोई चीज़ है, जो उसके हाथ से छिन जाएगी. यह इंसाफ़ की लड़ाई है.

संजीव भट्ट का मामला तो काफी दिनों से चल रहा था. अचानक ऐसा क्या हो गया कि इसने इतना तूल पकड़ लिया?

संजीव ने हरेन पांड्या के मामले में शपथपत्र दायर किया था, जिससे वहां की सरकार चौंकी. लोगों का कहना है कि हरेन, जो वहां के गृहमंत्री रह चुके थे, वह कुछ ऐसी सच्चाइयां जानते थे, जिन्हें वह दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे थे, इस वजह से उनकी हत्या हो गई. एक कांस्टेबिल का पुराना केस था, जिस पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में संजीव ने एक अपील दायर कर रखी थी, जिसमें लिखा था कि मैं चाहता हूं कि इस केस से मुझे बाहर कर दिया जाए, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी. अचानक हरेन पांड्या मामले में शपथपत्र दायर होने से वे लोग अलर्ट हो गए और संजीव को गिरफ्तार कर लिया गया.

आपकी आगे की रणनीति क्या है?

हमने गृहमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें उनसे त्वरित कार्रवाई करने की अपील की गई है. हमने यह मांग भी की है कि मामले की जांच राज्य से बाहर की जाए, ताकि मोदी उसे किसी भी तरीके से प्रभावित न कर सकें.

इसी दौरान भरतपुर और रुद्रपुर में भी फसाद हुआ, लेकिन इस मसले पर आप सब ख़ामोश क्यों हैं?

हमने राजस्थान सरकार को आड़े हाथों लिया. हमने नेशनल कमीशन ऑफ मॉइनारिटी से कहा कि आप ख़ुद जाकर वहां की सच्चाई को समझें और मुख्यमंत्री को आगाह करें. हम रुद्रपुर भी जाने वाले थे, लेकिन वहां कर्फ्यू लगा दिया गया और जाने की मनाही कर दी गई. हालांकि फिर भी हम इस सिलसिले में रणनीति बना रहे हैं. ऐसे मुश्किल वक्त में हम सभी को मिलकर आवाज बुलंद करनी होगी, ताकि देश को फासिस्ट ताकतों से बचाया जा सके.

feedback@chauthiduniya.com

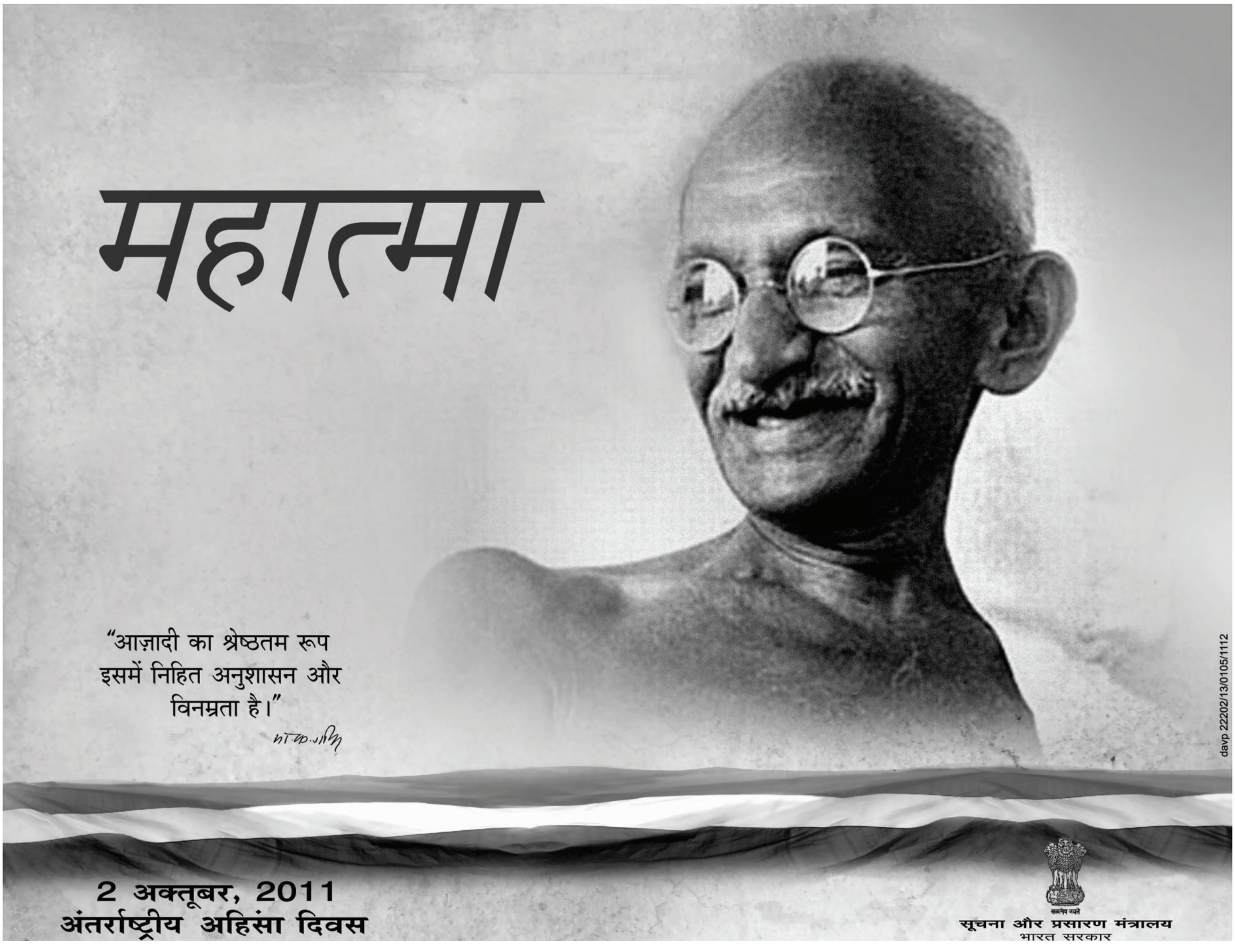

जिस दिन सदन में इस मामले को लेकर बहस हो रही थी, वहां वर्तमान मुख्यमंत्री भी मौजूद थे. वह अन्य विषयों पर तो बोले, लेकिन इस विषय पर एक शब्द नहीं बोले.

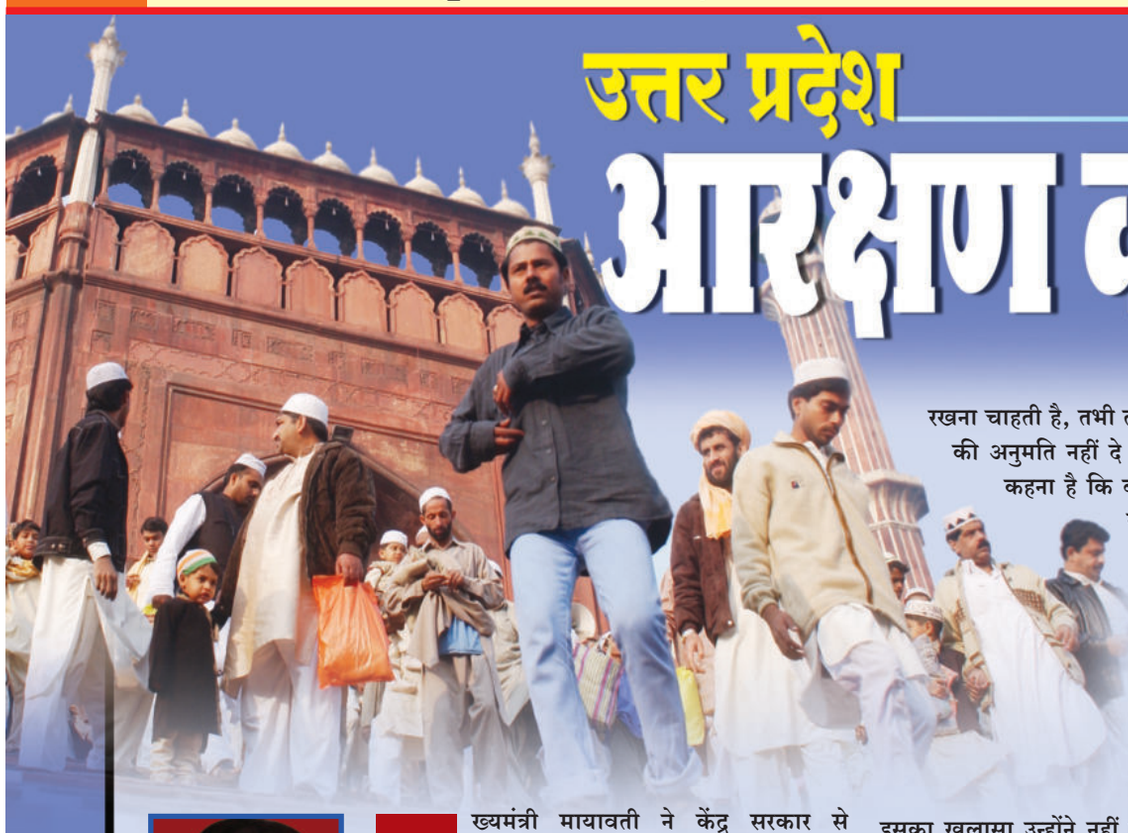

उत्तर प्रदेश

आरक्षण का मुद्दा फिर सुर्ख़ियों में

फ़िरदौस ख़ान

मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्र सरकार से मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग करके इस मुद्दे को एक बार फिर सुर्ख़ियों में ला दिया है. उन्होंने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को लिखे पत्र में कहा है कि अगर अल्पसंख्यकों, ख़ासकर मुसलमानों की हालत सुधारनी है तो यह ज़रूरी है कि शिक्षा, रोज़गार और दूसरे क्षेत्रों में उनके लिए विकल्प बढ़ाए जाएं. आज़ादी के 64 सालों बाद भी मुसलमान पिछड़े हुए हैं, सच्चर समिति की रिपोर्ट ने भी इसकी तस्दीक की है. सियासी हलक़े में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की इस मांग को विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक अपने पक्ष में करने के लिए उठाए गए क़दम के तौर पर देखा जा रहा है. इतना ही नहीं, विपक्षी दलों ने भी मायावती के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है.

मुसलमानों को आरक्षण देने के मुद्दे पर राहुल गांधी क्या रुख़ अपनाते हैं, यह तो अभी तक साफ़ नहीं हो पाया है, मगर इतना ज़रूर है कि इस मुद्दे पर सियासत ख़ूब होगी. संविधान के मुताबिक़, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता.

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हृदय नारायण दीक्षित ने मायावती की इस मांग को तुष्टिकरण क़रार देते हुए कहा है कि बसपा सरकार ने ही 2002 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा संशोधन अधिनियम पारित कराकर मुस्लिम समुदाय की 35 पिछड़ी जातियों को आरक्षण के अधिकार से वंचित कर दिया था, जबकि भाजपा सरकार ने 2000 में अधिनियम पारित कराकर पिछड़े वर्गों की तीन सूचियां जारी की थीं, जिसमें 14 फ़ीसदी आरक्षण मुस्लिम समुदाय की जातियों को दिया गया था. उनका कहना है कि बसपा अति पिछड़ों और अति पिछड़े मुसलमानों को वास्तविक आरक्षण देने की पक्षधर कभी नहीं रही. उसने अति पिछड़ी जातियों और पिछड़े मुसलमानों के हितों पर डाका डाला है. उन्होंने मांग की कि मायावती प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के बजाय अति पिछड़ों एवं अति पिछड़े मुसलमानों को वास्तविक आरक्षण दें.

इसी तरह समाजवादी पार्टी के महासचिव आज़म ख़ां ने मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने का दावा करने वाली मायावती की इस मांग को मुसलमानों के साथ छलावा क़रार दिया है. उनका कहना है कि जिस सच्चर समिति का हवाला देते हुए मायावती ने मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग की है, उसी समिति ने यह भी कहा है कि राज्य सरकारें भी आरक्षण दे सकती हैं और इसे देने का तरीक़ा भी बताया गया है. फिर क्यों मायावती गेंद केंद्र सरकार के पाले में डालकर मुसलमानों को बेवक़ूफ़ बना रही हैं, इसे आसानी से समझा जा सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि बसपा सरकार मुसलमानों को अशिक्षित और ग़रीब ही बनाए रखना चाहती है, तभी तो वह मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में दाख़िले की अनुमति नहीं दे रही है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि बसपा सरकार के क़रीब साढ़े चार सालों में मायावती को न तो मुसलमानों की याद आई और न ही सच्चर समिति की. उन्होंने दावा किया कि हाल में 33 हज़ार सिपाहियों की भर्ती में बसपा सरकार ने सिर्फ़ 650 मुस्लिम सिपाही भर्ती किए, जो कुल भर्ती का दो फ़ीसदी से भी कम है. हाल में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान ख़ुर्शीद ने ख़ुलासा किया है कि केंद्र सरकार पिछड़े वर्गों के 27 फ़ीसदी आरक्षण में पिछड़े वर्ग में आने वाले मुसलमानों का कोटा तय करने के लिए क़ानून बना रही है. यह कोटा कितना होगा, इसका ख़ुलासा उन्होंने नहीं किया है, लेकिन इस बात के संकेत दिए हैं कि यह कोटा आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक की तर्ज़ पर तय होगा. ग़ौरतलब है कि कांग्रेस सरकार ने आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण देने का प्रावधान किया है. अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है.

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस की चुनावी मुहिम की बागडोर राहुल गांधी के हाथ में है. जिस तरह राहुल गांधी ने भट्टा-पारसौल में सक्रियता दिखाते हुए किसान आंदोलन में शिरकत की, भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ पदयात्रा कर किसानों की समस्याएं सुनीं और उनसे किया वादा निभाते हुए लोकसभा में संशोधित भूमि अधिग्रहण विधेयक पेश करा दिया. यह विधेयक सिर्फ़ 55 दिनों में तैयार कर लिया गया था. इस सबको देखते हुए इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने की दिशा में कोई क़दम उठा सकती है. हालांकि यह बात दीगर है कि आज़ादी के बाद से अब तक कांग्रेस ने मुसलमानों की भलाई के लिए कुछ ख़ास नहीं किया है. हालांकि योजनाएं तो व़क़्त-दर-व़क़्त अनेक बनती रही हैं, लेकिन मुसलमानों को उनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ. प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम की ही हालत देख लीजिए. इसके तहत केंद्र सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं. इनमें एक मुसलमानों के बहुआयामी विकास कार्यक्रम नामक योजना है. इसकी मद में केंद्र सरकार की तरफ़ से मुसलमानों के विकास के लिए आर्थिक पैकेज की व्यवस्था की गई है. यह कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा चुने गए 90 ज़िलों में शुरू किया गया है. इसे लागू करने के लिए ज़रूरी है कि संबंधित ज़िले में कम से कम 15 फ़ीसदी मुस्लिम आबादी हो. इसके लिए ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के ज़िलों को चुना गया है. इनके लिए क़रीब 25 हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा की सहायता राशि का प्रावधान है, लेकिन अब तक सिर्फ़ 20 फ़ीसदी रक़म का ही इस्तेमाल हुआ है. यूपीए सरकार को इस बात की फ़िक्र है कि उसके कार्यक्रमों को सही तरीक़े से लागू नहीं किया जा रहा है, जिससे कांग्रेस को नुक़सान हो सकता है. पिछले दिनों एक बैठक में राहुल गांधी ने भी इस बात पर ज़ोर दिया था कि विभिन्न राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वित कराया जाए. दरअसल, मुसलमानों से संबंधित इस योजना के लिए केंद्र ने जिन ज़िलों को चुना है, उनमें से अनेक ज़िले ऐसे राज्यों में आते हैं, जहां ग़ैर कांग्रेसी सरकारें हैं. इन राज्यों की सरकारें नहीं चाहतीं कि यूपीए अल्पसंख्यकों, ख़ासकर मुसलमानों में लोकप्रिय हो. इस बात को लेकर राहुल गांधी अपने गुस्से का भी इज़हार कर चुके हैं. उनका कहना था कि राज्य में कांग्रेस की सरकार न होने की वजह से जनता को इन योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है.

मुसलमानों को आरक्षण देने के मुद्दे पर राहुल गांधी क्या रुख़ अपनाते हैं, यह तो अभी तक साफ़ नहीं हो पाया है, मगर इतना ज़रूर है कि इस मुद्दे पर सियासत ख़ूब होगी. संविधान के मुताबिक़, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता. आरक्षण का आधार केवल सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है. संविधान में तीन प्रकार के आरक्षण का प्रावधान है. केंद्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों के लिए 15 फ़ीसदी, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 फ़ीसदी और पिछड़े वर्गों के लिए 27 फ़ीसदी आरक्षण है. अनुसूचित जातियों के आरक्षण के दायरे में केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोग आते हैं, जबकि दलित मुसलमान और दलित ईसाई इससे बाहर हैं. कई राज्यों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण को आबादी के हिसाब से बांटा गया है. आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय की कई जातियों की एक अलग श्रेणी बनाकर 27 फ़ीसदी में से उनका कोटा तय कर दिया गया है. हालांकि इन राज्यों में यह बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि जातियों की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति के आधार पर है. बहरहाल, मायावती ने मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग उठाकर सवर्ण कार्ड खेलने की कोशिश ज़रूर की है.

firdaus@chauthiduniya.com

नीतीश को जगदानंद की सलाह

सरोज सिंह

नाटक का पात्र मत बनिए, अज्ञानता के लिए माफी मांगिए. राजद सांसद जगदानंद सिंह कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं तो दो टूक. पिछले चुनाव में जब उन्होंने कहा था कि बेटे का नहीं, पार्टी का साथ दूंगा तो सहसा लोगों को यक़ीन नहीं हुआ, लेकिन जब राजद प्रत्याशी ने उनके पुत्र को हरा दिया तो सूबे की जनता ने माना कि जगदा बाबू जो कहते हैं, वह करते हैं. इन दिनों फरक्का बैराज समझौते एवं तिस्ता जल बंटवारे को लेकर प्रदेश के मंत्रियों की बयानबाज़ी से जगदानंद सिंह दु:खी हैं. वह कहते हैं कि मंत्रियों एवं उनके मुखिया की अज्ञानता इस सूबे को ले डूबेगी. जगदानंद सिंह गंगा जल बंटवारे मामले में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहते हैं कि तीस्ता नदी के पानी के साथ बिहार का भी हित जुड़ा है. इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार को राज्य के हितों की जानकारी नहीं है. मालूम हो कि बिहार और बंगाल के साथ हुए पूर्व के करार के मुताबिक़ महानंदा बैराज को तीस्ता नदी का पानी मिलना है. इस बैराज से राज्य के कई सीमावर्ती इलाक़ों को पानी मिलेगा, लेकिन तब, जबकि बैराज को ख़ुद पानी मिलना शुरू हो जाएगा.

जगदानंद कहते हैं कि द्वितीय सिंचाई आयोग ने बक्सर में गंगा नदी में पानी की कमी का आकलन किया था. इसलिए बिहार के तत्कालीन सरकार की पूरी कोशिश इस बात की थी कि ऊपर के तटवर्ती राज्य बक्सर में तय सीमा तक पानी दें और बिहार को अपने हिस्से से अधिक अंशदान फरक्का के लिए न करना पड़े. फरक्का में गंगा जल बंटवारा संबंधी 1996 के समझौते का पूर्व और बाद में विरोध करके ही तत्कालीन सरकार ने अपने हितों की रक्षा की थी. वह कहते हैं कि मौजूदा जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी को यह मालूम होना चाहिए कि वर्ष 1996 के समझौते के बाद गंगा से पानी लेने का बिहार का हक़ समाप्त हो गया था, तो 2001-02 में तत्कालीन सरकार ने बाढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए गंगा से पानी कैसे दिया था? उन्होंने कहा कि कोसी नदी पर बनने वाले उच्चस्तरीय बांध का भारत-नेपाल समझौता ही बिहार की शर्त पर हुआ. चौधरी इस संचिका का अध्ययन करें. नेपाल की मांग कोसी से जल परिवहन की थी और भारत सरकार ब्रह्मपुत्र से परिवहन की बात पर अड़ी थी. कोसी नदी से जल परिवहन की मांग नेपाल से अधिक बिहार के लिए हितकारी थी. कोसी नदी से गंगा के माध्यम से समुद्र तक एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार का रास्ता होना उत्तर बिहार के लिए हितकर था. जलाशय निर्माण का रास्ता भी खुल गया, यह हमारे प्रयासों से ही संभव हुआ. ब्रह्मपुत्र के माध्यम से नेपाल को रास्ता देने के बदले कोसी की व्यवस्था बिहार की आर्थिक स्थिति को ऊंचाई पर ले जाने वाली साबित होगी. नेपाल को मात्र एक बंदरगाह मिलेगा, मगर बिहार को कुर्सेला-वीरपुर के बीच अनेक बंदरगाह मिलेंगे. क्या कभी किसी सरकार ने ऐसा सोचा भी था. उन्होंने सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा तथ्यों को झुठलाने का प्रयास किया जाता है. तीस्ता प्रकरण के माध्यम से ममता बनर्जी को नायक बनाने का प्रयत्न न किया जाए. गंगा से बिहार को पानी मिलता रहे, यह बात भी तत्कालीन सरकार के सिवा कभी किसी की समझ में आया हो तो इसका उदाहरण देना चाहिए. 1996 के समझौते को लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका मात्र प्रशंसक की थी. 1997 से लेकर 2004 तक केंद्र सरकार में मंत्री और 2005 से 2011 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे नीतीश अपनी भूमिका बिहारवासियों के समक्ष कैसे उचित ठहराएंगे? ममता ने आज कुछ किया है, लेकिन इससे अधिक तत्कालीन सरकार ने गंगा एवं गंगा बेसिन की सबसे बड़ी नदी कोसी के बारे में अपनी भूमिका का निर्वाह किया. चौधरी अगर तीस्ता और गंगा के फ़र्क़ को समझेंगे तो ममता और तत्कालीन सरकार के कार्यों तथा देश में केंद्र और राज्यों की संवैधानिक भूमिका को भी समझ पाएंगे.

दूसरी तरफ़ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि फरक्का समझौते का इतिहास बताकर राजद सांसद जगदानंद अपनी और तत्कालीन सरकार की कमियां छिपा रहे हैं. बात दिसंबर 1996 में भारत एवं बांग्लादेश के बीच हुए फरक्का समझौते से संबंधित है. सर्वविदित है कि उस समय बिहार और केंद्र में जनता दल की हुकूमत थी. मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा थे. पूर्व जल संसाधन मंत्री ने यह माना कि फरक्का समझौते में बिहार के हितों की अनदेखी की गई. यह सच है कि उस वक़्त बिहार के लिए गंगा नदी में जल की उपलब्धता का ख्याल नहीं रखा गया. मूल प्रश्न यह है कि जब बिहार के हितों के विरुद्ध यह समझौता हो रहा था तो उस समय राज्य एवं केंद्र में सत्ताधारी दल के नेता क्यों मुंह छिपाए बैठे थे, बिहार के हितों के साथ खिलवाड़ क्यों हुआ, राज्य एवं केंद्र सरकार की आख़िर क्या मजबूरी थी? जगदानंद सिंह कहते हैं कि गंगा नदी के पानी को लेकर बांग्लादेश से हुए समझौते के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री से जवाब तलब किया जाना चाहिए. जिस दिन सदन में इस मामले को लेकर बहस हो रही थी, वहां वर्तमान मुख्यमंत्री भी मौजूद थे. वह अन्य विषयों पर तो बोले, लेकिन इस विषय पर एक शब्द नहीं बोले. जगदानंद कहते हैं कि योजनाओं को कार्यान्वित करने वालों पर मुक़दमा नहीं किया जाना चाहिए और राज्य हित में काम करने वालों की आलोचना नहीं होनी चाहिए. दुर्गावती जलाशय नीतीश इसलिए शुरू नहीं कर पाए, क्योंकि जिन भ्रष्ट पदाधिकारियों को मैंने दंडित किया था, उनके सहयोग से वह मुझे जेल भेजना चाहते थे. जगदा बाबू ने मुख्यमंत्री से कहा कि आपका पद बड़ा है, दिल और दिमाग़ को भी बड़ा कीजिए. नाटक का पात्र मत बनिए, क्योंकि तात्कालिक आभा स्थायी नहीं होती.

जगदानंद कहते हैं कि द्वितीय सिंचाई आयोग ने बक्सर में गंगा नदी में पानी की कमी का आकलन किया था. इसलिए बिहार के तत्कालीन सरकार की पूरी कोशिश इस बात की थी कि ऊपर के तटवर्ती राज्य बक्सर में तय सीमा तक पानी दें और बिहार को अपने हिस्से से अधिक अंशदान फरक्का के लिए न करना पड़े.

feedback@chauthiduniya.com

नब्बे के दशक में तेलुगूदेशम पार्टी का हिस्सा रहे तेलंगाना समर्थक के चंद्रशेखर राव 1999 के चुनाव के बाद मंत्री पद चाहते थे, लेकिन उन्हें डिप्टी स्पीकर बनाया गया.

तेलंगाना को राज्य का दर्जा मिले

आंध्र प्रदेश के अहम हिस्से तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर पिछले चार दशकों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है. इस मुद्दे पर जहां केंद्र की यूपीए सरकार पर तेलंगाना इलाक़े के अपने नेताओं का दबाव है, वहीं अन्य सियासी दलों के नेता भी सरकार पर जल्द फ़ैसला लेकर आंदोलन ख़त्म करने के लिए दबाव बना रहे हैं. कांग्रेस के लिए एक दिक्क़त यह है कि प्रदेश में उसकी सरकार है और रायलसीमा के नेता अलग राज्य की मांग का विरोध कर रहे हैं. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव प्रकाश करात ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर तेलंगाना मुद्दे पर जल्द फ़ैसला लेने की अपील की है. उनका कहना है कि टालमटोल से स्थिति सिर्फ़ बिगड़ेगी. आंध्र प्रदेश में सभी सियासी दलों और समाज के विभिन्न वर्गों ने श्रीकृष्ण समिति को अपनी राय दी थी. इसलिए इस मुद्दे पर आगे सियासी दलों के साथ परामर्श करने की ज़रूरत नहीं है. तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने कार्यकर्ताओं सहित गांधी जयंती पर राजघाट पर धरना दिया. इस संबंध में बातचीत की सरकारी पेशकश को भी उन्होंने सिरे से ख़ारिज कर दिया.

ग़ौरतलब है कि तेलंगाना का अर्थ है तेलुगुओं की भूमि. तेलंगाना मूल रूप से हैदराबाद के निज़ाम की रियासत का हिस्सा था. 1948 में भारत ने निज़ाम की रियासत ख़त्म करके हैदराबाद राज्य की नींव रखी. आंध्र प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य था, जिसका गठन भाषाई आधार पर किया गया था. उस वक़्त कामरेड वासुपुन्नया ने अलग तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर मुहिम शुरू कर दी. कामरेड वासुपुन्नया का सपना भूमिहीन किसानों को ज़मींदार बनाना था, मगर कुछ साल बाद इस आंदोलन की कमान नक्सलियों के हाथों में आ गई. इसी बीच 1956 में तेलंगाना के एक बड़े हिस्से को आंध्र प्रदेश में शामिल कर लिया गया, जबकि कुछ हिस्से कर्नाटक और महाराष्ट्र में मिला दिए गए.

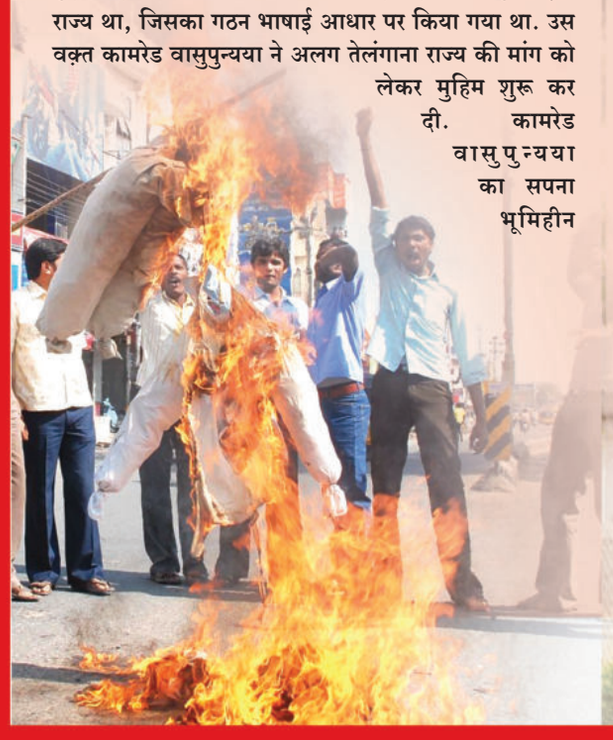

इसके कुछ साल बाद 1969 में तेलंगाना आंदोलन फिर शुरू हुआ. इस बार इसका मक़सद इलाक़े का विकास था और इसमें बड़ी तादाद में छात्रों को शामिल किया गया था. उस्मानिया विश्वविद्यालय इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र हुआ करता था. इस आंदोलन को पुलिस फ़ायरिंग और लाठीचार्ज में मारे गए सैकड़ों छात्रों की क़ुर्बानी ने ऐतिहासिक बना दिया. हालांकि इस आंदोलन को लेकर सियासी दलों ने ख़ूब रोटियां सेंकीं. तेलंगाना प्रजा राज्यम पार्टी के नेता एम चेन्ना रेड्डी ने जय तेलंगाना का नारा देकर सबका ध्यान अपनी तरफ़ खींचा, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करके उसके सुर में सुर मिला लिया. इससे ख़ुश होकर इंदिरा गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, मगर एम चेन्ना रेड्डी के पार्टी समेत कांग्रेस में शामिल होने से तेलंगाना आंदोलन को बहुत नुक़सान हुआ. कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक रणनीति के तहत 1971 में तेलंगाना क्षेत्र के नरसिंह राव को भी आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर तेलंगाना आंदोलन को मज़बूत नहीं होने दिया.

नब्बे के दशक में तेलुगूदेशम पार्टी का हिस्सा रहे तेलंगाना समर्थक के चंद्रशेखर राव 1999 के चुनाव के बाद मंत्री पद चाहते थे, लेकिन उन्हें डिप्टी स्पीकर बनाया गया. अपनी अनदेखी से आहत चंद्रशेखर राव ने 2001 में अलग तेलंगाना राज्य की मांग करते हुए तेलुगूदेशम पार्टी को अलविदा कह दिया. उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर तेलंगाना राष्ट्र समिति का गठन किया. इसके बाद 2004 में वाई एस राजशेखर रेड्डी ने अलग तेलंगाना राज्य के गठन को समर्थन देते हुए चंद्रशेखर राव से गठबंधन कर लिया, मगर इस बार भी वही हुआ, जो अब तक होता आ रहा था. वाई एस राजशेखर रेड्डी ने भी अलग तेलंगाना राज्य के गठन को तरजीह नहीं दी. इससे नाराज़ होकर तेलंगाना राष्ट्र समिति के विधायकों ने इस्तीफ़ा दे दिया. इस पर चंद्रशेखर राव ने भी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दे दिया और अपना आंदोलन जारी रखा. ग़ौरतलब है कि 1,14,800 वर्ग किलोमीटर में फैले तेलंगाना में आंध्र प्रदेश के 23 ज़िलों में से 10 ज़िले यानी ग्रेटर हैदराबाद, रंगा रेड्डी, मेडक, नालगोंडा, महबूबनगर, वारंगल, करीमनगर, निज़ामाबाद, अदीलाबाद और खम्मम आते हैं. आंध्र प्रदेश की 294 में से 119 विधानसभा सीटें और 17 लोकसभा सीटें भी इस क्षेत्र में आती हैं. क़रीब 3.5 करोड़ आबादी वाले तेलंगाना की भाषा तेलुगु और दक्कनी उर्दू है. तेलंगाना के अलग राज्य बनने की स्थिति में इसके बीचोबीच स्थित ग्रेटर हैदराबाद को राजधानी बनाए जाने की उम्मीद है.

ग़ौरतलब है कि 2009 में सोनिया गांधी के जन्मदिन यानी 9 दिसंबर को तेलंगाना के कांग्रेसी सांसदों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के साथ ही तेलंगाना को अलग राज्य बनाने की मांग कर डाली, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया. इस पर तेलंगाना के कांग्रेसियों ने मिठाइयां बांटकर ख़ुशियां मनाईं. लगा कि यह आंदोलन अब ख़त्म हो गया है. शायद उस वक़्त सोनिया गांधी ने इसे गंभीरता से न लिया हो, मगर अब यह मुद्दा पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन गया है. शायद सोनिया गांधी ने इसे भी उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ की तरह आसान मसला समझा, लेकिन वह यह भूल गईं कि आंध्र और रायलसीमा के प्रभावशाली रेड्डी इतनी आसानी से प्रदेश का बंटवारा नहीं होने देंगे. ख़ास बात यह है कि यहां से मिलने वाले राजस्व, भू-माफ़ियाओं पर रेड्डियों के वर्चस्व और तमाम सुविधाओं के मद्देनज़र कोई भी इसे छोड़ना नहीं चाहता. चंडीगढ़ की तर्ज़ पर हैदराबाद को दोनों राज्यों की राजधानी बनाए जाने की मांग को भी सिरे से ख़ारिज किया जा चुका है. जब कांग्रेस को मुद्दे की गंभीरता का एहसास हुआ तो उसने इसे लटकाए रखने में ही अपनी भलाई समझी.

आंध्र प्रदेश में अलग तेलंगाना राज्य की मांग पर विचार के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल जस्टिस श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था. समिति ने बीते साल दिसंबर में ही अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी थी. केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट का वह भाग तो सार्वजनिक कर दिया था, जिसमें समिति ने सरकार के सामने छह उपाय रखे थे और उनके संभावित प्रभाव के बारे में अपनी राय भी दे दी थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट के एक हिस्से को यह कहकर गुप्त रखा था कि इसमें क़ानून व्यवस्था के बारे में संवेदनशील जानकारी है, जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता. रिपोर्ट में सिफ़ारिश की गई थी कि सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आंध्र प्रदेश को एक रखा जाए और दूसरा सबसे अच्छा रास्ता यह होगा कि तेलंगाना को अलग राज्य बनाया जाए. मगर जो गुप्त रिपोर्ट सामने आई है, उसमें समिति ने तेलंगाना राज्य के ख़िलाफ़ कड़ा रुख़ अपनाया है. रिपोर्ट में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को उस्मानिया, काकिया एवं अन्य विश्वविद्यालयों में तेलंगाना आंदोलन को कुचलने के लिए ताक़त का इस्तेमाल किए जाने की सलाह दी गई. तेलंगाना के पूर्व सांसद नारायण रेड्डी ने गुप्त रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दाख़िल कर दी. उस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि वह रिपोर्ट सार्वजनिक करे, क्योंकि उसमें गुप्त रखने लायक़ कुछ नहीं है. साथ ही उन्होंने अपने फ़ैसले में ही रिपोर्ट के कुछ उन हिस्सों को प्रकाशित कर दिया, जो केंद्र सरकार के वकील ने अदालत को दिए थे. इनके सार्वजनिक होने पर ही प्रदेश में हंगामा हुआ. बताया जाता है कि इस रिपोर्ट पर 20 करोड़ रुपये ख़र्च किए गए. सत्तारूढ़ कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति, भारतीय जनता पार्टी और तेलुगूदेशम सहित सभी सियासी दलों के तेलंगाना क्षेत्र के नेताओं ने रिपोर्ट की आलोचना करते हुए समिति पर पूंजीपतियों के हाथों बिक जाने के आरोप तक लगाए.

तेलंगाना की मांग को लेकर समर्थक अपनी जान देने पर तुले हुए हैं. हाल में कोहेडा गांव में 18 वर्षीय छात्रा भवानी ने आत्मदाह कर लिया. पिछले साल फरवरी में हैदराबाद के नोबेल कॉलेज के छात्र एस यदैया ने ख़ुद को आग लगा ली थी, जिससे उसकी मौत हो गई. इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं. इसके कारण जहां जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं सरकारी सेवाओं पर भी ख़ासा असर पड़ रहा है. इसके अलावा सरकार को अरबों रुपये का नुक़सान भी हो रहा है. स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो चुकी है कि कांग्रेस और सोनिया गांधी के लिए इस मसले को हल करना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है. हालांकि इसे सुलझाने की ज़िम्मेदारी सरकार के संकट मोचक कहे जाने वाले प्रणब मुखर्जी को सौंपी गई है. फ़िलहाल इस मुद्दे का समाधान होता नज़र नहीं आ रहा है.

फ़िरदौस खान
firdaus@chauthiduniya.com

लेफ्टिनेंट की क़ुर्बानी बेकार गई

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

बीते 20 अगस्त को गुरेज सेक्टर में भारतीय सेना का एक युवा लेफ्टिनेंट आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गया. शहीद लेफ्टिनेंट 15 मराठा एलआई बटालियन से जुड़ा था. इस युवा सेना अधिकारी की शहादत ने देश के समक्ष हमारे सैनिकों के गौरवशाली इतिहास को एक बार फिर ताज़ा कर दिया है. गुरेज सेक्टर में शहीद हुए इस लेफ्टिनेंट ने अकेले ही 12 दहशतगर्दों को मार गिराया और अंत में ख़ुद भी शहीद हो गया. सेना को उसकी शहादत पर गर्व है, लेकिन दिल्ली के सियासी गलियारे में उसकी शहादत की कोई चर्चा नहीं सुनी गई. यहां यह सवाल उठता है कि 12 आतंकियों को ढेर करने वाले इस जवान को मरणोपरांत वीरता पदक क्यों न दिया जाए.

ग़ौरतलब है कि देश की सीमाओं की हिफ़ाजत करते हुए हर साल हज़ारों जवान शहीद होते हैं. उनकी कुर्बानी पर देश की आम जनता को भले ही गर्व हो, लेकिन हमारे मीडिया और नेताओं के पास शोक जताने का भी समय नहीं है. दरअसल इसके पीछे इन लोगों की संवेदनहीनता है, जो उन्हें आंख रहते भी अंधा बनाए हुए है. आजकल न्यूज चैनलों पर ग़ैर स्तरीय ख़बरें और कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, लेकिन कश्मीर घाटी में सेना के जवान किन विपरीत परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, यह देखने के लिए उनके पास वक्त नहीं है. अगर घाटी में कोई अलगाववादी नेता सरेआम भारत विरोधी बातें कहे तो यही मीडिया उसके लिए अपने दफ्तर में मंच प्रदान करता है. सैयद अली शाह गिलानी और जेकेएलएफ चीफ यासिन मलिक राजधानी दिल्ली में खुल्लमखुल्ला भारत के ख़िलाफ़ बयान देते हैं, लेकिन हमारी तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां और मीडिया इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी क़रार देते हैं. क्या मानवाधिकारों के सारे नियम आतंकवादियों पर ही लागू होते हैं. क्या देश की सीमाओं पर तैनात हज़ारों जवानों के लिए कोई मानवाधिकार नहीं है.

विश्व में संभवत: भारत ही ऐसा देश है, जहां सरकार से वार्ता का निमंत्रण मिलने का आशय राष्ट्र विरोधी होने से है. पिछले दिनों एक अंग्रेजी अख़बार ने जम्मू-कश्मीर में सेना द्वारा आम कश्मीरियों से ज़्यादती और उन पर अत्याचार संबंधी लेख प्रकाशित किए. यहां पिछले दो वर्षों के दौरान सेना के ख़िलाफ़ मानवाधिकार उल्लंघन के 1600 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं. हालांकि जांच के बाद यह पाया गया कि उनमें से सिर्फ़ 2 प्रतिशत मामले ही सही थे. बाकी 98 फ़ीसदी मामले ग़लत आधार पर दर्ज किए गए थे. इस तरह घाटी में हर साल मानवाधिकार उल्लंघन के 2-3 मामले ही सत्य होते हैं. भारत में तथाकथित अत्याचार के मामलों के संदर्भ में एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स (एसीएचआर) की हालिया रिपोर्ट कहती है कि आठ वर्षों में (अप्रैल 2001 से मार्च 2009 तक) भारत में 1184 लोग पुलिस हिरासत में मारे गए.

महाराष्ट्र में सबसे अधिक 192 मामले दर्ज किए गए. दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, जहां 128 लोग विभिन्न स्थानों पर पुलिस लॉकअप में मारे गए. गुजरात में 113, आंध्र प्रदेश में 85, पश्चिम बंगाल में 83, तमिलनाडु में 76, असम में 74, कर्नाटक में 55, पंजाब में 41, मध्य प्रदेश में 38, बिहार एवं राजस्थान में 32-32, हरियाणा में 31, केरल में 30, झारखंड में 29, दिल्ली में 25, उड़ीसा में 24, छत्तीसगढ़ में 23, उत्तराखंड एवं मेघालय में 16-16 और अरुणाचल प्रदेश में 11 मामले दर्ज किए गए. वैसे ये आंकड़े बड़े राज्यों के हैं, जबकि जम्मू-कश्मीर और त्रिपुरा में पुलिस हिरासत के मात्र नौ-नौ मामले दर्ज किए गए. ऐसे में यह सवाल लाज़िमी है कि मानवाधिकार उल्लंघन के लिए कौन सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है, महाराष्ट्र या जम्मू-कश्मीर किसे ज़्यादा दोषी माना जाना चाहिए? क्या इस बारे में कभी किसी ने सोचा है कि बार-बार मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाने और राष्ट्र विरोधी प्रचार से हमारे सैनिकों के मनोबल और विश्वास को कितनी ठेस पहुंचती है. यह तक़लीफदेह है कि अपनी सजग और धर्मनिरपेक्ष छवि दिखाने वाला मीडिया किस तरह अलगाववादियों के प्रति प्रेम जताता है.

सुरक्षाकर्मी, मीडिया और समाज

जम्मू-कश्मीर को लेकर देशवासियों में यह आम धारणा है कि वहां सेना अपना शासन चला रही है. इसलिए घाटी में होने वाली हर घटना और ग़लत गतिविधियों को लेकर सैनिकों को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है. जबकि यह सरासर ग़लत है. न्यूज चैनलों और अख़बारों के संपादकीय पृष्ठ में ऐसी बेबुनियाद बातों को ज़ोर-शोर से प्रचारित किया जाता है. मीडिया सिर्फ़ एक पहलू को ही देखता है. क्या उसने कभी इस बात की कोशिश की है कि सेना के जवान किस तरह मुश्किल भरे हालात में चौबीसों घंटे सरहद की हिफ़ाजत करते हैं. देश का तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मीडिया इस हक़ीक़त को सामने क्यों नहीं लाता, किसी आतंकी कार्रवाई में जब सेना का कोई जवान शहीद हो जाता है तो उसके रोते-बिलखते परिवारीजनों की सुध मीडिया क्यों नहीं लेता?

हर साल अपना फ़र्ज़ निभाते हुए चार-साढ़े चार हज़ार सैनिक शहीद हो जाते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे नेताओं को सेना के जवानों से कोई हमदर्दी नहीं है. जब भी सेना की जायज़ मांगों पर बात होती है तो वे उसे सिरे से ख़ारिज़ कर देते हैं. जबकि संसद में शोरगुल करके जनता के लाखों रुपये बर्बाद करने वाले ये नेता एक झटके में अपना वेतन-भत्ता कई गुना बढ़ा लेते हैं. ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब नेता और मीडिया इस तरह सेना के जवानों का मनोबल गिराएंगे तो देश की सुरक्षा कौन करेगा.

feedback@chauthiduniya.com

सरकार ने एक और बात पर ध्यान नहीं दिया. उसने वरिष्ठ नागरिकों की एक ही कैटेगरी बनाई है. सरकार जब कोई नीति बनाती है तो उसमें सभी वरिष्ठ नागरिकों को एक नज़र से देखती है, जो कि सही नही है.

हाशिए पर वरिष्ठ नागरिक

डी आर आहूजा

भारत में उम्रदराज लोगों की संख्या बढ़ रही है. यहां लोगों की औसत आयु में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. पुरुषों की औसत आयु 1951–60 के बीच 42 वर्ष थी, जो 1986–90 में बढ़कर 58 साल हो गई और अनुमान है कि 2011–16 में यह 67 साल हो जाएगी. इस वृद्धि से यह तय है कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या में भी वृद्धि होगी. एक अनुमान के अनुसार, भारत में 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों की संख्या 2013 तक 100 मिलियन हो जाएगी. संयुक्त राष्ट्र संघ के एक आकलन के अनुसार, भारत में 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों की संख्या 2030 तक 198 मिलियन और 2050 तक 326 मिलियन हो जाएगी. बुजुर्गों की बढ़ती संख्या के बावजूद सरकार का ध्यान उनकी ओर नहीं है. अगर सालाना बजट पर नज़र डाली जाए तो इसका अनुमान सहज ही लग जाएगा कि सरकार किस तरह इनकी उपेक्षा कर रही है. सरकार द्वारा बरती जा रही उपेक्षा की एक बड़ी वजह इनका संगठित न होना भी है. चुनाव के समय ये संगठित होकर मतदान नहीं करते, इस कारण सरकार पर इनका वैसा कोई दबाव नहीं होता, जैसा अन्य संगठनों यथा किसानों, मज़दूरों, सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों एवं व्यापारियों का होता है.

एक वरिष्ठ नागरिक का कहना है कि संगठित होकर मतदान न करने की वजह से ही उनके लिए बजट में धनराशि काफ़ी कम होती है. जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके इन लोगों को समुचित देखभाल की आवश्यकता है. सरकार को चाहिए कि इनके लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, सुविधायुक्त वृद्धाश्रम के साथ–साथ इन्हें भौतिक, भावनात्मक और आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराए. आर्थिक सुरक्षा तो सबसे बड़ी ज़रूरत है. इसके लिए सरकार इन्हें आयकर में ज़्यादा छूट दे सकती है, साथ ही कुछ अन्य करों को कम कर सकती है या माफ़ कर सकती है. अधिकांश वरिष्ठ नागरिक अपने द्वारा बचाए गए धन पर निर्भर हैं या फिर उन्होंने जो मकान बनाया है, उसके एक भाग को किराए पर देकर उससे मिलने वाली रकम पर निर्भर हैं. वरिष्ठ नागरिकों में कम ही ऐसे हैं, जो सफलतापूर्वक अपना व्यापार चला रहे हैं. हालांकि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं जैसे पेंशन, स्वास्थ्य सेवा के लिए सीजीएचएस और आवास आदि, लेकिन ये पर्याप्त नहीं हैं. ज़्यादातर लोग तो निजी कंपनियों में काम करते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद उनके लिए कंपनियां कोई व्यवस्था नहीं करती हैं. सरकार को चाहिए कि निजी कंपनियों के लिए भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुविधाएं देना अनिवार्य करे, ताकि ग़ैर सरकारी उपक्रमों से जुड़े लोगों का भविष्य भी सुरक्षित हो सके.

सरकार ने एक और बात पर ध्यान नहीं दिया. उसने वरिष्ठ नागरिकों की एक ही कैटेगरी बनाई है. सरकार जब कोई नीति बनाती है तो उसमें सभी वरिष्ठ नागरिकों को एक नज़र से देखती है, जो कि सही नही है. जो लोग 80 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, उनकी समस्या उनसे अलग है, जो अभी 60 से 80 वर्ष के बीच हैं. सरकार उनके लिए अलग से कोई योजना नहीं बनाती. उनके लिए विशेष अस्पताल भी नहीं हैं, जिनमें अल्जाइमर, हृदय रोग या दृष्टि संबंधी रोगों का इलाज हो सके. इस उम्र के ज़्यादातर लोग चलने–फिरने से लाचार हैं, बिस्तर पकड़े हुए हैं और कई तरह की शारीरिक परेशानियों के शिकार हैं. इन्हें अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है. ये बिना छड़ी के चल नहीं सकते और अक्सर दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं. इन्हें सामाजिक और पारिवारिक उपेक्षा भी झेलनी पड़ती है. समाज से कटे होने के कारण इनमें से अधिकांश लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं. समाज में जिन लोगों को सबसे अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, उन्हें हाशिए पर रखा जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय वियना प्लान ऑफ एक्शन 1982 में भी 80 साल से ऊपर के लोगों की समस्याओं को देखते हुए उनके लिए विशेष योजना बनाने की ओर ध्यान देने की बात कही गई है, लेकिन इस पर भारत सरकार भी ग़ौर नहीं कर रही है. समाज का यह हिस्सा आर्थिक रूप से दूसरों पर अधिक निर्भर है, सामाजिक रूप से उपेक्षित है और ये अकेलापन महसूस करते हैं. इन्हें विशेष तरह के भोजन की आवश्यकता होती है, जिसमें कम कैलोरी, तेल या मसाला हो, लेकिन घर के लोग इस पर ध्यान नहीं देते और शारीरिक आवश्यकता के अनुकूल भोजन इन्हें नहीं मिल पाता है. अंतरराष्ट्रीय प्लान ऑफ एक्शन 2002 में भी इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि जो लोग वृद्धों में भी वृद्ध हैं, उनके लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है. उनकी परेशानियां 60 से 79 वर्ष के लोगों से अलग होती हैं और इस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए.

एक सेवानिवृत्त अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के बारे में कहते हैं कि बुढ़ापा अपने आप में एक समस्या है. एक बुजुर्ग व्यक्ति को अकेले या बहुत हुआ तो अपनी पत्नी के साथ, जो ख़ुद भी बुजुर्ग होती है, रहना होता है. उनके बच्चे साथ नहीं रहते, क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी के कारण दूसरी जगह रहना पड़ता है. उनके साथ कोई नहीं होता, जिसके कारण समय काटना मुश्किल हो जाता है. यह समस्या उन लोगों के साथ और अधिक है जो सरकारी या ग़ैर सरकारी स्तर पर किसी बड़े ओहदे पर काम कर चुके हैं और जिनके पास नौकरी के समय अधिकार रहे हैं. ये लोग उस तरह के वातावरण के आदी हो जाते हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद इन्हें उस प्रकार का माहौल नहीं मिल पाता. इनके कार्यालय का माहौल अलग होता है, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद इन्हें बिल्कुल अलग तरह के माहौल का सामना करना पड़ता है. नौकरी के समय इनके इर्द–गिर्द सेवकों एवं जी हुजूरी करने वाले लोगों का तांता लगा रहता है, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद इनके आसपास उस तरह के लोग नहीं होते. यहां तक कि किसी प्रकार के उत्सव आदि में भी इन्हें नहीं बुलाया जाता है. इसके कारण इनकी परेशानी काफी बड़ी हो जाती है.

अधिकारों का भरपूर उपयोग कर चुके ये लोग एकाएक अपने को अधिकारविहीन पाते हैं, इन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता. बड़े पदों पर रहने वाले ये लोग जब काम करते रहते हैं तो उस दौरान इनके पास वक़्त ही नहीं होता कि ये घर के बच्चों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत कर सकें. समयाभाव अथवा कुछ अन्य मजबूरियों के कारण ये लोग अपने आसपास के लोगों के साथ भी बहुत नज़दीकी संबंध नहीं बना पाते हैं.

अधिकारों का भरपूर उपयोग कर चुके ये लोग एकाएक अपने को अधिकारविहीन पाते हैं, इन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता. बड़े पदों पर रहने वाले ये लोग जब काम करते रहते हैं तो उस दौरान इनके पास वक़्त ही नहीं होता कि ये घर के बच्चों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत कर सकें. समयाभाव अथवा कुछ अन्य मजबूरियों के कारण ये लोग अपने आसपास के लोगों के साथ भी बहुत नजदीकी संबंध नहीं बना पाते हैं. इसलिए जब सेवानिवृत्ति के बाद ये लोग घर आते हैं तो न घर में इनके अनुकूल माहौल बन पाता है और न आस–पड़ोस के लोगों के साथ इनका तालमेल बैठ पाता है. ऐसी स्थिति में इनके साथ सबसे बड़ी समस्या यह हो जाती है कि इन्हें इस बात का भी पता नहीं होता कि ये किस पर विश्वास करें और किस पर अविश्वास. इन्हें बेहद अकेलापन महसूस होने लगता है. एक तरफ शारीरिक परेशानियां और दूसरी तरफ मानसिक परेशानियां, दोनों तरह की समस्याएं इन्हें एक साथ झेलनी पड़ती हैं. इसके साथ ही इन्हें अपने ख़र्चों में भी कटौती करनी पड़ती है, क्योंकि इनकी आमदनी इस समय तक कम हो जाती है. ऐसी अवस्था में देखा जाए तो बुजुर्गों को एक साथ कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि सरकार इनकी समस्याओं को समझे और इन्हें विशेष सुविधाएं मुहैय्या कराए, ताकि देश, समाज और परिवार की सेवा करने वाले इन लोगों की बाकी ज़िंदगी सुकून से कट सके. सरकार के अलावा समाज में भी इनके लिए जागरूकता लाने की आवश्यकता है, ताकि इस उपेक्षित वर्ग की परेशानियों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके. सबको अच्छी तरह पता है कि इस दौर से उन्हें भी गुज़रना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उनका ध्यान इनकी समस्याओं की तरफ नहीं जा रहा है, जो कि चिंता की बात है. समाज और सरकार यानी दोनों के संयुक्त प्रयासों से ही बुजुर्गों की परेशानियों का निदान किया जा सकता है.

feedback@chauthiduniya.com

मोरारका फाउंडेशन से जुड़ी एक महिला ने जब मुसलमानों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ने की कोशिश की तो उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा,

शेखावाटी

मुसलमानों को दिखी उम्मीद की एक नई किरण

भारत के अधिकतर मुसलमान इसी बात का रोना रोते रहते हैं कि उनके साथ सरकार और प्रशासन का रवैय्या भेदभाव वाला होता है, उनकी तरक्की के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं. हो सकता है कि देश के कुछ हिस्सों के मुसलमानों की यह शिकायत सही हो, लेकिन भारत के बहुत से हिस्से ऐसे हैं, जहां तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखने को मिल रहा है. हमने पिछले दिनों राजस्थान की शेखावाटी तहसील के नवलगढ़ क़स्बे के कुछ मुसलमानों के घरों का दौरा किया. राजस्थान में शेखावाटी एक ऐसी जगह है, जहां मोरारका फाउंडेशन के प्रयासों से न सिर्फ़ बहुसंख्यक, बल्कि अल्पसंख्यकों के दिलों में भी उम्मीद की एक किरण जगी है. अब उन्हें भी नए सपने देखने का हौसला मिला है. आख़िर कैसे बदल रही है तस्वीर, पढ़िए इस रिपोर्ट में.

डॉ. क़मर तबरेज़

राजस्थान के झुंझनू ज़िले की शेखावाटी तहसील में एक छोटा सा क़स्बा है नवलगढ़. यहां के बनारसी रोड पर वार्ड नंबर 24 में मुसलमानों के 40–50 घर आबाद हैं. नवलगढ़ को यहां की पुरानी हवेलियों की वजह से याद किया जाता है, जिन्हें देखने के लिए देश–विदेश से पर्यटक यहां आते हैं, लेकिन इन हवेलियों के अंदर की ज़िंदगी यहां के स्थानीय निवासियों की आम ज़िंदगी से बिल्कुल अलग है. यहां के अधिकतर लोगों का जीवनयापन खेती–बाड़ी पर निर्भर है. इसके अलावा यहां के लोग कपड़ों पर कढ़ाई, बुनाई और चूड़ियां आदि बनाने का भी काम करते हैं. कपड़ों पर बंधेज का काम और यहां की लाख की बनी चूड़ियां देश–विदेश में काफी मशहूर हैं. बंधेज दरअसल कपड़ों पर धागों के ज़रिए बंधाई का काम है, ताकि जब इन कपड़ों को किसी विशेष रंग से रंगा जाए तो इन धागों पर कोई रंग न चढ़े.

हमने नवलगढ़ के वार्ड नंबर 24 में लगभग 25–30 घरों की मुस्लिम महिलाओं से बातचीत की और उनसे जानना चाहा कि उनके जीवनयापन का स्रोत क्या है और उन्हें किन–किन समस्याओं से जूझना पड़ता है. इन सारी महिलाओं ने एक आवाज़ में कहा कि उनकी सबसे बड़ी समस्या माली तंगी है. अधिकतर मर्द मेहनत– मज़दूरी करते हैं, ख़ासकर मकान आदि बनाने में गारा, मिट्टी और ईंट ढोने का काम करते हैं. इसके लिए वे मुंबई और कोलकाता जैसे दूरदराज के शहरों तक सफर करते हैं. महिलाएं आम तौर पर घरों में बंधेज, पेपर बैग या फिर चूड़ियां बनाने का काम करती हैं. यही उनकी रोज़ी–रोटी का एकमात्र साधन है. देश के बाकी मुसलमानों की तरह यहां के मुसलमानों के बीच भी शिक्षा और जागरूकता का अभाव है. स्थानीय निवासी अब्दुल रज़्ज़ाक़ के दो बेटे हैं, शकील और जावेद. शकील पांचवीं पास है, जबकि जावेद सिर्फ़ दूसरी कक्षा तक ही पढ़ सका है. ये दोनों अब मज़दूरी करके अपना और अपने घर का पेट पालते हैं. बड़े परिवार के मामले में यहां का मुसलमान भी वही सब सोचता है, जो सोच देश के अधिकतर हिस्सों में रहने वाले मुसलमानों की है.

ज़ाहिर है, यह सोच हर एक आम भारतीय मुसलमान की है और यही सोच उनकी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट भी है. लेकिन, इन तमाम परेशानियों और समस्याओं के बीच भी नवलगढ़ के मुसलमान अब तरक्की के नए रास्ते पर निकल पड़े हैं और उनके लिए यह रास्ता बनाया है मोरारका रूरल रिसर्च फाउंडेशन ने. फाउंडेशन की तरफ़ से यहां के किसानों के साथ–साथ जनसाधारण के लिए भी कई प्रकार के विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे पेपर बैग बनाने की ट्रेनिंग, सोलर लालटेन प्रोजेक्ट, कम्युनिटी किचन, 21वीं शताब्दी में टेक्निकल एजुकेशन के लिए आकांक्षा प्रोजेक्ट और महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह. इन सारी योजनाओं की खास बात यह है कि ये समाज के उपेक्षित तबकों के उत्थान के लिए बनाई गई हैं और इन्हीं योजनाओं/कार्यक्रमों से जुड़कर नवलगढ़ का मुसलमान भी विकास के रास्ते पर चल पड़ा है. इन कार्यक्रमों पर अगर ग़ौर किया जाए तो यहां की मुस्लिम महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह सबसे फ़ायदेमंद साबित हो सकता है. मोरारका फाउंडेशन ने कुछ साल पहले गांव पंचायत स्तर पर महिलाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया था, जिसके तहत उन्हें सरकार की तरफ़ से चलाई जा रही कुछ योजनाओं की जानकारी देने का काम शुरू किया गया. सरकारी योजनाओं में आपसी तालमेल न होने के कारण उनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन मुश्किल हो रहा था. इसी बात को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के छोटे–छोटे समूह बनाए गए. महिलाओं का यह समूह एक छोटे बैंक की तरह काम करता है, जहां ये महिलाएं अपनी घरेलू बचत की राशि एक जगह जमा करती हैं. फिर कुल जमा धनराशि में से किसी ज़रूरतमंद महिला को क़र्ज़ दे दिया जाता है. इस प्रकार इस समूह की कोई भी महिला अब किसी की मोहताज नहीं है, बल्कि वह अपनी ज़रूरतों को अपने समूह द्वारा जमा की गई धनराशि से पूरा कर लेती है.

मोरारका फाउंडेशन से जुड़ी एक महिला ने जब मुस्लिम महिलाओं को भी इस कार्यक्रम से जोड़ने की कोशिश की तो शुरुआत में उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुस्लिम मोहल्लों के मर्द शुरू में उस महिला को अपने घरों में घुसने ही नहीं देते थे, लेकिन धीरे–धीरे इस महिला पर उनका विश्वास मज़बूत हुआ तो वे स्वयं सहायता समूह से ख़ुद को जोड़ने लगीं. अब उन्हें इस बात की काफी ख़ुशी है कि वे अपनी ज़रूरतें इसी समूह से क़र्ज़ लेकर पूरा कर लेती हैं, साथ ही उन्हें पेपर बैग, बंधेज और इस तरह के दूसरे छोटे–मोटे काम घर पर करने को मिल जाते हैं, जिससे उनकी कुछ आमदनी हो जाती है.

अपने इसी सफ़र के दौरान हमें शेखावाटी के चेलासी गांव जाने का भी मौक़ा मिला. इस गांव में मुसलमानों के 30–35 घर हैं. हमारी मुलाक़ात यहां के 65 वर्षीय भनवर ख़ान से हुई. उन्होंने बताया कि यहां पर मुसलमान 1947 के पहले से रहते चले आए हैं. इस बीच न तो उन्होंने कोई सांप्रदायिक दंगा–फसाद देखा और न यहां की सरकार और प्रशासन से उन्हें कोई शिकायत है. भनवर ख़ान पहले फौज में थे, अब रिटायर होने के बाद खेती–बाड़ी करते हैं. चेलासी गांव के मुसलमान नवलगढ़ के मुसलमानों की अपेक्षा ज़्यादा ख़ुशहाल है. यहां के बहुत से मुसलमान सरकारी नौकरियां करते हैं और फौज में भी हैं. बहुत से ऐसे मुसलमान भी हैं, जो इराक़ और कुवैत में ट्रक ड्राइवर का काम करते हैं. ज़ाहिर है कि उनकी आमदनी भी ज़्यादा होगी, इसलिए उनके जीवन में ख़ुशहाली है. भनवर ख़ान अब मोरारका फाउंडेशन से जुड़कर जैविक खेती करना चाहते हैं. यहां के मुसलमानों के लिए यह एक अच्छा संकेत है.

सांप्रदायिक सौहार्द्र, एकता और कंधे से कंधा मिलाकर विकास पथ पर आगे बढ़ने की नवलगढ़ की यह कहानी पूरे देश के मुसलमानों को एक संदेश भी देती है. संदेश यह है कि आगे बढ़ने के लिए जहां अपनी सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है, वहीं एक–दूसरे पर विश्वास करने की भी. मोरारका फाउंडेशन का यह प्रयास बताता है कि विकास के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ सरकारी योजनाओं के भरोसे ही बैठकर रहा जाए. ख़ासकर, इस देश में विकास के अंतिम पायदान पर खड़े मुसलमानों के लिए बनीं सैकड़ों करोड़ों की सरकारी योजनाओं के असफल होते देखने के इस दौर में फाउंडेशन का यह प्रयास और भी प्रासंगिक हो जाता है.

tabrez@chauthiduniya.com

मोरारका फाउंडेशन से जुड़ी एक महिला ने जब मुस्लिम महिलाओं को भी इस कार्यक्रम से जोड़ने की कोशिश की तो शुरुआत में उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुस्लिम मोहल्लों के मर्द शुरू में उस महिला को अपने घरों में घुसने ही नहीं देते थे, लेकिन धीरे-धीरे इस महिला पर उनका विश्वास मज़बूत हुआ तो वे स्वयं सहायता समूह से ख़ुद को जोड़ने लगीं. अब उन्हें इस बात की काफ़ी ख़ुशी है कि वे अपनी ज़रूरतें इसी समूह से क़र्ज़ लेकर पूरा कर लेती हैं, साथ ही उन्हें पेपर बैग, बंधेज और इस तरह के दूसरे छोटे-मोटे काम घर पर करने को मिल जाते हैं, जिससे उनकी कुछ आमदनी हो जाती है.

चौथी दुनिया

पृथ्वी पर स्वर्ग उतार लाने का स्वप्न इसी बात से ज़ाहिर है कि भौतिक पदार्थ जितने भी हैं, वे सब बराबर-बराबर उपभोग किए जाएं. स्वर्ग की कल्पना भी ऐसा ही कुछ बतलाती है.

एक जन्मदिन, जो पता नहीं किस कारण से हम लोग नहीं मनाते हैं, वह है नेहरू का, लेकिन यह नेहरू जवाहर लाल नहीं, बल्कि उनके पिता मोती लाल नेहरू हैं.

चौथी दुनिया

महावीर प्रसाद आर मोरारका

वर्तमान अर्थव्यवस्था से संत्रस्त सृष्टि

अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि समान वित्त वितरण में कोई कठिनाई नहीं है. यह योजना शाश्वत चल सकने वाली और संभव है. आपने देख लिया होगा कि वर्तमान अर्थव्यवस्था से किसी को भी संतोष नहीं है. समाजवाद शब्द की व्याख्या किए बिना ही या मतलब समझे बिना ही आपको जंच गया होगा कि समान रूप से सबको धन का बंटवारा हो जाए तो वह ही अति उत्तम मार्ग है. अगर आपको यह नहीं जंचा है तो कोई भी दूसरा मार्ग जो अच्छा और संतोषप्रद हो, आप ही सुझाइए. शायद आपका बताया मार्ग ज़्यादा ठीक हो. अगर आपके पास कोई मार्ग नहीं है तो फिर आप भी समाजवादी बन जाइए. जो समाजवादी राजनीतिक पार्टी है, उससे और इस विचारधारा से कोई लाग-लगाव नहीं है. उस राजनीतिक पार्टी में सब तरह के व्यक्ति हैं, जैसे सब पार्टियों में हुआ करते हैं. उनमें ऐसे भी हैं जो लंबी-लंबी तकरीरें झाड़ते हैं और अगर कहीं आप अपने घर उन्हें दावत पर बुला लें तो शायद आपके जूते चोरी कर ले जाएं. अच्छे हैं, उनमें से काफी लोग अच्छे भी हैं. जब उनको आप कहेंगे कि भाई हमने समाजवाद का जो तथ्य समझा है, उसके हिसाब से राष्ट्र के संपूर्ण धन का समान बंटवारा करना है. चाहे वृद्ध हो या युवा, स्त्री हो या पुरुष, चोर, डाकू, धोबी, मोची, कुम्हार, शराबी, जुआरी सबके लिए समान रूप से वित्त वितरण करना होगा. आपकी बात सुनकर वह सिर्फ़ हंसेगा, मानो आपने बहुत नादानी की या मूर्खतापूर्ण बात कह दी हो.

फिर आप उनसे पूछिए कि भाई आप समाजवादी हैं, आप बताइए, आप कैसा समाजवाद चाहते हैं? तो उनका जवाब जो नपा-तुला है, वह यह है कि हर मानव को समान अवसर मिले, यही समाजवाद है. उनका कहना है कि अगर पूंजीवादी भी हो तो बुरा नहीं, पर पूंजीवादी बनने का सबको समान अवसर मिलना चाहिए. आप कहेंगे, भाई यह संभव कैसे है, बिना समान अवसर वित्त के समान अवसर कैसे बन पड़ेगा? इसका जवाब अधिकतर समाजवादी दे नहीं पाते हैं. आपने कई पुस्तकें पढ़ी होंगी, नहीं तो देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र या महाभारत काल की अर्थव्यवस्था, वहां समाजवाद का चित्रण सुलभ है. कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल पढ़ने लायक महत्वपूर्ण पुस्तक है. वर्तमान अर्थव्यवस्था से संत्रस्त होकर कतिपय नेताओं ने जो अलग-अलग आवाज़ें उठाईं, उसी में समूहवाद, आतंकवाद, अराजकतावाद, राष्ट्रवाद या साम्यवाद, कई तरह के वाद आ गए. वस्तुत: समाजवाद को समाजवाद के रूप में व्यवस्थित चलाने के लिए उनमें एक भी वाद संसार में कहीं भी सफल नहीं हो पाया.

वर्तमान अर्थव्यवस्था से संत्रस्त होकर कतिपय नेताओं ने जो अलग-अलग आवाज़ें उठाईं, उसी में समूहवाद, आतंकवाद, अराजकतावाद, राष्ट्रवाद या साम्यवाद, कई तरह के वाद आ गए. वस्तुत: समाजवाद को समाजवाद के रूप में व्यवस्थित चलाने के लिए उनमें एक भी वाद संसार में कहीं भी सफल नहीं हो पाया. यों तो सृष्टि के आदि से ही वैदिक काल में समाजवाद जीवित रहो और जीने दो के सिद्धांत में निहित है. भगवान से वैदिक प्रार्थना है, सर्वे संतु: निरामया: यानी सारी प्रजा सुखी रहे, किसी तरह की कमी या कष्ट महसूस न करे.

यों तो सृष्टि के आदि से ही वैदिक काल में समाजवाद जीवित रहो और जीने दो के सिद्धांत में निहित है. भगवान से वैदिक प्रार्थना है, सर्वे संतु: निरामया: यानी सारी प्रजा सुखी रहे, किसी तरह की कमी या कष्ट महसूस न करे. इस भावना का बाद में अनेक ऋषियों या दार्शनिकों ने भी ख़ूब प्रतिपादन किया. महर्षि अरस्तु और सुकरात या प्लेटो ने घोषणा की कि सबको भगवान ने समान बनाया है, समान ही जीने का अधिकार है. गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं, मानव ही नहीं, प्राणी मात्र इस माने में समान हैं.

विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी,
शुनि चैव श्वपा के च, पंडिता: समदर्शिन:.

अर्थात पढ़ा-लिखा ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या अंत्यज हो, इन सबको विद्वान लोग समान दृष्टि से देखते हैं, यही तो समाजवाद का उद्गम है, उस समय का समाजवाद यही तो था.

पृथ्वी पर स्वर्ग उतार लाने का स्वप्न इसी बात से ज़ाहिर है कि भौतिक पदार्थ जितने भी हैं, वे सब बराबर-बराबर उपभोग किए जाएं. स्वर्ग की कल्पना भी ऐसा ही कुछ बतलाती है. जिसने यह जान लिया कि भौतिक पदार्थों का बराबर-बराबर बंटवारा होना चाहिए, वही सच्चा समाजवादी है. चाहे इस निर्णय पर पहुंचने के लिए उसे किसी भी मार्ग का अनुसरण करना पड़ा हो. और जो यह नहीं जानता, वह समाजवादी नहीं है. वह चाहे कितने ही जोर से समाजवाद का नारा लगाए, चाहे हिमालय की चोटी से घोषणा करे कि मैं समाजवादी हूं और ऐसा करने में वह शहीद भी हो जाए, तो भी वह दरअसल में समाजवादी है नहीं. आपने जान लिया होगा कि तथाकथित समाजवादियों में और असली समाजवाद में कितना अंतर है. राजनीतिक पक्ष को प्रबल करने के लिए अलग-अलग पार्टियां अलग-अलग प्रचार करती हैं, पर तथ्यपूर्ण समाजवाद की स्थापना के लिए सच्चे मन से प्रयास कौन कर रहा है, यह विचारणीय है.

feedback@chauthiduniya.com

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

कमल मोरारका का ब्लॉग

www.kamalmorarka.com

ग़रीबी घटाने के लिए रणनीति बदलनी होगी

अन्ना हजारे एक टेलीविजन कार्यक्रम में गए और उन्होंने कहा कि भारत में दो तरह के लोग हैं. पहले तरह के लोग वे हैं, जो कहते हैं कि क्या खाऊं, मतलब यह कि उनके पास खाने को इतना कम है कि उन्हें यह सोचना पड़ता है कि वे क्या खाएं. दूसरे तरह के लोग वे हैं, जो कहते हैं कि क्या-क्या खाऊं, मतलब यह कि उनके पास खाने की इतनी चीजें उपलब्ध हैं कि उन्हें उनमें चुनना पड़ता है कि क्या-क्या खाएं. अन्ना हजारे ने समाज में फैली उस विषमता की ओर ध्यान दिलाया है, जो अमीरों और ग़रीबों के बीच मौजूद एक बड़ी खाई को दर्शाती है. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ उनका आंदोलन इसी विषमता से प्रेरित है. अन्ना को विश्वास है कि भ्रष्टाचार के कारण जो पैसा सिस्टम से बाहर जाता है, यदि वह विकास के काम में लगाया जाए तो ग़रीबों की समस्याओं पर बेहतर तरीके से ध्यान दिया जा सकता है.

इसमें कोई शक नहीं कि भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, लेकिन मेरा सोचना है कि हमारे पास ग़रीबी मिटाने और सबसे ग़रीब लोगों को उचित ढंग से खाना उपलब्ध कराने की कोई सही रणनीति नहीं है. अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन में शामिल होने वाले अधिकांश लोग उस वर्ग के थे, जिन्हें इस बात की चिंता होती है कि क्या-क्या खाऊं, न कि उस वर्ग के, जिन्हें यह सोचना पड़ता है कि क्या खाऊं. शहरी क्षेत्र में तो विशेषकर ऐसे ही लोग अन्ना के आंदोलन में शामिल थे. भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का समर्थन करना स्वागत योग्य है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश जिस प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है, उनकी ओर अन्ना टीम को ध्यान देना चाहिए. यह सही है कि भ्रष्टाचार कम होने से हमारी अर्थव्यवस्था पहले से ज़्यादा कारगर तरीके से काम करेगी, लेकिन इससे समस्याओं का समाधान तो नहीं होगा. इसके बावजूद विषमता बढ़ेगी ही. एक पूर्व वित्त मंत्री का कहना है कि जब ज्वार-भाटा आता है तो सारी नावें गतिशील हो जाती हैं. उनका मतलब है कि अगर अर्थव्यवस्था का विकास होगा तो सभी लोगों को इसका लाभ होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है.

पिछले बीस सालों को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है. इस बीच जीडीपी और वीओपी की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, लेकिन उसके अनुरूप गरीबों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है. इसी कारण यह कहा जा सकता है कि जिस तरह की रणनीति का पालन वर्तमान समय में किया जा रहा है, अगर आगे भी किया जाता रहा तो ग़रीबों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा. गरीब और बेरोज़गार लोग क्या खाऊं वाली परिधि से बाहर नहीं निकल पाएंगे. यह सही है कि मनरेगा जैसी कुछ योजनाएं बनी हैं, जो रोज़गार देती हैं और जिनके कारण ग़रीबों को पैसा मिलता है, लेकिन यह काफ़ी नहीं है. वर्तमान व्यवस्था में संसद लोगों की समस्याओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है. यह भी कहा जा रहा है कि अभी जिस प्रकार की चुनाव प्रणाली हमारे देश में है, उससे तो हम सुधार की बात नहीं सोच सकते. यह सही भी हो सकता है और ग़लत भी, लेकिन यदि वर्तमान व्यवस्था से लोग संतुष्ट नहीं हैं तो फिर इसके विकल्प की तलाश करनी ही पड़ेगी. वर्तमान चुनाव प्रणाली मुख्यत: अमीरों और ताक़तवर लोगों को ही सहयोग करती है.

यदि संसदीय लोकतंत्र को सही मायने में आगे बढ़ाना है तो इस व्यवस्था को जल्द से जल्द सुधारने की आवश्यकता है. इसमें सुधार के लिए एक प्रस्ताव रखा गया था कि चुनाव में पार्टियों द्वारा जो ख़र्च किया जाता है, उसका वहन सरकार करे, ताकि चुनाव में काले धन का इस्तेमाल रोका जा सके. चुनाव आयोग से इस बात की मांग की गई थी कि चुनाव में एक उम्मीदवार के लिए ख़र्च की जो सीमा तय की गई है, उसे बढ़ाया जाए. चुनाव आयोग ने इसे बढ़ाकर विधानसभा सदस्य के चुनाव के लिए 16 लाख रुपये कर दिया. सामान्य तौर पर एक विधानसभा सदस्य अपना चुनाव ख़र्च आठ से नौ लाख रुपये दिखाता है, लेकिन सभी जानते हैं कि वास्तविकता इसके विपरीत है. जितनी रकम दिखाई जाती है, उससे कई गुना अधिक ख़र्च की जाती है. चुनाव में किया गया यह ख़र्च काला धन ही होता है. ऐसी स्थिति में चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को रोकना बहुत मुश्किल लगता है. पार्टियां चाहे सरकार से पैसा लें या न लें, काले धन का इस्तेमाल तो किया ही जाएगा, क्योंकि ख़र्च सीमा निर्धारित करने के बाद भी चुनाव में कई गुना ज़्यादा ख़र्च किया जाता है, जिसे चुनाव आयोग नहीं रोक पाता है. जब सरकार चुनाव लड़ने के लिए पार्टियों को पैसा देगी तो भी यह होगा, तो फिर क्यों सरकारी धन बर्बाद किया जाए. इसलिए निर्वाचन सुधार के लिए विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है, उसके बाद ही इसका निर्धारण किया जा सकता है कि कैसी निर्वाचन प्रणाली हमारे देश के लिए सही रहेगी.

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

दलालों का मकड़जाल

केंद्र या बिहार सरकार की जितनी भी योजनाएं किसानों एवं मज़दूरों को लाभ पहुंचाने के लिए बनी हैं, जिनके लिए पैसे का भुगतान किसी न किसी बैंक द्वारा किया जाता है, ऐसे बैंकों के परिसरों में अक्सर दलालों का बोलबाला देखने को मिलता है और उनके जाल में फंसे बिना भुगतान संभव नहीं हो पाता. विशेषकर किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में बैंकों द्वारा जो रवैया अपनाया जा रहा है, उससे किसान परेशान हैं. दलाल और बैंक के अधिकारी-कर्मचारी किसानों को लूटने में लगे हैं.

–प्रताप नारायण सिंह, *बेगूसराय, बिहार.*

107/116 का दुरुपयोग

पुलिस द्वारा धारा 107/116 के दुरुपयोग के कारण प्राय: पीड़ित लोग थानों में जाने से कतराते हैं. जब भी कोई किसी दबंग व्यक्ति या संस्था द्वारा पीड़ित होता है तो पुलिस दोनों पक्षों की बात सुनने के बजाय उनसे रिश्वत लेने का प्रयास करती है. जो भी पुलिस की मुट्ठी गरम कर देता है, पुलिस उसी की बोली बोलने लगती है और दूसरे पक्ष को धमकाते हुए कहती है कि दोनों को शांति भंग करने के प्रयास में कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. ऐसे में पीड़ित पक्ष के पास कोई रास्ता नहीं बचता.

–शिव कुमार फ़ैज़ाबादी, *फ़ैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश.*

सर्वश्रेष्ठ पत्र

हॉकी की बदहाली

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल खेलने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कई खिलाड़ियों के पास मैच खेलने लायक जूते न होने का समाचार जहां इस खेल के खिलाड़ियों की आर्थिक बदहाली को बयां करता है, वहीं क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों के प्रति उपेक्षा को भी दर्शाता है. यह शर्म की बात है कि जिस खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा प्राप्त है, उसके खिलाड़ियों को पिछले साल अपने पारिश्रमिक के भुगतान के लिए भूख हड़ताल करनी पड़ी थी. दूसरी तरफ़ क्रिकेट पर पानी की तरह पैसा बहाया जाता है. सरकार को हॉकी पर ध्यान देना चाहिए.

–चंद्रकांत यादव, *चंदौली, उत्तर प्रदेश.*

मुसलमानों को आरक्षण मिले

भाजपा और शिवसेना को छोड़कर अमूमन सभी राजनीतिक दल ख़ुद को मुस्लिम हितैषी बताते हैं. सवाल यह है कि दर्जनों मुस्लिम हितैषी दल होने के बावजूद मुसलमानों की हालत बद से बदतर क्यों होती जा रही है. इस सवाल का जवाब किसी राजनेता के पास नहीं है, क्योंकि उनका मुसलमानों के हित से कोई लेना-देना नहीं है. मुसलमानों को आरक्षण देने से उनकी स्थिति सुधर सकती है. इसके लिए संविधान में संशोधन की ज़रूरत होगी. भाजपा और शिवसेना को छोड़कर कोई भी दल इसका विरोध नहीं करेगा. अगर वे ऐसा करती हैं तो उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा.

–मो. मसीह इमाम, *सहरसा, बिहार.*

भ्रष्टाचार का बोलबाला

भ्रष्टाचार एक विश्वव्यापी बीमारी है. एक तरफ़ जहां उत्तर कोरिया के असंख्य लोगों को भरपेट भोजन तक नसीब नहीं हो पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ़ वहां के तानाशाह किम जोंग इल ने एक लाख 20 हज़ार पाउंड स्टर्लिंग एक साल में अपने कुत्तों पर ख़र्च कर डाले. यह ख़ुलासा एक रिपोर्ट से हुआ है. कोरिया की एक चौथाई जनता यानी क़रीब 60 लाख लोग ग़रीबी के शिकार हैं. देश में पांच साल से कम उम्र के क़रीब एक तिहाई बच्चे कुपोषण के शिकार हैं. हमारे देश का भी यही हाल है. यहां राजनेता तो राजसी जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि जनता भूखों मरती है.

–सरफ़राज़ ख़ान, *दिल्ली.*

मनमोहन सिंह राष्ट्रपति बनेंगे!

चौथी दुनिया में प्रकाशित आलेख-मनमोहन सिंह राष्ट्रपति और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे पढ़ा. यह तो तय था कि आने वाले समय में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, पर मनमोहन सिंह का राष्ट्रपति बनना एक मिसाल होगा. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अब प्रधानमंत्री पद पर अपने लाडले की ताजपोशी करना चाहती हैं.

–आबिद मजीद, *जहानाबाद, बिहार.*

राजकमल प्रकाशन समूह

राजकमल प्रकाशन राधाकृष्ण लोकभारती प्रकाशन

चौथी दुनिया में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को राजकमल प्रकाशन की ओर से 700 रुपए की किताबें दी जाएंगी.

राजकमल प्रकाशन की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें. हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

वक़्त की नज़ाकत को समझने की ज़रूरत

दो अक्टूबर बीत गया. पहली बार देश में 2 अक्टूबर सरकारी फाइलों और सरकारी समारोहों से बाहर निकल करके लोगों के बीच में रहा. लोगों ने गांधी टोपी लगाकर महात्मा गांधी को याद किया. न केवल महात्मा गांधी को याद किया, बल्कि उनके विचारों के ऊपर चर्चाएं कीं, सेमिनार किए. 2 अक्टूबर बीतने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस देश में बहुत सालों के बाद गांधी का नाम गांधीवादियों द्वारा नहीं, बल्कि गांधी के विचारों की ताक़त के आधार पर लोगों के मन में घर कर रहा है. यह बड़ी अजीब बात है और शायद शर्मनाक भी कि आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें आईं या जितने भी समाजसेवी हुए, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन लोगों के मन में भरोसा नहीं जगा पाए और लोगों के सामने नए आदर्श नहीं गढ़ पाए. नतीजे के तौर पर जब एक फिल्म आई रंग दे बसंती, तो इस देश के नौजवानों, जिनकी उम्र आज 30 साल है, उस समय वे शायद 25, 26, 27 के रहे होंगे, को पता चला कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या क्रांतिकारी आंदोलन का मतलब क्या था. हालांकि उस फिल्म में बहुत सतही कोशिश हुई थी इन प्रतीकों को जोड़ने की, लेकिन इसके बावजूद उस फिल्म ने कमाल का काम किया और नौजवानों को बताया कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के आदर्श क्या थे, किस चीज़ को लेकर उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी.

दूसरी बात जो मुझे याद आती है, वह भी फिल्म से जुड़ी हुई है. फिल्म का नाम है लगे रहो मुन्ना भाई. इस फिल्म में गांधीगिरी शब्द का प्रयोग हुआ. बापू नाम के चरित्र ने मुन्ना भाई नाम के चरित्र को कई सारी चीज़ें बताईं. इस फिल्म ने गांधी जी के नाम पर नए सिरे से हिंदुस्तान के लोगों का मन झकझोरने का काम किया. लोगों ने विरोध का गांधीवादी तरीक़ा भी फिल्म से सीखा. जिसके प्रति वे विरोध करना चाहते थे, उसके यहां वे फूल लेकर जाने लगे, मौन बैठने लगे. कम ही जगहों पर हुआ, लेकिन हुआ और यह एक अच्छी शुरुआत थी. इसीलिए जब अन्ना हजारे ने उपवास किया तो लोगों ने अन्ना को सीधे गांधी की छवि से जोड़ दिया. देश में नौजवानों के मन में बात उठी कि अगर गांधी होते तो अन्ना जैसे होते. लोगों ने कहा कि हमने गांधी को नहीं देखा, लेकिन हम अन्ना को देख रहे हैं. इसीलिए इस बार गांधी जयंती पर न अन्ना हजारे ने कोई अपील की, न किसी ने अपील की, पर देश में जगह-जगह लोगों ने अपने आप न केवल गांधी जयंती मनाई, बल्कि गांधी के विचारों को भी आत्मसात करने की कोशिश की. गांधी के साहित्य को पढ़ने वाले लोगों की संख्या में इज़ाफ़ा हुआ है, पर इसमें सरकार क्या कर रही है. यह सरकार, हमारी अपनी सरकार, आज़ादी के बाद की भारत की सरकार या सरकारें, इन्होंने गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया. अगर देखें तो पाएंगे कि इन्होंने कुछ नहीं किया. क्या यह मान लिया जाए कि इन सरकारों का गांधी में कोई विश्वास रहा ही नहीं.

अगर और गहरे जाकर देखें तो कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब कोई सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन की बात सुनने से मना करती है तो यह सहज मान लेना चाहिए या माना जा सकता है कि वह सरकार गांधी के आदर्शों पर विश्वास नहीं करती. गांधी ने आज़ादी की लड़ाई अहिंसक ढंग से लड़ी. उन्होंने अहिंसा को एक ताक़तवर हथियार के रूप में लोगों के सामने रखा. उन्होंने अहिंसा के हथियार का उस समय की सर्वशक्तिमान या सर्वाधिक शक्तिशाली सरकार के सामने इस तरह प्रयोग किया कि वह सरकार हिल गई और हिंदुस्तान छोड़कर सात समंदर पार अपने देश लौट गई. जिस गांधी ने हिंदुस्तान को आज़ादी शांतिप्रिय ढंग से दिलाई, उसी गांधी के देश में अगर शांतिपूर्ण आंदोलन की बात न सुनी जाए तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है. ऐसा नहीं है कि गांधी ने यह अकेले किया, उनके साथ जवाहर लाल नेहरू थे. आज के ज़माने के जितने नेता हैं, इन सबके नेता कहीं न कहीं गांधी के साथ थे. हर एक कहीं न कहीं गांधी से प्रभावित था.

हमारे देश में अमीरी बढ़ रही है, लेकिन किन लोगों की अमीरी बढ़ रही है. देश के 7 से 9 प्रतिशत लोगों की अमीरी बढ़ रही है. पैसा उनकी जेब में जा रहा है. बाक़ी लोगों की खाने की थाली से खाने का सामान ख़त्म हो रहा है. पैसा है, लेकिन क्रय शक्ति घट रही है. बेरोज़गारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, निराशा बढ़ रही है, नक्सलवाद बढ़ रहा है. गांधी के इस देश में नक्सलवाद यह तर्क दे रहा है कि ग़रीबो, यह तुम्हारी सरकार है, जिसे तुम अपनी सरकार कहते हो, जिसे तुम वोट से चुनते हो, वही तुम्हारी बात नहीं सुनती.

उसी देश में लोगों की तकलीफों पर अगर सरकार ध्यान न दे, लोगों की परेशानियों को अपनी परेशानियां न समझे और उनका मज़ाक उड़ाए तो माना जा सकता है कि सरकार गांधी के आदर्शों पर भरोसा नहीं करती. कोई सरकार अपवाद नहीं है, कोई पार्टी अपवाद नहीं है, क्योंकि पार्टी जब सरकार में जाती है तो वह सरकार का चोला पहन लेती है और उसका चरित्र सरकारी चरित्र हो जाता है. लोगों को भरोसा था कि आज़ादी के बाद सरकारें जनता की बात सुनेंगी और उसकी तकलीफों को हल करने में अपना सारा ध्यान लगाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. हमारे देश में अमीरी बढ़ रही है, लेकिन किन लोगों की अमीरी बढ़ रही है. देश के 7 से 9 प्रतिशत लोगों की अमीरी बढ़ रही है. पैसा उनकी जेब में जा रहा है. बाक़ी लोगों की खाने की थाली से खाने का सामान ख़त्म हो रहा है. पैसा है, लेकिन क्रय शक्ति घट रही है. बेरोज़गारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, निराशा बढ़ रही है, नक्सलवाद बढ़ रहा है. गांधी के इस देश में नक्सलवाद यह तर्क दे रहा है कि ग़रीबो, यह तुम्हारी सरकार है, जिसे तुम अपनी सरकार कहते हो, जिसे तुम वोट से चुनते हो, वही तुम्हारी बात नहीं सुनती. इसलिए नहीं सुनती कि सरकार कभी भी ग़रीबों की बात सुन ही नहीं सकती. सरकार ग़रीबों की बात तभी सुनेगी, जब ग़रीब हाथ में हथियार उठाएगा. यह नक्सलवादियों का तर्क है और उनके इस तर्क को अमलीजामा पहनाने का काम हमारे देश की वे सरकारें कर रही हैं, वे राजनीतिक दल कर रहे हैं, जो आज़ादी के आंदोलन से कहीं न कहीं जुड़े थे, अहिंसक आंदोलन से जुड़े थे, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे.

आज उन सबको जो नौजवान हैं, जिनका इस देश के भविष्य में विश्वास है, जो इस देश को ख़ुशहाली के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और ख़ासकर उन नौजवानों को, जो सरकार से जुड़े हुए हैं, जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर रुककर यह विचार अवश्य करना चाहिए कि कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही है. कहीं हम ही तो बैठे-बैठाए लोकतंत्र के ख़िलाफ सामग्री लोगों के पास नहीं भेज रहे हैं, कहीं हम लोकतंत्र का नाम लेकर लोकतंत्र के प्रति अनास्था तो नहीं पैदा कर रहे हैं या अनास्था पैदा होने में हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं. अभी भी वक़्त है. लेकिन अगर इस वक़्त को हमने जाने दिया या वक़्त की ज़िम्मेदारी को समझते हुए इन तमाम सवालों पर विचार नहीं किया तो जब इनका उत्तर हमें मिलेगा तो वह उत्तर उस सवाल का नहीं होगा, जो देश का सवाल है. वह उत्तर लोगों के दु:ख-दर्द का होगा, जो निराशा से उपजा हुआ होगा और निराशा से उपजा हुआ उत्तर कभी भी शांति, समृद्धि, सौहार्द्र और विकास नहीं लाता. वक़्त है, सोचिए!

संपादक
editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

गांधी-नेहरू ज़िंदाबाद

दो अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है. यह दिन पाखंड, अतिशयोक्ति और बड़बोलेपन का होता है. इस दिन बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं. राष्ट्रपिता को हम लोग दो दिन ही याद रखते हैं, एक उनके जन्मदिवस पर और दूसरे जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी. इसके बाद गांधी जी नोटों पर विराजमान होकर हम पर हंसते हुए दिखाई देते हैं. ये वही नोट होते हैं, जिनका इस्तेमाल काले धन के तौर पर हमारी राजनीति को भ्रष्ट करने के लिए किया जाता है. आजकल कौन चरखा चलाता है और खादी के वस्त्र बुनता है, लेकिन गांधी जी के नाम का इस्तेमाल दोनों ओर से किया जाता है. राजनीति में फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए भी उनके नाम और उनके द्वारा सुझाए गए मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है. अन्ना हजारे का उदाहरण हमारे सामने है. उन्होंने दिखा दिया कि किस प्रकार 21वीं शताब्दी में भी पूरे भारत में युवाओं की भीड़ जुटाई जा सकती है. यह भीड़ केवल शहरी मध्य वर्ग के युवाओं की नहीं थी, जैसा कि सरकार ने प्रचारित किया. इसके अलावा गांधी और उनके शिष्य जय प्रकाश नारायण के नाम का इस्तेमाल राजनेताओं द्वारा भी किया जाता है और वे भी इनके नाम का इस्तेमाल भीड़ जुटाने के लिए करते हैं. हालांकि उनका उद्देश्य कुछ और ही होता है.

गांधी जी और उनके शिष्यों विशेषकर जय प्रकाश नारायण की अपील संसदीय व्यवस्था के विरुद्ध रही है. गांधी जी ने उस समय बनाए गए संविधान को पसंद नहीं किया था. उनका विचार था कि भारत में सात लाख स्वशासित गांव होने चाहिए. उनका यह विचार अव्यवहारिक और अराजकतावादी दिखाई पड़ता है. अव्यवहारिक इसलिए, क्योंकि गांधी जी जिस आदर्श गांव की बात करते थे, वह आज तक संभव नहीं हो सका. उनका गांव समानता पर आधारित गणतंत्र था, लेकिन आज का गांव उनके आदर्शों के विपरीत है. समानता की बात तो उसमें सोची ही नहीं जा सकती. गांव में दलितों एवं पिछड़े वर्ग के लोगों की स्थिति बदतर होती है. वे जानते हैं कि गांव उनके लिए जेल है, जहां से निकले बिना उनका कल्याण नहीं हो सकता है. इसी कारण वे गांव छोड़कर शहरों की ओर आते हैं, जहां उन्हें अपनी स्थिति सुधारने के अच्छे मौक़े मिल जाते हैं. खाप पंचायतों के फ़ैसलों ने यह बात साबित कर दी है कि वहां परंपराओं के निर्वहन के नाम पर लोगों को सताया जाता है. अंबेडकर इस बात को जानते थे और जवाहर लाल नेहरू उनके विचारों से सहमत थे. यही वजह थी कि इन लोगों ने ग्रामीण गणतंत्र के विचार का विरोध किया और पश्चिमी तरीक़े के निर्वाचन वाले संसदीय लोकतंत्र का समर्थन किया.

इसके बावजूद कि इन लोगों ने इस व्यवस्था को अच्छा समझा, अभी तक यह लोकतांत्रिक व्यवस्था जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल ही दिखाई दी. भ्रष्टाचार में संलिप्तता के कारण आज के सांसदों की विश्वसनीयता लगातार घटती जा रही है. ऐसे समय में हमें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है, जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके. अमेरिका में इसके लिए सफेद घोड़े पर बैठे एक आदमी की कल्पना की जाती है, लेकिन भारत में गांधी जी ने हमें दूसरी तस्वीर दिखाई है, एक कृशकाय संत की तस्वीर जो अनशन के माध्यम से दुनिया के दु:खों को दूर करने की ताक़त रखता है. लेकिन यह एक प्रकार से पूर्णत: लोकतंत्र विरोधी विचारधारा है. इसके तहत चुनी गई सरकार में अविश्वास किया जाता है, जबकि उस संत में विश्वास किया जाता है, जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा. यह वही रास्ता है, जिसका उपयोग गांधी जी ने कांग्रेस के माध्यम से भारत की आज़ादी के लिए किया था. वह ऐसे मज़बूत आदमी थे, जिसने अकेले ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, चाहे वह चौरी-चौरा के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मामला हो या भारत छोड़ो आंदोलन का या फिर सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफ़े का. गांधी जी के अलावा, जो कांग्रेस के चार आने वाले सदस्य तक नहीं थे, पूरी कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीक़े से काम करती थी, लेकिन स्वाधीनता के बाद भारत ने उस संत की छवि को अस्वीकार कर दिया, जो तानाशाह किस्म का था.

गांधी जी और उनके शिष्यों विशेषकर जय प्रकाश नारायण की अपील संसदीय व्यवस्था के विरुद्ध रही है. गांधी जी ने उस समय बनाए गए संविधान को पसंद नहीं किया था. उनका विचार था कि भारत में सात लाख स्वशासित गांव होने चाहिए. उनका यह विचार अव्यवहारिक और अराजकतावादी दिखाई पड़ता है. अव्यवहारिक इसलिए, क्योंकि गांधी जी जिस आदर्श गांव की बात करते थे, वह आज तक संभव नहीं हो सका.

एक जन्मदिन, जो पता नहीं किस कारण से हम लोग नहीं मनाते हैं, वह है नेहरू का, लेकिन यह नेहरू जवाहर लाल नहीं, बल्कि उनके पिता मोती लाल नेहरू हैं. मोती लाल अपने घर के तो शासक थे, लेकिन अपने राजनीतिक व्यवहार में वह लोकतांत्रिक थे. वह महात्मा गांधी के अनशन एवं ब्रह्मचर्य आदि विचारों को स्वीकार नहीं करते थे. उन्होंने चौरी-चौरा के बाद गांधी का साथ छोड़ दिया और स्वराज पार्टी की स्थापना की. इस पार्टी के माध्यम से उन्होंने विधायिका में प्रवेश किया. साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए 1929 में जो आयोग बनाया गया, उसके अध्यक्ष भी मोतीलाल ही थे. इस आयोग का काम भारत के लिए संविधान बनाना था. अगर देखा जाए तो भारत के संविधान के असली जन्मदाता तो मोती लाल नेहरू थे. गांधी को याद करना और मोती लाल को भूलना हमारी राजनीति के लिए सही नहीं है. गांधी जी संत के रूप में सही हो सकते हैं. चौरी-चौरा के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित करने का उनका निर्णय एकपक्षीय था. इस निर्णय ने कांग्रेस से मुस्लिमों को अलग करने में योगदान किया. इसी के बाद भारतीय मुसलमान कांग्रेस से अलग होने लगे. यह सही हो सकता है और गलत भी, लेकिन कांग्रेस आज़ादी मिलने तक उनके निर्णयों पर भरोसा करती रही. जब आज़ादी निकट थी, तब नेहरू और पटेल को पता हो गया था कि अब उन्हें निर्णय लेना है, न कि गांधी को, क्योंकि सरकार तो उन्हें ही चलानी है. अब यह कहना मुश्किल है कि नेहरू और पटेल ग़लत कर रहे थे.

feedback@chauthiduniya.com

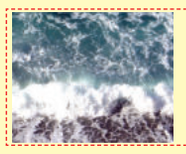

लोक सूचना अधिकारी न्यायालय की अवमानना की बात कहकर कई बार सूचना देने से मना कर देते हैं. हो सकता है कि कई बार यह तर्क सही भी हो.

सूचना का अधिकार चौथी दुनिया की पहल

सूचना की राह के रोड़े

कई बार लोक सूचना अधिकारी किसी आरटीआई आवेदन के जवाब में कहता है कि फलां सूचना तीसरे पक्ष से जुड़ी है, इसलिए आपको नहीं दी जा सकती या मामला अदालत में विचाराधीन है या फिर अमुक सूचना सार्वजनिक करने से संसद की अवमानना होगी, इसलिए सूचना नहीं दी जा सकती. इस अंक में हम आपको आरटीआई क़ानून की धारा 8 एवं 11, न्यायालय की अवमानना, संसदीय विशेषाधिकार और तीसरे पक्ष के बारे में उदाहरण सहित बताएंगे, जो आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने से रोकते हैं.

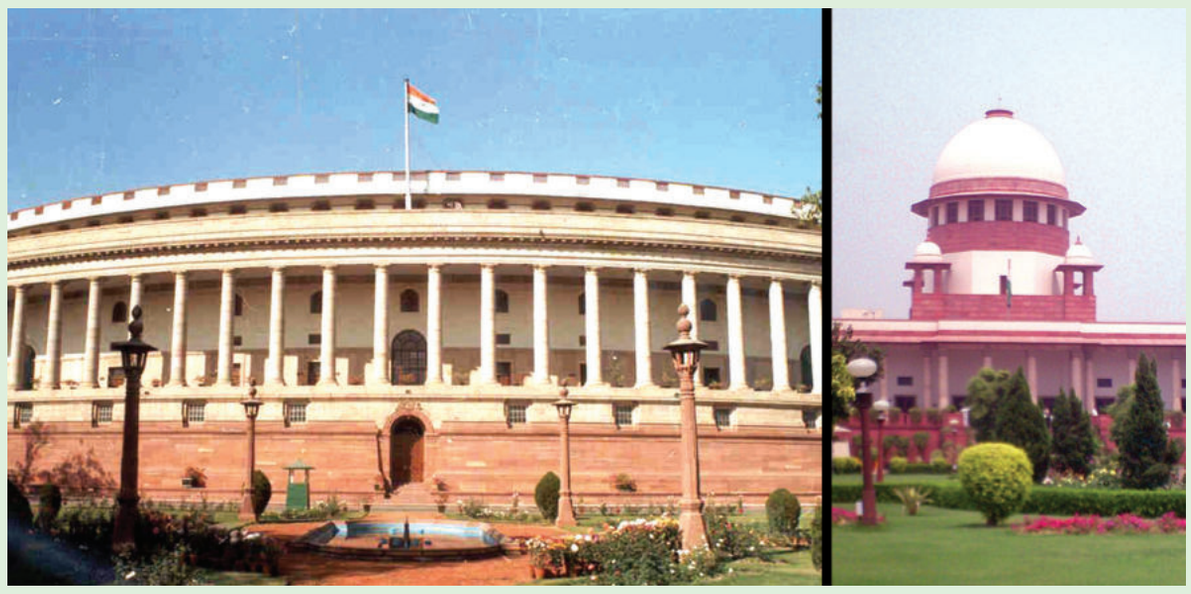

संसदीय विशेषाधिकार

आरटीआई क़ानून की धारा 8 (1) (सी) में बताया गया है कि ऐसी सूचना, जिसे सार्वजनिक किए जाने से संसद या किसी राज्य के विधान मंडल के विशेषाधिकार का हनन होता है, उसे सूचना के अधिकार के तहत दिए जाने से रोका जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार पीआईओ इस प्रावधान का सही इस्तेमाल करते हों. राहुल विभूषण ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और तीन सांसदों के बीच हुए पत्र व्यवहार की प्रतिलिपि मांगी थी. दरअसल एक पेट्रोल पंप को अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण बंद कर दिया गया था. इस पेट्रोल पंप को दोबारा खुलवाने के लिए तीन सांसदों ने पेट्रोलियम मंत्री को पत्र लिखा था. राहुल ने इस पत्र के जवाब की प्रतिलिपि मांगी थी, जिसे यह कहकर देने से मना कर दिया गया कि इसे दिए जाने से संसद के विशेषाधिकारों का हनन होता है. आयोग में सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त ने माना कि सांसद द्वारा लिखे गए पत्र का संसद या संसदीय कार्रवाई से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और इस सूचना के सार्वजनिक किए जाने से संसद के किसी विशेषाधिकार का कोई हनन नहीं होता. आयुक्त ने मांगी गई सूचना 15 दिनों के भीतर आवेदक को सौंपे जाने का आदेश दिया. कुल मिलाकर देखें तो ज़्यादातर मामलों में लोक सूचना अधिकारी संसदीय विशेषाधिकार की आड़ में सूचना देने से मना कर देते हैं, जबकि वास्तव में वह मामला संसदीय विशेषाधिकार से जुड़ा नहीं होता है.

न्यायालय की अवमानना

लोक सूचना अधिकारी न्यायालय की अवमानना की बात कहकर कई बार सूचना देने से मना कर देते हैं. हो सकता है कि कई बार यह तर्क सही भी हो, लेकिन ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि लोक सूचना अधिकारी इस तर्क का ग़लत इस्तेमाल करते हैं. इसलिए यह ज़रूरी है कि आवेदक को न्यायालय की अवमानना की सही परिभाषा के बारे में जानकारी हो. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)(बी) में ऐसी सूचनाएं, जिनके प्रकाशन पर किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्रतिबंध लगाया गया हो या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती हो, उसके सार्वजनिक किए जाने पर रोक लगाई गई है. अगर कोई मामला किसी अदालत में निर्णय के लिए विचाराधीन है तो इसका यह कदापि अर्थ नहीं है कि उससे संबंधित कोई सूचना नहीं मांगी जा सकती. विचाराधीन मामलों के संबंध में कोई सूचना सार्वजनिक किए जाने से अदालत की अवमानना हो, यह ज़रूरी नहीं है. हां, कोई विशेष सूचना, जिसे अदालत ने स्पष्ट तौर पर सार्वजनिक किए जाने पर रोक लगा दी हो, अगर उसे सार्वजनिक किए जाने की बात होगी तो कोर्ट की अवमानना ज़रूर होगी. गोधरा जांच के दौरान उच्च न्यायालय ने अपने एक फ़ैसले में रेल मंत्रालय को विशेष तौर पर निर्देश दिए थे कि वह गोधरा नरसंहार की जांच रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत न करे. न्यायालय ने रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने पर रोक लगा दी. इस सूचना को दिए जाने से अदालत की अवमानना हो सकती थी और धारा 8 (1)(बी) का उल्लंघन भी. ऐसे मुद्दों पर निर्णय देते वक़्त अधिकारियों को केवल वही सूचनाएं देने से मना करना चाहिए, जिन्हें न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर सार्वजनिक किए जाने को निषिद्ध कर रखा हो. कुछ मामलों में देखने में आया है कि सरकारी अधिकारी इस धारा का इस्तेमाल सूचना न देने के बहाने के रूप में धड़ल्ले से कर रहे हैं.

तीसरा पक्ष

सूचना अधिकार क़ानून के तहत जो व्यक्ति सूचना मांगता है, वह प्रथम पक्षकार होता है. जिस विभाग या लोक प्राधिकारी से सूचना मांगी जाती है, वह द्वितीय पक्षकार होता है. इस तरह की सूचनाओं में आम तौर पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती. लेकिन यदि आवेदक द्वारा मांगी जा रही सूचना आवेदक से सीधे-सीधे संबंधित न होकर किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित हो तो वह अन्य व्यक्ति ही तृतीय पक्ष कहलाता है. तीसरे पक्ष से संबंधित व्यक्ति की सूचना को तृतीय पक्ष की सूचना कहा जाता है. सूचना अधिकार क़ानून में तृतीय पक्ष की गोपनीयता को संरक्षित करने का प्रावधान है. क़ानून की धारा 11 के अनुसार, ऐसी सूचनाएं, जो किसी दूसरे व्यक्ति से संबंधित होती हैं, उन्हें आवेदक को दिए जाने से पूर्व तीसरे पक्षकार की इजाज़त लेनी पड़ती है. ऐसे मामलों में लोक सूचना अधिकारी की ज़िम्मेदारी होती है कि वह आवेदन प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर तीसरे पक्षकार को इस आशय की सूचना देगा और अगले 10 दिनों के भीतर सूचना जारी करने की सहमति या असहमति प्राप्त करेगा. लेकिन क़ानून में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसी सूचना, जिससे सामाजिक हित सधता हो या तीसरे पक्ष की सूचना को जारी करने से होने वाली संभावित क्षति लोकहित से ज़्यादा बड़ी न हो तो उस दशा में मांगी गई सूचना दी जा सकती है. क़ानून में यह एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी लोक सूचना अधिकारी को है कि वह मांगी गई सूचना तृतीय पक्षकार एवं लोकहित को अच्छी तरह समझ-बूझकर जारी करे. कई मामलों में देखने में आया है कि लोक सूचना अधिकारी व्यक्तिगत स्वार्थ या विभागीय दबाव के चलते तृतीय पक्ष से संबंधित सूचनाओं को जारी करने से रोकने के लिए धारा 11 का ग़लत इस्तेमाल कर रहे हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

बिजली बनाने का नायाब तरीक़ा

बिजली संकट से निजात पाने के लिए स्पेन में समुद्र की लहरों से बिजली बनाई जा रही है. हालांकि यह प्रक्रिया थोड़ी महंगी है, लेकिन कंपनी का कहना है कि तटीय इलाक़ों के लिए यह तकनीक अच्छी है. 600 लोगों को बिजली मिल रही है. इस साल गर्मियों में दक्षिणी स्पेन में दुनिया के पहले लहर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत हो गई. भारी लागत होने के बावजूद इस संयंत्र से दक्षिणी स्पेन के एक शहर को बिजली की आपूर्ति भी हो रही है. यह प्लांट अन्य तटीय इलाक़ों के लिए एक मॉडल साबित हो सकता है. स्पेन के छोटे से तटीय शहर मुत्रिको को देखकर यह कहना मुश्किल है कि इस शहर में हाईटेक पावर प्लांट भी लग सकता है, लेकिन सेन सेबास्टियन से 30 किलोमीटर दूर बास्के शहर के 600 लोगों को समुद्र की लहरों से बनने वाली बिजली मिल रही है. समुद्री लहरों से बिजली बनाने वाला यह संयंत्र बीते जुलाई माह में शुरू हुआ. बास्के शहर के संयंत्र में काम करने वाले इंजीनियर खोजे इगनाशियो होर्माएचे कहते हैं, जब लहरों से बिजली बनाने की बात आएगी तो लोग मुत्रिको का हवाला देंगे. लहरों से बिजली बनाने का यह पहला वाणिज्यिक ऑपरेशन है, जिससे ग्राहकों को बिजली मिलती है. यह संयंत्र बंदरगाह की दीवार से टकराने वाली लहरों से बिजली बनाता है. इस काम में लगी कंपनी एंटे वास्को दे ला एनर्जिया (ईवीई) ने बंदरगाह और समुद्र के बीच बनी दीवार में 16 गड्ढे बनाए हैं. जब लहरें इन गड्ढों में पानी लेकर आती हैं तो टरबाइन से हवा को धक्का दिया जाता है और बिजली पैदा होती है. इस तकनीक पर पिछले 10 सालों से स्कॉटलैंड में भी शोध और सुधार हो रहा है. दुनिया भर में लहरों से बनने वाली बिजली के 60 प्रोजेक्ट चल रहे हैं. कहीं पानी के नीचे स्पिन ब्लेड का इस्तेमाल कर बिजली बनाई जाती है तो कहीं अन्य तकनीक का इस्तेमाल करके. लिस्बन के लहर ऊर्जा केंद्र के शोधकर्ता फ्रैंक न्यूमैन के मुताबिक़ , मुत्रिको का प्लांट आर्थिक रूप से निकट भविष्य में सफल रहेगा. इस प्लांट में 300 किलोवॉट बिजली बनती है, जिससे शहर की 10 फ़ीसदी ज़रूरत पूरी होती है. इस प्लांट को बनाने में 70 लाख यूरो की लागत आई है. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के सरकारी पैनल का अनुमान है कि लहरों से बनने वाली बिजली विश्व की 30 फ़ीसदी ऊर्जा मांग को पूरा कर सकती है, लेकिन अक्षय ऊर्जा और स्थापित तकनीक के मुक़ाबले इस बिजली की तकनीक प्रारंभिक अवस्था में है.

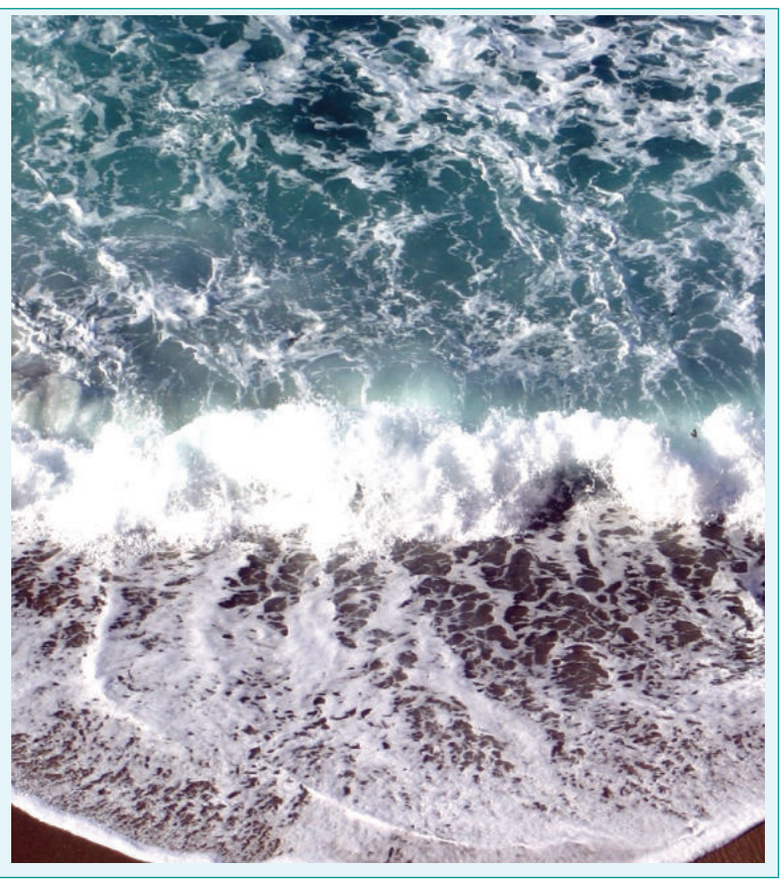

स्पीड का नया दावा

स्विटज़रलैंड में यूरोपीय परमाणु अनुसंधान केंद्र (सर्न) और इटली के वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि उन्हें ऐसे पार्टिकल मिले हैं जो प्रकाश की गति से तेज चलते हैं. वैज्ञानिक ख़ुद भी चकित हुए. पिछले दिनों वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि उन्हें न्यूट्रिनो नामक पार्टिकल मिले हैं, जो प्रकाश की गति से भी तेज चलते हैं. अगर यह कहीं और से भी साबित हो जाता है तो आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत ग़लत साबित हो जाएगा. स्विटजरलैंड की सर्न प्रयोगशाला और इटली की प्रयोगशाला में हुए प्रयोग के दौरान यह तथ्य सामने आया. पाया गया कि ये छोटे सब-एटॉमिक पार्टिकल 3,00,00,06 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से जा रहे हैं जो प्रकाश की गति से क़रीब छह किलोमीटर प्रति सेकेंड ज़्यादा है. इस प्रयोग के प्रवक्ता भौतिकविद् एंटोनियो ऐरेडिटाटो ने कहा, यह नतीजा हमारे लिए भी आश्चर्यजनक है. हम न्यूट्रिनो की गति नापना चाहते थे, लेकिन हमें ऐसा अद्भुत नतीजा मिलने की उम्मीद नहीं थी. हमने क़रीब छह महीने जांच, परीक्षण, नियंत्रण और फिर से जांच करने के बाद यह घोषणा की है. न्यूट्रिनो प्रकाश की तुलना में 60 नैनो सेकेंड जल्दी पहुंचे. इस प्रयोग में शामिल वैज्ञानिकों ने इसके नतीजों के बारे में नपे-तुले शब्दों में बात की. सर्न के निदेशक सर्गियो बेर्टोलुची ने कहा, अगर इस नतीजे की पुष्टि हो जाती है तो भौतिकी को देखने का हमारा नज़रिया बदल जाएगा. न्यूट्रिनो पर कोई आवेश नहीं होता और ये इतने छोटे होते हैं कि इनका द्रव्यमान भी अभी-अभी ही पता चल सका है. इनकी संख्या तो बहुत होती है, लेकिन इनका पता लगाना मुश्किल है. इन्हें भुतहा कण भी कहा जाता है और ये न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण पैदा होते हैं. इस प्रयोग के तहत वैज्ञानिकों ने स्विटज़रलैंड और इटली की प्रयोगशालाओं के बीच प्रकाश पुंज फेंका. दोनों प्रयोगशालाओं के बीच 730 किलोमीटर की दूरी है. पार्टिकल फिजिक्स की दुनिया में इस घोषणा से सनसनी फैल गई है. फ्रांस में भौतिकी संस्थान के पिएरे बिनेट्यूरी ने कहा, सामान्य सापेक्षता और विशेष सापेक्षता दोनों ही सिद्धांतों पर इससे सवाल खड़ा हुआ है. भौतिकविद् एंटोनियो जिचिषी कहते हैं, अगर आप प्रकाश की गति को छोड़ दें तो विशेष सापेक्षता का सिद्धांत तो नाकाम हो जाएगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)

मित्रजनों का साहचर्य समय को सार्थक कर देगा. फ़िलहाल जिस काम का बोझ आपके सिर पर है, उसे पूरा करना ज़रूरी है. जिस प्रकार के फ़ायदे आप अपने तरीक़े से लेना चाहते हैं, उसमें कुछ रुकावटें आ सकती हैं. आपका काम करने का तरीक़ा इतना सहज है कि आपको इसका फ़ायदा अवश्य मिल सकता है.

वृष (21 अप्रैल से 20)

घर और बाहर के मामले तनाव पैदा कर सकते हैं. मान-सम्मान की चिंता करें. सप्ताह मध्य के बाद आपको अच्छे भाग्य का संकेत मिल सकता है. यदि आप अपने रुके हुए काम को बनाने के लिए प्रयासरत रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. सप्ताह के अंत में अपना ज़रूरी काम समय पर पूरा कर लेने से ही आपको राहत मिलेगी.

मिथुन (21 मई से 20 जून)

अधिकार और प्रतिष्ठा हेतु अधिक साहस को आप विडंबना समझें. यह आपके लिए किसी धार्मिक कार्य या मानसिक सुख-शांति में सहायक हो रहा है. हो सकता है, सप्ताह के बीच में आपको अपने प्रियजनों के साथ किसी समारोह या आयोजन में शामिल होना पड़े. कार्यक्षेत्र में भी आपको सतर्क होकर चलना पड़ेगा.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)

सुखद भविष्य का स्वप्न साकार होगा और मायूसियां ख़त्म होंगी. आपके सभी पहले से तय किए काम पूरे हो सकते हैं. किसी शुभचिंतक या मित्र के ज़रिए ऐसा काम करने की प्रेरणा मिल सकती है, जो लाभदायक सिद्ध होगा. अच्छा समय बार-बार नहीं आता है, अत: उसका सही इस्तेमाल करना आपके लिए ज़रूरी है.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)

कुछ विघ्न-बाधाओं के कारण मायूसियां रहेंगी. काफी प्रयासों के बावजूद आपका लाभ मार्ग अवरुद्ध रहेगा. यद्यपि आपने पिछले काफी समय से जो परिश्रम किया है, उसका फल आपको पहले ही मिल जाना चाहिए था. इस प्रकार की बाधाएं जीवन में आती-जाती रहती हैं.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)

परिश्रम के बावजूद चेष्टाएं व्यर्थ जा सकती हैं. किसी पुराने संकल्प को पूरा करने वाला समय है. आपके उत्साह में वृद्धि होगी. युक्ति और तरकीब से काम करने से आपको अपने प्रयासों में इच्छित सफलता मिलेगी. सप्ताह मध्य में आपके व्यक्तित्व में सुधार आएगा और सामाजिक दायरे में लोकप्रियता बढ़ेगी.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)

आनंददायक आयोजनों में समय व्यतीत होगा. बनते हुए कार्य में अनावश्यक विलंब पैदा होगा. काफी समय से जो संकट आपके निजी जीवन में आया है, उसका कुछ ज़्यादा ही असर आप पर हो रहा है. यदि आप सूझबूझ और कूटनीति से काम लेंगे तो इन उलझनों को दूर करने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)

पराक्रम और निष्ठा से किया गया परिश्रम अवश्य लाभकारी होगा. मन में अनेक प्रकार की चिंताओं के बावजूद बाहर से आप सुख-शांति का अनुभव करेंगे. दूसरों को ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी बेहतरीन समय का आनंद उठा रहे हैं.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)

कोशिश करने पर कामकाज का फैलाव हो सकता है. आपके मित्र या सहयोगी सप्ताह मध्य में आपसे कुछ नाराज़ प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ और धैर्य की परीक्षा ऐसे ही समय पर होगी, जब किसी विपरीत परिस्थिति को आप अपने बुद्धि बल से अनुकूल बनाने में सहायक होंगे.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)

सूझबूझ के अभाव में व्यर्थाधिक्य का क्षोभ रहेगा. भावना और आवेग में आकर किए गए कार्यों का अवसाद होगा. अनेक प्रकार की व्यवसायिक सफलताएं आपको मिलने वाली हैं. सप्ताहांत में कोई ऐसा प्रयोग या तरीक़ा न अपनाएं, जिसके करने से आपका अपना हित कुछ समय के लिए टल जाए.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)

सप्ताह के आरंभ में आर्थिक समस्या ख़त्म हो जाएगी. अनुकूल चंद्रमा के बावजूद मन में उदासी और खिन्नता रहेगी. अपने किसी नज़दीकी परिवारीजन या बुजुर्ग के स्वास्थ्य की चिंता से आपका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)

शुभ संदेश से मन को उत्साह और प्रसन्नता मिलेगी. आप किसी ग़लत निर्णय या किसी व्यक्ति के वायदे से मुकर जाने के कारण परेशानी में पड़ सकते हैं. यह भी ध्यान रहे कि कोई गोपनीय बातचीत आपका विश्वासपात्र या नज़दीकी दोस्त कहीं लीक न कर दे.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

सीमा विवाद समाप्त करने के लिए दशकों से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिली.

क्रांति की राह पर यमन

राजीव कुमार

लीबिया, ट्यूनीशिया और मिस्र में सत्ता के विरुद्ध जनता का आंदोलन सफल रहा. तीनों देशों के तानाशाहों को पराजित होना पड़ा, लेकिन आंदोलन अभी थमा नहीं है. अगली बारी यमन की है. यमन में भी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष हो रहा है. राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह को सत्ता से बेदखल करने के लिए ख़ूनी जंग चल रही है. सऊदी अरब से इलाज कराकर अब्दुल्ला सालेह की वापसी के बाद हिंसा–प्रतिहिंसा का दौर फिर शुरू हो गया है. कबायली विद्रोहियों ने सालेह की सेना पर आक्रमण करके उनके विश्वस्त जनरल अब्दुल्ला अल कुलैबी की हत्या कर दी, साथ ही सालेह समर्थक 30 सैनिकों को बंधक बना लिया. यमन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस हमले में चार विद्रोहियों की भी मौत हुई. विद्रोहियों ने सेना का एक लड़ाकू विमान भी मार गिराया. यहां भी वही स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो लीबिया में है. यमन दो खेमों में बंट गया है. एक खेमा वर्तमान सरकार यानी अब्दुल्ला सालेह का समर्थन कर रहा है और दूसरा खेमा विरोध. कुल मिलाकर गृहयुद्ध के हालात हैं.

अब्दुल्ला सालेह 1978 से यमन पर शासन कर रहे हैं. वह चुनाव जीतने के लिए काबायलियों के बीच फूट का फ़ायदा उठाते रहे. कहने को तो वह यमन के निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, लेकिन देखा जाए तो वह तानाशाह रहे हैं. जब स्थिति बद से बदतर होने लगी तो लोगों को लगा कि अब सालेह को जाना चाहिए. जनवरी 2011 में सालेह सरकार के विरुद्ध क़रीब 16,000 लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया. वे सालेह से इस्तीफ़े की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने यह कहकर इस्तीफ़ा देने से इंकार कर दिया कि 2013 के बाद वह चुनाव नहीं लड़ेंगे और न अपने बेटे को सत्ता में भागीदार बनाएंगे. जनता उनके इस वायदे से संतुष्ट नहीं हुई और प्रदर्शन जारी रहा. विरोध करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती गई. बीते मार्च माह में हुए विद्रोह में कुछ लोगों की मौत भी हो गई, लेकिन विरोध बढ़ता रहा, कम नहीं हुआ. सालेह ने खाड़ी सहयोग परिषद से मध्यस्थता करने के लिए कहा, लेकिन जब सालेह ने सहयोग नहीं किया तो परिषद ने मध्यस्थता करने से मना कर दिया.

सालेह की दमनकारी नीतियों ने सरकार का विरोध करने वाले लोगों को विद्रोही बनने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने भी गोली का जवाब गोली से देना शुरू कर दिया. सालेह समर्थकों में भी फूट पड़ने लगी और सरकार में शामिल लोग उनका साथ छोड़ने लगे. प्रधानमंत्री के सलाहकार अब्दुल मजीद सहित कई मंत्रियों ने इस्तीफ़ा दे दिया. विरोधियों ने संगठित होना शुरू कर दिया और शेख सादिक अल अहमर ने उनका नेतृत्व किया. जनरल अली मोहसिन अल अहमर भी विरोधियों में शामिल हो गए. इसके बाद सालेह समर्थक सैनिकों और विरोधियों के बीच जो ख़ूनी जंग शुरू हुई, वह अभी तक चल रही है.

अभी हाल में यमन में अलक़ायदा के एक नेता अनवर अल अवलाकी की हत्या कर दी गई, जिसे अमेरिका ने अलक़ायदा के लिए एक बड़ा झटका बताया. इससे निश्चित तौर पर सालेह की साख बढ़ेगी, लेकिन यह तय है कि जिस दिन विद्रोहियों ने अपना मज़बूत संगठन बना लिया और अपने नेता का चुनाव कर लिया, उसी दिन से विश्व के कई देश उन्हें खुला समर्थन देने लगेंगे.

यमन में चल रहा यह संघर्ष अब्दुल्ला सालेह के अंत के साथ ख़त्म होगा या उनके विरोधियों की पराजय के साथ, यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन वहां जैसे हालात हैं, उनसे तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि जनता की जीत होगी. लीबिया में भी ऐसा ही हुआ था. वहां भी ग़द्दाफ़ी सरकार के लोग उसके रवैये से नाख़ुश होकर उसका साथ छोड़ने लगे थे, लेकिन वहां गद्दाफी की पराजय का एक सबसे बड़ा कारण नाटो सैनिकों द्वारा विद्रोहियों का साथ देना रहा. यमन में अभी वैसी स्थिति नहीं है. सालेह अलक़ायदा का सफ़ाया करने का क़दम उठाकर अमेरिका को ख़ुश करने की कोशिश कर रहे हैं. अभी हाल में यमन में अलक़ायदा के एक नेता अनवर अल अवलाकी की हत्या कर दी गई, जिसे अमेरिका ने अलक़ायदा के लिए एक बड़ा झटका बताया. इससे निश्चित तौर पर सालेह की साख बढ़ेगी, लेकिन यह तय है कि जिस दिन विद्रोहियों ने अपना मज़बूत संगठन बना लिया और अपने नेता का चुनाव कर लिया, उसी दिन से विश्व के कई देश उन्हें खुला समर्थन देने लगेंगे. अमेरिका एवं यूरोपीय देश लोकतंत्र के नाम पर विद्रोहियों का समर्थन करेंगे और सालेह का भी वही हाल होगा, जो ग़द्दाफ़ी का हुआ. इसलिए सालेह के लिए उचित यही है कि वह जन भावनाओं का आदर करें और गद्दी का लालच छोड़कर चुनाव कराएं.

feedback@chauthiduniya.com

चीन से सतर्क रहना ज़रूरी

भारत के प्रति चीन का रवैया हमेशा संदिग्ध रहा है. आज़ादी के बाद भारत के चीन से संबंध अच्छे रहे, सुरक्षा परिषद में चीन की स्थायी सदस्यता के लिए भारत ने समर्थन किया, वहीं चीन ने भी नेहरू के पंचशील के सिद्धांत का समर्थन किया था और हिंदी–चीनी भाई–भाई का नारा दिया गया था, लेकिन चीनियों ने यही नारा लगाते हुए 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया. इस घटना ने भारतीयों को काफ़ी आहत किया और भारत में चीन को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा. यूं तो चीन हमेशा भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की बात करता है, लेकिन उसके कारनामे ऐसे होते हैं, जिनके कारण उस पर विश्वास करना मुश्किल है. जहां उसे फ़ायदा दिखाई पड़ता है, वहां तो वह भारत के साथ अच्छे संबंधों की दुहाई देता है, लेकिन जहां उसे लगता है कि इस काम से उसे नुक़सान हो या न हो, लेकिन भारत को नुक़सान ज़रूर होगा तो वहां वह मौक़े का लाभ उठाने से नहीं चूकता. एशिया में वह भारत को ही अपनी रफ्तार में बाधा समझता है. इसलिए वह भारत को समस्याओं में उलझाए रखना चाहता है. भारतीय सीमा का अतिक्रमण अथवा अरुणाचल प्रदेश को विवादित बनाना उसकी इसी नीति का उदाहरण है.

हाल की कुछ घटनाओं ने इसे और अधिक पुख्ता कर दिया है. भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर उसने आपत्ति जताई थी. विश्व बैंक से अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए पैसा मिलना था, चीन ने उसका भी विरोध किया था. चीन ने भारतीय सेना के एक अधिकारी, जो कश्मीर में तैनात थे, को वीजा न देकर इस विवाद को और तूल दे दिया था. भारत ने भी इस पर कड़ा रुख़ अपनाया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच संबंध फिर से सामान्य हो गए. दोनों देशों के बीच सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सीमा संबंधी विवाद रहा है. सीमा विवाद समाप्त करने के लिए दशकों से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिली. अधिकारी स्तर पर लगातार वार्ताएं हो रही हैं, फिर भी स्थिति जस की तस है. लगता है, चीन विवादों का निपटारा चाहता ही नहीं. वह तो यदा–कदा भारतीय सीमा का अतिक्रमण करता रहता है. विगत अगस्त माह में चीनी सैनिकों ने हद ही कर दी. उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाक़े में भारतीय सैनिकों द्वारा बनाई गई दीवार तोड़ डाली. हालांकि इस दीवार को फिर से बना दिया गया. कुछ माह पहले ही चीन के सैन्य हेलीकॉप्टरों ने जम्मू–कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया था.

इस मामले को चीनी सेना के साथ हुई फ्लैग मीटिंग में उठाया भी गया, परंतु नतीजा कुछ नहीं निकला. इस तरह की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं. विगत अगस्त माह में चीन की तरफ से वास्तविक नियंत्रण रेखा का कम से कम 26 बार उल्लंघन किया गया. भारतीय सेना का कहना है कि कई स्थानों पर वास्तविक नियंत्रण रेखा स्पष्ट नहीं है, इसलिए ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन सेना के इस कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता. अगर ऐसी बात है तो भारत की तरफ से सीमा का उल्लंघन क्यों नहीं किया जाता, क्यों हमेशा चीनी सैनिक ही सीमा का उल्लंघन करते हैं? चीनी सैनिक तो भारतीय सीमा में घुसकर भारतीय सैनिकों के शिविरों से मिट्टी का तेल, पेट्रोल और अन्य सामान भी उठाकर ले जाते हैं. सीमा उल्लंघन के मामलों में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार पचास फ़ीसदी की वृद्धि हुई है. पिछले साल चीनी सैनिकों ने सिक्किम स्थित भारतीय सीमा पर गोलीबारी भी की थी. इन सब घटनाओं से ऐसा लगता है कि चीन भारत के साथ अपने सीमा विवाद में सैन्य दबाव बढ़ाना चाहता है. भारतीय वायुसेना के पूर्व अध्यक्ष सुरेश मेहता ने भी एक बार कहा था कि चीन आर्थिक तौर पर ताक़तवर होने के साथ–साथ सीमाओं के मामले में भारत पर अपना दबाव डाल रहा है. रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन एशिया में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है, जिसके लिए वह भारत पर आक्रमण भी कर सकता है. हालांकि भारत सरकार ऐसी किसी आशंका से इंकार करती है, लेकिन अगर भारत–चीन संबंधों का इतिहास देखा जाए तो इस बात पर यकीन किया जा सकता है. 1962 में भी चीन ने भारत पर आक्रमण अपना वर्चस्व दिखाने और भारत को नीचा दिखाने के लिए किया था. इसलिए भारत को चीन से हमेशा सतर्क रहना चाहिए.

राजीव कुमार
feedback@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक–संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम–उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा–201301 www.chauthiduniya.tv

साई बाबा रामगिर बुवा को बापूगिर बुवा कहते थे. उन्होंने रामगिर उर्फ बापूगिर बुवा को अपने पास बुलाया और उन्हें कुछ समय के लिए जामनेर जाकर नाना साहब चांदोरकर के यहां रुकने के लिए कहा.

जामनेर में बाबा का चमत्कार

साई बाबा ने रामगिर को आश्वासन दिया कि वह चिंता न करें, जामनेर तक जाने की सुविधा उन्हें मिल जाएगी. उसके बाद बाबा ने शामा से माधव आदकर द्वारा रची गई आरती की एक प्रति तैयार करने के लिए कहा और उस प्रति को भभूत के साथ नाना साहब चांदोरकर को जामनेर में देने के लिए रामगिर बुवा को दे दिया.

वर्ष 1904-05 में नाना साहब चांदोरकर खानदेश ज़िले के जामनेर में मामलतदार थे. जामनेर शिरडी से 100 मील से अधिक दूर है. उनकी पुत्री मैना ताई उस समय गर्भवती थी और वह अपने पिता चांदोरकर के पास जामनेर में थी. उसकी दशा बहुत ही गंभीर थी और दो-तीन दिनों से वह प्रसव पीड़ा से कष्ट पा रही थी. नाना साहब ने सभी प्रकार के उपचार कराए, पर सब व्यर्थ गया. तब उन्होंने साई बाबा का स्मरण किया और उनसे सहायता मांगी. उधर शिरडी में रामगिर बुवा ने खानदेश में स्थित अपने पैतृक घर में जाने की इच्छा व्यक्त की. साई बाबा रामगिर बुवा को बापूगिर बुवा कहते थे. उन्होंने रामगिर उर्फ बापूगिर बुवा को अपने पास बुलाया और उन्हें कुछ समय के लिए जामनेर जाकर नाना साहब चांदोरकर के यहां रुकने के लिए कहा. रामगिर उर्फ बापूगिर बुवा ने साई बाबा को बताया कि उनके पास केवल जलगांव तक ही रेल टिकट लेने लायक रुपये हैं, इसलिए जलगांव से 30 मील दूर जामनेर तक जा पाना संभव नहीं हो पाएगा. साई बाबा ने रामगिर को आश्वासन दिया कि वह चिंता न करें, जामनेर तक जाने की सुविधा उन्हें मिल जाएगी. उसके बाद बाबा ने शामा से माधव आदकर द्वारा रची गई आरती की एक प्रति तैयार करने के लिए कहा और उस प्रति को भभूत के साथ नाना साहब चांदोरकर को जामनेर में देने के लिए रामगिर बुवा को दे दिया. रामगिर बुवा ने शिरडी से प्रस्थान किया और वह लगभग दो बजकर पैंतालिस मिनट के समय रात को जलगांव पहुंच गए. उस समय उनके पास केवल दो आने बचे थे और उनकी दशा बहुत ख़राब थी. तभी किसी ने कहा, शिरडी का बापूगिर बुवा कौन है? वह उसके पास गए और बोले, मैं बापूगिर बुवा हूं. उस व्यक्ति ने बताया कि वह चांदोरकर द्वारा उसे लेने के लिए भेजा गया चपरासी है. उसने रामगिर बुवा को एक बहुत अच्छे तांगे पर बैठाया, जिसमें दो बहुत अच्छे घोड़े जुते हुए थे. चपरासी के साथ एक तांगा चलाने वाला भी था. तांगा तेजी के साथ दौड़ने लगा. सबेरे वे लोग एक छोटे नाले के पास पहुंच गए. वहां पहुंच कर तांगे वाले ने तांगा रोका और घोड़ों को पानी पिलाने के लिए तांगे से अलग किया. चपरासी की दाढ़ी-मूंछ और वर्दी देखकर रामगिर बुवा को संदेह हुआ कि यह मुसलमान है और इसलिए उसका दिया हुआ नाश्ता खाने में वह हिचकिचाए. उन्हें पशोपेश में देखकर चपरासी ने कहा, मैं हिंदू हूं और गढ़वाल ज़िले का रहने वाला क्षत्रिय हूं. यह नाश्ता नाना साहब ने उनके लिए भेजा है, इसे खाने में संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है. नाश्ता करने के बाद दोनों तांगे में बैठकर आगे चले और वे शाम होते-होते जामनेर पहुंच गए. रामगिर बुवा लघुशंका के लिए तांगे से उतरे. कुछ मिनटों के बाद वापस आने पर वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि वहां पर तांगा, घोड़ा, तांगे वाला और चपरासी कोई भी नहीं था.

रामगिर बुवा नाना साहब चांदोरकर के घर पहुंचे और साई बाबा द्वारा दी गई आरती और भभूत उन्हें दे दी. उस समय मैना ताई की दशा बहुत गंभीर थी और सब उसके बारे में चिंता कर रहे थे. नाना साहब ने अपनी पत्नी को बुलाया और उनके हाथ में भभूत देकर उसे पानी में घोलकर मैना ताई को पिलाने और साथ ही आरती गाने के लिए कहा. चांदोरकर ने सोचा कि साई बाबा की सहायता समयोचित है और उनकी कृपा से ही यह सहायता मिली है. थोड़ी ही देर में नाना साहब चांदोरकर को सूचना मिली कि प्रसव उचित और सुरक्षित ढंग से हो गया और ख़तरा टल गया है. जब रामगिर बुवा ने नाना साहब चांदोरकर को तांगा और नाश्ता भेजने के लिए धन्यवाद दिया, तब वह अचरज में पड़ गए और बोले, मैंने तो किसी को नहीं भेजा था. मुझे तो मालूम भी नहीं था कि शिरडी से कोई आ रहा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बालाराम धुरंधर और भगवान पांडुरंग

साताक्रूज, बंबई के बालाराम धुरंधर प्रभु जाति के एक सज्जन पुरुष थे. वह बंबई उच्च न्यायालय में एडवोकेट थे और किसी समय शासकीय विधि विद्यालय बंबई के प्राचार्य भी थे. उनका संपूर्ण कुटुंब सात्विक एवं धार्मिक था. बालाराम ने अपनी जाति की ख़ूब सेवा की और इस संबंध में एक पुस्तक भी प्रकाशित कराई. इसके बाद उनका ध्यान आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों पर गया. उन्होंने ध्यानपूर्वक गीता, उसकी टीका ज्ञानेश्वरी एवं अन्य दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन किया. वह पंढरपुर के भगवान विठोबा के परम भक्त थे. 1912 में उन्हें साई बाबा के दर्शनों का लाभ हुआ. छह माह पूर्व उनके भाई बाबुल जी और वामनराव ने शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए थे और उन्होंने घर लौटकर अपने मधुर अनुभव भी बालाराम एवं परिवार के अन्य लोगों को सुनाए. तब सब लोगों ने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया. यहां शिरडी में उनके पहुंचने के पूर्व ही बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आज मेरे बहुत से दरबारीगण आ रहे हैं. अन्य लोगों द्वारा बाबा के उपरोक्त वचन सुनकर धुरंधर परिवार को काफी आश्चर्य हुआ. उन्होंने अपनी यात्रा के संबंध में किसी को भी इसकी पहले से सूचना नहीं दी थी. सभी ने आकर उन्हें प्रणाम किया और बैठकर वार्तालाप करने लगे. बाबा ने अन्य लोगों को बताया कि ये मेरे दरबारीगण हैं, जिनके संबंध में मैंने तुमसे पहले कहा था. फिर वह धुरंधर भाइयों से बोले कि मेरा और तुम्हारा परिचय 60 जन्म पुराना है. सभी नम्र और सभ्य थे, इसलिए वे सब हाथ जोड़े हुए बैठे-बैठे बाबा की ओर निहारते रहे. उनमें सब प्रकार के सात्विक भाव जैसे अश्रुपात, रोमांच एवं कंठावरोध आदि जागृत होने लगे और सबको बड़ी प्रसन्नता हुई. इसके बाद वे सब भोजन के लिए गए और थोड़ा विश्राम लेकर पुन: मस्जिद आकर बाबा के पांव दबाने लगे. उस समय बाबा चिलम पी रहे थे. उन्होंने बालाराम को भी चिलम देकर एक फूंक लगाने का आग्रह किया. यद्यपि अभी तक उन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया था, फिर भी चिलम हाथ में लेकर बड़ी कठिनाई से उन्होंने एक फूंक लगाई और आदरपूर्वक बाबा को लौटा दी. बालाराम के लिए तो यह अनमोल घड़ी थी. वह 6 वर्षों से श्वांस रोग से पीड़ित थे, पर चिलम पीते ही रोगमुक्त हो गए. उन्हें फिर कभी यह कष्ट नहीं हुआ. 6 वर्षों के बाद उन्हें एक दिन पुन: दौरा पड़ा. यह वही दिन था, जब बाबा ने महासमाधि ली थी. वह गुरुवार के दिन शिरडी आए थे. भाग्यवश उसी रात्रि को उन्हें चावड़ी उत्सव देखने का अवसर मिल गया. आरती के समय बालाराम को चावड़ी में बाबा का मुखमंडल भगवान पांडुरंग सरीखा दिखाई पड़ा. दूसरे दिन कांकड़ आरती के समय उन्हें बाबा के मुखमंडल की प्रभा अपने परम इष्ट भगवान पांडुरंग के सदृश ही पुन: दिखाई दी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

श्री साई महिमा

श्री साई राम परम सत्य, प्रकाश रूप, परम पावन शिरडी निवासी, परम ज्ञान आनंद स्वरूप, प्रज्ञा प्रदाता, सच्चिदानंद स्वरूप, परम पुरुष योगीराज, दयालु देवाधिदेव हैं, उनको बार-बार नमस्कार.

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

मुख्य अतिथि जीनों पोनिन बल्लोम ने हिंदी दिवस के आयोजन की शुरुआत को महत्वपूर्ण बताया और इसे हर साल किए जाने की संकल्पना को मूर्त रूप देने की बात कही.

अनंत विजय

अमिताभ का विरोध क्यों?

हमारे देश के सबसे बड़े साहित्यिक पुरस्कार को लेकर विवाद पैदा किया जा रहा है. विवाद और आपत्ति इस बात को लेकर है कि शहरयार और अमरकांत को ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी फिल्मों के महानायक अमिताभ बच्चन के हाथों दिया गया. इस बात को लेकर कई साहित्यकारों को घोर आपत्ति है कि हिंदी फिल्मों में नाचने–गाने वाला कलाकार हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक को सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार देने योग्य कैसे हो गया. दरअसल यह हिंदी के शुद्धतावादी लेखकों की कुंठा है, जो किसी न किसी रूप में प्रकट होती है. मेरी जानकारी में सबसे पहले यह सवाल हिंदी के आलोचक वीरेंद्र यादव ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर उठाया. वीरेंद्र यादव ने फेसबुक पर लिखा, हिंदी के दो शीर्ष लेखकों श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने का समाचार इन दिनों सुर्ख़ियों में है. फ़िलहाल इस बात से ध्यान हट गया है कि ज्ञानपीठ में अब अमिताभ बच्चन का दख़ल हो गया है. अभी पिछले ही हफ्ते शहरयार को अमिताभ बच्चन ने यह पुरस्कार दिया है यानी अब मूर्धन्य साहित्यकार बॉलीवुड के ग्लैमर से महिमामंडित होंगे. जिस सम्मान को अब तक भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और नेल्सन मंडेला जैसी विभूतियां देती रही हों, उसकी यह परिणति दयनीय नहीं है. वीरेंद्र यादव ने फेसबुक पर क्या नहीं की शक्ल में सवाल भी उछाला. वीरेंद्र यादव एक समझदार और सतर्क आलोचक हैं. उनसे इस तरह की हल्की टिप्पणी की उम्मीद मुझे नहीं थी. अमिताभ बच्चन इस देश के एक बड़े कलाकार हैं और सिर्फ़ फिल्मों में लंबू तंबू में बंबू लगाए बैठा और झंडू बाम का विज्ञापन कर देने भर से उनका योगदान कम नहीं हो जाता. क्या वीरेंद्र यादव को अमिताभ बच्चन की उन फिल्मों के नाम गिनाने होंगे, जिनमें उन्होंने यादगार भूमिकाएं कीं. क्या वीरेंद्र यादव को अमिताभ बच्चन के अभिनय की मिसाल देनी होगी. मुझे नहीं लगता है कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी. अमिताभ बच्चन इस सदी के सबसे बड़े कलाकार के तौर पर चुने गए हैं.

मुझे लगता है कि अशोक वाजपेयी का विरोध अमिताभ से कम ज्ञानपीठ से ज़्यादा है. उसी विरोध के लपेटे में अमिताभ बच्चन आ गए हैं. जिस तरह से किसी जमाने में प्रतिष्ठित रहा अख़बार ज्ञानपीठ के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहा है, उससे यह बात और साफ हो जाती है. अशोक वाजपेयी की देखादेखी कुछ छुटभैये लेखक भी अमिताभ बच्चन और ज्ञानपीठ के विरोध में लिखने लगे.

वीरेंद्र यादव को यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की अपनी आर्थिक ज़रूरतें होती हैं और वह जिस पेशे में होता है, उससे अपनी उन आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करता है. अमिताभ बच्चन ने भी वही किया. सचिन तेंदुलकर और शबाना आजमी भी कई उत्पादों का विज्ञापन करते हैं तो क्या सिर्फ़ उन विज्ञापनों के आधार पर ही उनके क्षेत्र में उनके योगदान को नकार दिया जाए. अमिताभ बच्चन की तरह बिरजू महाराज भी झंडू बाम का विज्ञापन करते हैं तो इसी आधार पर उनके योगदान को कम कर दिया जाना चाहिए. लगता है, वीरेंद्र जी की नज़र से यह विज्ञापन नहीं निकला, वर्ना वह बिरजू महाराज और उनके योगदान को ख़ारिज कर देते. कई बड़े कलाकार विज्ञापन करते हैं, ये बातें उनके पेशे से जुड़ी हैं. अमिताभ बच्चन पोलियो ड्राप का भी विज्ञापन करते हैं. वीरेंद्र यादव की बहस में इस बात के लिए भी अमिताभ की आलोचना की गई है कि वह गुजरात के ब्रांड एंबेसडर हैं. उस गुजरात के, जिसके मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हैं. लेकिन इस बात को छुपा लिया गया कि वही अमिताभ बच्चन उस जमाने में केरल के ब्रांड एंबेसडर थे, जब वहां वामपंथी सरकार थी. तो इस तरह के तर्क और इस तरह की समझ पर सिर्फ़ तरस आ सकता है.

हिंदी के एक और लेखक अशोक वाजपेयी, जिनका दायरा और एक्सपोजर किसी भी अन्य लेखक से बड़ा है, ने भी अमिताभ बच्चन के हाथों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने को संस्थान की एक दयनीय कोशिश क़रार दिया है. अशोक वाजपेयी ने अपने साप्ताहिक स्तंभ में लिखा कि यह समझना मुश्किल है कि अब अपने को सिनेमाई चमक से जोड़ने की जो दयनीय कोशिश भारतीय ज्ञानपीठ कर रहा है, उसका कारण क्या है. अशोक वाजपेयी जी को यह समझना होगा कि ज्ञानपीठ की यह कोशिश अपने को सिनेमाई चमक से जोड़ने की नहीं, बल्कि हिंदी के बड़े लेखक को एक बड़े कलाकार के हाथों सम्मानित कराने की हो सकती है. मुझे नहीं मालूम कि ज्ञानपीठ की मंशा क्या थी. वह सिनेमाई चमक से जुड़कर क्या हासिल कर लेगा. इस मंशा और वजह को अशोक वाजपेयी बेहतर समझते होंगे. अशोक जी के मुताबिक़, ज्ञानपीठ का किसी अभिनेता को बुलाने का निर्णय किसी कलामूर्धन्य को बुलाने की इच्छा से नहीं जुड़ा है, क्योंकि ऐसी इच्छा के ज्ञानपीठ में सक्रिय होने का कोई प्रमाण या परंपरा नहीं है. प्रसंगवश उन्होंने भारत भवन में कालिदास सम्मान के लिए तीन कलामूर्धन्यों को बुलाने की बात कहकर अपनी पीठ भी थपथपा ली.

वाजपेयी जी के इन तर्कों में कोई दम नहीं है और ज्ञानपीठ की परंपरा की दुहाई देकर वह अमिताभ बच्चन के योगदान को कम नहीं कर सकते. अमिताभ का हिंदी के विकास में जो योगदान है, उसे अशोक वाजपेयी के तर्क नकार नहीं सकते. अमिताभ बच्चन ने हिंदी के फैलाव में जिस तरह से भूमिका निभाई, उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके आलोचकों को वह भी दिखाई नहीं देता. अमिताभ बच्चन हिंदी फिल्मों के एकमात्र कलाकार हैं, जो हिंदी में पूछे गए सवालों का हिंदी में ही जवाब देते हैं. मुझे तो लगता है कि हाल के दिनों में जिस तरह से घोटालों की छीटें यूपीए सरकार पर पड़ रही हैं, उस माहौल में मनमोहन सिंह से बेहतर विकल्प तो निश्चित तौर पर अमिताभ बच्चन हैं. दरअसल अशोक वाजपेयी जैसे संवेदनशील लेखक, जो कला और कलाकारों की इज़्ज़त करते रहे हैं, की लेखनी से जब एक बड़े कलाकार के लिए छोटे शब्द निकलते हैं तो तकलीफ होती है. अशोक वाजपेयी को अमिताभ बच्चन के हाथों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिलवाने पर तो आपत्ति है, लेकिन जब हिंदी के जादुई यथार्थवादी कहानीकार उदय प्रकाश को कट्टर हिंदूवादी नेता योगी आदित्य नाथ अपने कर कमलों से पुरस्कृत करते हैं तो अशोक वाजपेयी चुप रह जाते हैं. अशोक वाजपेयी जैसे बड़े लेखक की जो यह सेलेक्टेड चुप्पी होती है, वह साहित्य और समाज के लिए बेहद ख़तरनाक है.

मुझे लगता है कि अशोक वाजपेयी का विरोध अमिताभ से कम ज्ञानपीठ से ज़्यादा है. उसी विरोध के लपेटे में अमिताभ बच्चन आ गए हैं. जिस तरह से किसी जमाने में प्रतिष्ठित रहा अख़बार ज्ञानपीठ के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहा है, उससे यह बात और साफ हो जाती है. अशोक वाजपेयी की देखादेखी कुछ छुटभैये लेखक भी अमिताभ बच्चन और ज्ञानपीठ के विरोध में लिखने लगे. अख़बार ने उन्हें जगह देकर वैधता प्रदान करने की कोशिश की, लेकिन अख़बार के कर्ताधर्ताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि पाठक मूर्ख नहीं होते हैं. उन्हें प्रायोजित चर्चाओं और स्वत:स्फूर्त स्वस्थ साहित्यिक बहस में फ़र्क़ मालूम होता है. वह यह भांप सकता है कि कौन सा विवाद अख़बार द्वारा प्रायोजित है और उसके पीछे की मंशा और राजनीति क्या है. कहना न होगा कि ज्ञानपीठ और अमिताभ को विवादित करने के पीछे की मंशा भी साफ तौर पर लक्षित की जा सकती है. इस विवाद को उठाने के पीछे की मंशा के सूत्र आप छिनाल विवाद से भी पकड़ सकते हैं. लेकिन इतना तय मानिए कि हिंदी के लोगों के मन में फिल्मी कलाकारों को लेकर जो एक ग्रंथि है, वह उनके ख़ुद के लिए घातक है. फिल्म में काम करने वाला भी कलाकार होता है और किसी भी साहित्यकार, गायक, चित्रकार से कम नहीं होता. मेरा तो मानना है कि अमिताभ बच्चन को बुलाकर ज्ञानपीठ ने एक ऐसी परंपरा क़ायम की है, जिससे हिंदी का दायरा बढ़ेगा. इस बात का विरोध करने वाले हिंदी भाषा के हितैषी नहीं हो सकते. उनसे मेरा अनुरोध है कि व्यक्तिगत स्कोर सेट करने के लिए किसी का अपमान नहीं होना चाहिए.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

फ्रांस में हिंदी दिवस का आयोजन

फ्रांस शासित बेहद ख़ूबसूरत रीयूनियन द्वीप में पहली बार हिंदी की पताका पहुंची. यहां पर भारतीय मूल के लोगों की आबादी लगभग 22,500 है, जिनमें तमिल एवं गुजराती मूल के भारतवंशी प्रमुख हैं. यहां भाषाई विभिन्नता न होकर सभी लोग फ्रेंच अथवा क्रियोल बोलते हैं. अंग्रेजी का नाममात्र भी प्रयोग नहीं होता. यहां हिंदी का रास्ता गुजराती मूल के भारतवंशियों में शामिल मुस्लिम एवं सुनार समाज में बची भाषाओं उर्दू और गुजराती के बीच से होकर निकलता है. राजधानी सेंट डेनिस के आंदी विला में वे बहुत रोमांचकारी पल थे, जब हिंदी दिवस समारोह में सम्मिलित होने के लिए ऐसे लोग एकत्र थे, जिनमें से कुछ तमिल जानते थे, कुछ उर्दू, कुछ गुजराती, कुछ अंग्रेजी और सभी फ्रेंच. कार्यक्रम की शुरुआत फ्रांस एवं भारत के राष्ट्रगीत जन–गण–मन... से हुई. मंच पर मुख्य अतिथि काउंसिल जीनों पोनिन बल्लोम, विशिष्ट अतिथि राकेश पांडेय–संपादक प्रवासी संसार (भारत), भारतीय कौंसलावास के अधिकारी महावीर रावत, आयोजक रजनीकांत जगजीवन, अध्यक्ष एनआरआई–रीयूनियन आंदी एवं उमेश कुमार आदि थे. कुछ श्रोताओं द्वारा हिंदी बिल्कुल न समझने के कारण भाषणों को हिंदी से फ्रेंच में अनुवाद की व्यवस्था की गई और यह कार्य उमेश कुमार ने किया.

राकेश पांडेय ने कहा कि जैसे अंग्रेजों की प्रतिनिधि भाषा अंग्रेजी है, फ्रांस की प्रतिनिधि भाषा फ्रेंच है, उसी तरह भारत में अनेक बोलियां–भाषाएं होते हुए भी हमारी भाषाई पहचान हिंदी है. यहां आप सभी भारत की भाषाई पहचान हिंदी के महत्व को रेखांकित करने के लिए एकत्र हुए हैं, आप सभी को बधाई. पांडेय ने विदेशों में हिंदी की स्थिति पर प्रकाश डाला. इसके बाद भारतीय कौंसलावास का प्रतिनिधित्व करते हुए महावीर रावत ने भारत में हिंदी के संवैधानिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्थानीय लोगों को हिंदी के प्रचार–प्रसार के लिए पुस्तकें एवं अन्य सहायता का आश्वासन दिया, साथ ही राकेश पांडेय एवं रजनीकांत के प्रयासों को सराहा, जिनके कारण रीयूनियन में हिंदी दिवस का आयोजन संभव हुआ.

मुख्य अतिथि जीनों पोनिन बल्लोम ने हिंदी दिवस के आयोजन की शुरुआत को महत्वपूर्ण बताया और इसे हर साल किए जाने की संकल्पना को मूर्त रूप देने की बात कही. कार्यक्रम के दूसरे चरण में भारतीय परिधानों का फैशन शो आयोजित किया गया. अंत में अतिथियों के लिए भारतीय मिठाइयां जैसे जलेबी, पेड़ा एवं गुझिया आदि परोसी गईं. पेड़े को तो भारतीय ध्वज के अनुरूप सजाया गया था. भारतीय मूल के प्रसिद्ध डॉक्टर दर्शन सिंह ने अगली बार भव्य तरीक़े से हिंदी दिवस मनाने की बात कही. सेंट लुई के मेयर क्लाउदे होराऊ की ओर से उनके सांस्कृतिक प्रबंधक एवं कवि सुली ने अगले वर्ष उनके यहां हिंदी दिवस आयोजन का प्रस्ताव भी किया.

राकेश पांडेय
feedback@chauthiduniya.com

किताब मिली

पुस्तक का नाम
मुबारक पहला कदम

संपादन
राजेन्द्र यादव

प्रकाशक
राजकमल प्रकाशन

मूल्य
450 रुपये

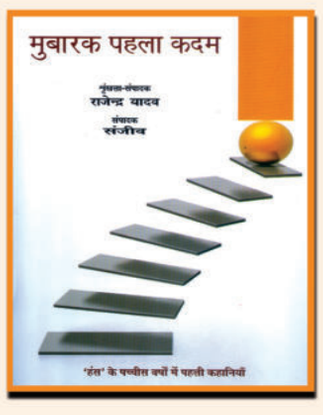

इस किताब में ३३ लेखकों की विभिन्न कहानियां शामिल हैं.

सभी के लिए उपयोगी पुस्तकें

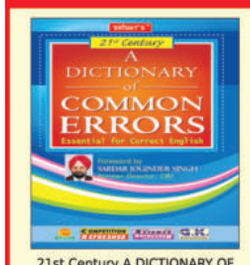

21st Century A DICTIONARY OF COMMON ERRORS
₹ 99

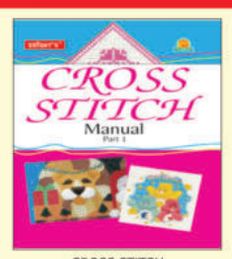

CROSS STITCH Manual Part - 1
₹ 60

Cross-Stitch Manual Part - II
₹ 70

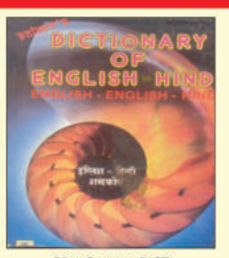

21st Century DICT ENGLISH - HINDI
₹ 75

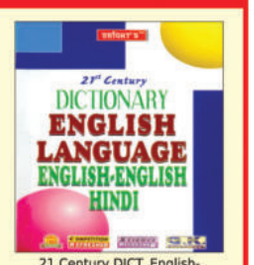

21 Century DICT. English-English-Hindi
₹ 125

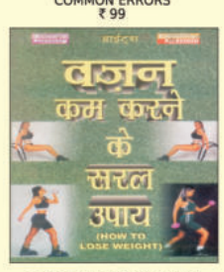

वजन कम करने के सरल उपाय
₹ 50

इंगलिश सीखिए और बोलिए
₹ 199

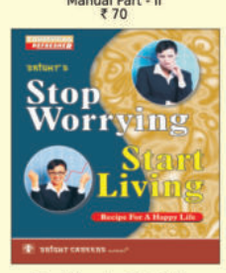

Stop Worrying Start Living
₹ 50

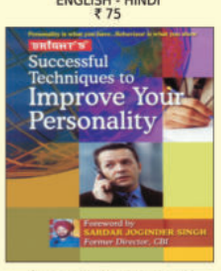

Successful Techniques to Improve Your Personality
₹ 99

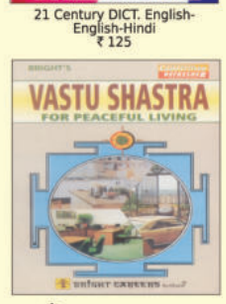

★ VASTU SHASTRA
₹ 70

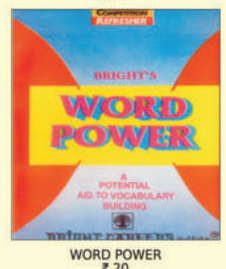

WORD POWER
₹ 20

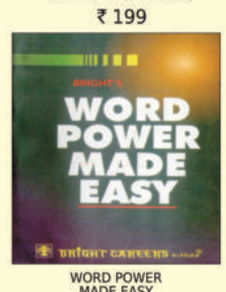

WORD POWER MADE EASY
₹ 80

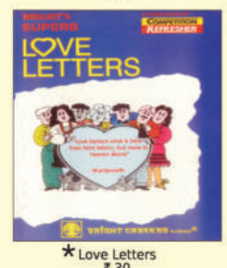

★ Love Letters
₹ 30

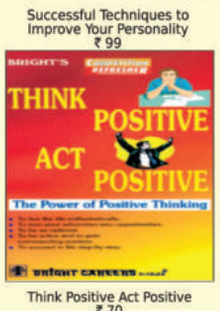

Think Positive Act Positive
₹ 70

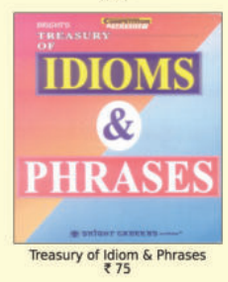

Treasury of Idiom & Phrases
₹ 75

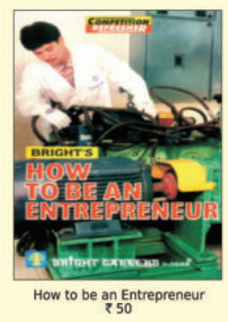

How to be an Entrepreneur
₹ 50

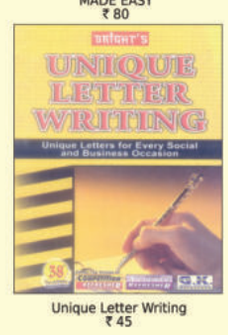

Unique Letter Writing
₹ 45

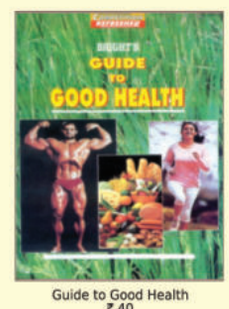

Guide to Good Health
₹ 40

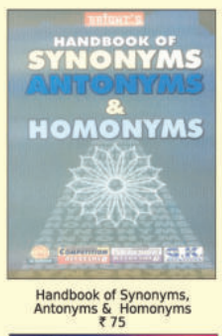

Handbook of Synonyms, Antonyms & Homonyms
₹ 75

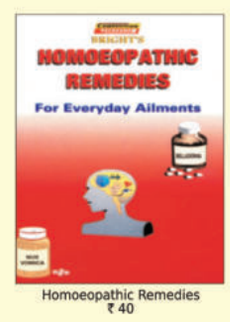

Homoeopathic Remedies
₹ 40

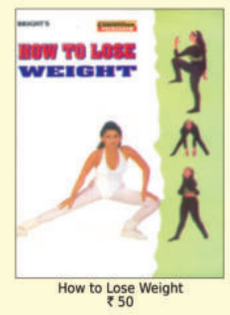

How to Lose Weight
₹ 50

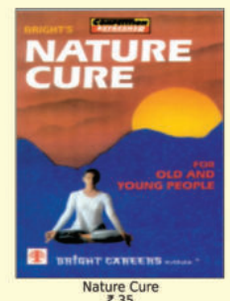

Nature Cure
₹ 35

A Modern Approach to Personality Development
₹ 45

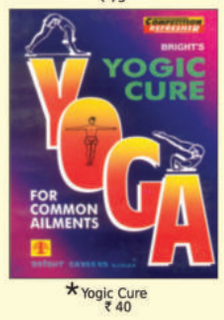

★ Yogic Cure
₹ 40

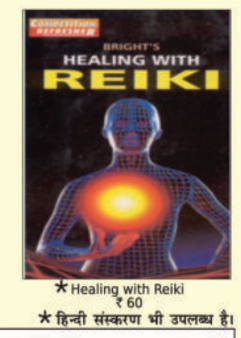

★ Healing with Reiki
₹ 60
★ हिन्दी संस्करण भी उपलब्ध है।

ब्राईट पब्लिकेशंस
भारत में सर्वाधिक बिकने वाली प्रतियोगिता पुस्तकों के प्रकाशक
2767, कूचा चैलान, दरियागंज, दिल्ली–110002 (भारत) (स्थापित : 1968)
फोन : 011-64632226, 23282226, 23283226 — फैक्स : 011-23269227
ई–मेल: sales@brightpublications.com | वैब साइट: http://www.brightpublications.com

हैंडसेट में पहले से ही कुछ एप्लीकेशंस मौजूद हैं, जैसे पैनोरमिक ईमेज व्यूवर. यह मॉडम को भी सपोर्ट करता है. हैंडसेट को आप किसी भी दूसरे हार्डवेयर से जोड़ सकते हैं.

फोटो- सुनील मल्होत्रा

नई दिल्ली में जीनियस ई-बाइक के लांचिंग के दौरान लोहिया ऑटो इंडस्ट्रीज के सीईओ आयुष लोहिया.

इंपल्स 4-जी मोबाइल

तकनीक के एक और पायदान पर क़दम रखते हुए मोबाइल हैंडसेट की दुनिया में एक नया प्रयोग हुआ. ग्लोबल मार्केट में 4-जी हैंडसेट ने अपने क़दम रख दिए हैं. 4-जी तकनीक वाले हैंडसेट में 3-जी का अपडेटेड वर्जन है जिसमें 3-जी से बेहतर इंटरनेट ब्राउजिंग और तेज़ डाउनलोडिंग की सुविधा है. नेक्स्ट जेनरेशन ने 4-जी की सर्विस को एलटीई और वाईमैक्स-2 टेक्नोलॉजी नाम दिया था, पर आजकल मार्केट में हर आम फोन 4-जी के नाम पर धड़ाधड़ बिक रहा है. इसी को देखते हुए चाइनीज कंपनी हवाई ने इंपल्स नामक 4-जी फोन को बाज़ार में इंट्रोड्यूस किया है. यह हैंडसेट एंड्रॉयड 2.2 स्मार्ट फोन है, जिसे कंपनी ने अभी डेमोंसट्रेट करने और इसकी विश्वसनीयता को जानने के लिए गारंटी में रखा है. इस कैंडी बार फोन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 120/65/11.9 एमएम है तथा भार केवल 125 ग्राम है. हवाई इंपल्स 4-जी टीएफटी डिस्प्ले के साथ है, जिसका रेजोल्यूशन 480/800 पिक्सल है. इस फोन की शानदार स्क्रीन 3.8 इंच की है जिसमें मल्टी टच और प्रोक्समिटी सेंसर भी लगा हुआ है. इसका कैमरा 5 मेगा पिक्सल है जिसमें लेड फ्लैश और ऑटो फोकस की बेहतरीन सुविधा है. इस स्मार्ट फोन में वे सारी ख़ूबियां हैं, जिनकी यूजर को बेहद ज़रूरत होती है. अगर आपको बार-बार इंटरनेट यूज़ करने में समस्या आती है तो इस फोन में वाईफाई 802.11 बी/जी/एन डिवाइस लगी है. फोन में 512 एमबी की मेमोरी है. इस डिवाइस के डाटा स्टोरेज को माइक्रो एसडी की मदद से 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. इसका मल्टी सिस्टम काफी जानदार है.

रॉक इट चार्जेबल स्पीकर

म्यूज़िक और गीत-संगीत के प्रति लोगों की बढ़ती रुचि देखकर कंपनियां ऑडियो स्पीकर्स में भी नए प्रयोग कर रही हैं और तरह-तरह के ऑडियो स्पीकर बाज़ार में उतारने पर जोर दे रही हैं. इस समय आईबॉल, जेबीएल एवं फिलिप्स के अलावा कई ऐसी कंपनियां हैं, जिनके अलग- अलग प्रकार के ऑडियो डिवाइस बाज़ार में उपलब्ध हैं. ऑडियो डिवाइस बनाने वाली कंपनी ऑरिग ने भी बाज़ार में नई तकनीक से लैस पोर्टेबल स्पीकर पेश किए हैं. ऑरिग के कॉम्पैक्ट स्पीकर्स को किसी भी म्यूज़िक डिवाइस से जोड़ा जा सकता है. यूजर्स इसे अपने आईपॉड, टेबलेट और एमपी-3 प्लेयर से कनेक्ट करके अपने फेवरिट म्यूज़िक का मजा ले सकते हैं. रॉक इट में एंप्लीफायर नहीं दिया गया है, लेकिन निराश होने की बात नहीं है क्योंकि रॉक इट स्पीकर में एक स्टिकी पैड है जिसे आडियो डिवाइस पर चिपका दिया जाता है. इस पैड की वजह से जब म्यूज़िक प्ले होता है तो स्पीकर डिवाइस की मदद से आवाज एंप्लीफाई हो जाती है जिससे यूजर को दमदार आवाज़ सुनने को मिलती है. रॉक इट स्पीकर में दो ट्रिपल ए बैटरी के लिए बैक साइड में जगह दी गई है. स्पीकरों को यूएसबी केबल की मदद से चार्ज भी किया जा सकता है. इसके अलावा 3.5 एमएम हेडफोन जैक की मदद से आप किसी भी ऑडियो डिवाइस को स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हैं. स्पीकर में दी गई स्टिक को किसी भी खाली जगह या फिर बॉक्स के अंदर रखने पर शानदार साउंड क्वालिटी मिलती है. किसी साधारण प्लास्टिक बाउल में भी स्टिक रखने पर अच्छी साउंड क्वालिटी मिलती है. भारत में रॉक इट स्पीकर 3,800 रुपये की अनुमानित कीमत में सभी ऑडियो स्टोर में उपलब्ध है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ऑप्टीमस ईएक्स का न्यू वर्जन

परफार्मेंस गैजेट के लिए मशहूर एलजी एक बार फिर से पीसी बाज़ार में कुछ नया लाई है. एंड्रॉएड फोन की मांग को देखते हुए एलजी ने अपने सबसे उन्नत फोन एलजी ऑप्टीमस के अपग्रेड वर्जन ऑप्टीमस ईएक्स को लांच किया है. एलजी ऑप्टीमस के पिछले वर्जन में काफी खामियां थी जिसे एलजी ने अपने नए वर्जन के फोन में दूर किया है. ऑप्टीमस ईएक्स में 4 इंच का मल्टीटच स्टाइलिश स्क्रीन दिया गया है जो 800/480 रेज्यूलूशन को सपोर्ट करता है. फोन का लुक एलजी ऑप्टीमस के पिछले लुक से काफी स्लिम और शानदार है साथ ही कैरी करने में भी पहले के मुक़ाबले यह काफी हल्का है. फोन में 1.2 गीगा हर्ट का ड्यूलकोर प्रोसेसर दिया गया है जो इसे शानदार परफार्मेंस प्रोवाइड करता है. ऑप्टीमस का ईएक्स एंड्रॉएड के 2.3 जिंजरब्रेड प्लेटफार्म में रन करता है जो आजकल ज़्यादातर फोन में कंपनियां दे रही हैं. 5 मेगापिक्सल के रियर कैमरे से फोन की वीडियो और फोटो कैपचरिंग क्वालिटी अच्छी आती है जो यूजर्स को बेहद पसंद आएगी. इसके अलावा एफएम, ब्लुटूथ, वाईफाई, ऑडियो और वीडियो प्लेयर जैसे स्मार्टफोन फीचर्स नए एलजी ऑप्टीमस में दिए गए हैं. हैंडसेट में फास्ट सोशल नेटवर्किंग साइट्स को एक्सेस करने के लिए कई शॉर्टकट आइकॉन मौजूद है.

आईफोन-आईपैड में फोटो एडिटिंग

एप्लीकेशन बाज़ार में आईफोन एवं आईपैड के लिए कई अनोखे और यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन मौजूद हैं, जिनमें फोटो शेयरिंग से जुड़े एप्लीकेशन को खासा पसंद किया जा रहा है. आईफोन और आईपैड के लिए ऐसे ही एक नए एप्लीकेशन इंस्टाग्राम को डिज़ाइन किया गया है, जिसे आईफोन और आईपैड में इंस्टाल कर यूजर फोटो कैप्चरिंग के साथ फोटो शेयरिंग भी कर सकते हैं. इंस्टाग्राम में साधारण सी फोटो मॉडीफाई करने के साथ ही कई तरह के इफैक्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं. अब तो ज़्यादातर लोग अपने मोबाइल से फोटो और वीडियो कैप्चरिंग करते हैं. मोबाइल कंपनियां भी अपने फोन में हाई डेफिनेशन कैमरा प्रोवाइड करा रही हैं. हाल में सोशल नेटवर्किंग साइटों में बूम सा आ गया है, इसलिए फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन से जुड़ा व्यवसाय काफी बढ़ गया है. इंस्टाग्राम को आईफोन एवं पैड आपरेटिंग सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया है. एप्लीकेशन में चार लेयर का ऑप्शन दिया गया है जिसे पिक्चर में एप्लाई करने के बाद फोटो क्वालिटी अच्छी हो जाती है. इंस्टाग्राम 2.0 अपने पिछले वर्जन से 200 गुना ज़्यादा तेजी से काम करता है.

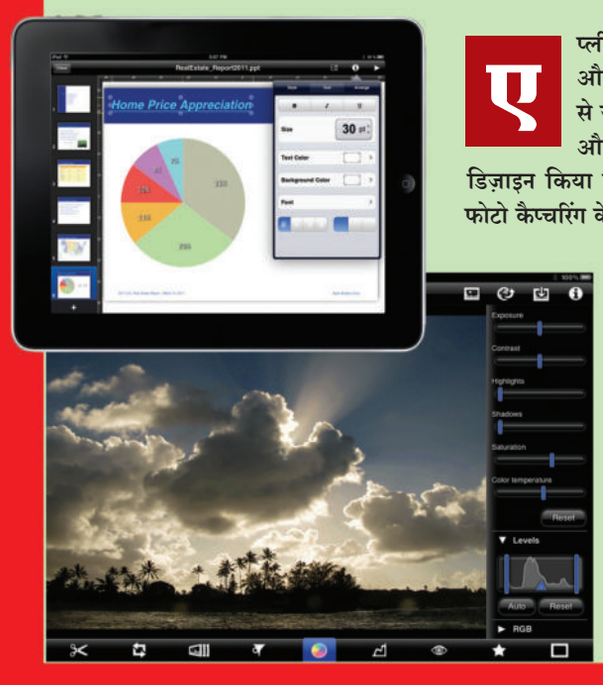

कार्बन 1818 ट्विस्टर

मध्यवर्गीय लोगों की ज़रूरतों और जेब का ख्याल रखते हुए कार्बन मोबाइल ने भारतीय बाज़ार में अपनी छवि एक अच्छे फोन निर्माता के रूप में बना ली है. कंपनी ने न सिर्फ़ फोन की डिज़ाइन पर, बल्कि गुणवत्ता पर भी काफी ध्यान दिया है. कंपनी ने इस बार भारतीय ग्राहकों के लिए अपना नया ड्यूल सिम हैंडसेट के-1818 ट्विस्टर लांच किया है. इस मोबाइल की ख़ासियत है 3.2 इंच की बड़ी सी टच स्क्रीन, जिसका रेजोल्यूशन 240/400 पिक्सल है. इस हैंडसेट में 3.2 मेगा पिक्सल का कैमरा है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है. इस फोन में आप गानों को केवल एमपी-3 फॉर्मेट में सुन सकते हैं, जबकि वीडियो का मज़ा एमपी-4, 3-जीपी और एवीआई में भी लिया जा सकता है. इसमें एफएम की सुविधा काफी बेहतरीन है, जिसकी रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है. यह मोबाइल 3-डी इंटरफेस है. हैंडसेट में पहले से ही कुछ एप्लीकेशंस मौजूद हैं, जैसे पैनोरमिक ईमेज व्यूवर. यह मॉडम को भी सपोर्ट करता है. हैंडसेट को आप किसी भी दूसरे हार्डवेयर से जोड़ सकते हैं. इसमें 1000 एमएएच लीयॉन बैट्री है. इस फोन में आप 2000 नंबर और 1000 एसएमएस सेव कर सकते हैं. इसमें 8 जीबी तक फाइल स्टोरेज की सुविधा है. इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग का शौक रखने वाले लोगों के लिए इसमें फेसबुक, ट्विटर, एमएसएन और याहू जैसी कई सुविधाएं भी हैं. यह हैंडसेट बाज़ार में मात्र 3,291 रुपये में उपलब्ध है.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

एकल्सटन इस तरह के आयोजनों को बहुत बारीकी से समझने की क्षमता रखते हैं. इससे पहले वह मलेशिया, सिंगापुर, चीन, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड में ऐसे आयोजनों को सफलता दिला चुके हैं.

BUDDH INTERNATIONAL CIRCUIT
INDIA'S RACING ARENA

भारत में पहली बार फॉर्मूला रेस

कहीं इसमें कोई ब्रेकर तो नहीं!

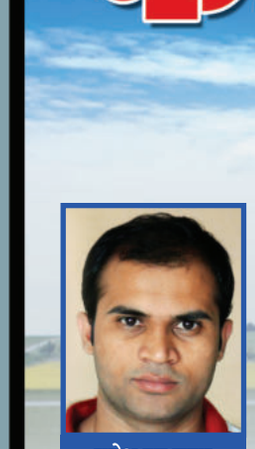

राजेश एस कुमार

आगामी 30 तारीख़ को कई भारतीय शूमाकर फॉर्मूला ट्रैक पर रेसिंग करते दिखाई देंगे. यह रेस इस बार भारतीय मेजबानी के तहत ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर होगी. यह भारत के लिए पहला मौक़ा होगा, जब इस देश में फॉर्मूला रेस होगी. ख़ैर, जब इस माह के आख़िर में ग्रेटर नोएडा के इस सर्किट में फॉर्मूला–1 कारें 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी तो हर भारतीय के चेहरे पर गौरव भरी मुस्कान ज़रूर फैलेगी. अब तक इस रेस को हम भारतीयों ने ज़्यादातर विदेशी खेल चैनलों पर ही देखा होगा और इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों में नारायण कार्तिकेयन जैसे इक्का–दुक्का रेसर को छोड़कर ज़्यादातर अंग्रेज प्रतियोगी ही दिखाई देते हैं. यह खेल उन संभ्रात खेलों में से है, जिनके लिए कहा जाता है कि इन खेलों को भारतीय अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. मसलन गोल्फ, विलियर्ड्स, फुटबॉल, आइस हॉकी वगैरह–वगैरह. लेकिन जबसे भारत में फॉर्मूला रेस के आयोजन को लेकर चर्चाएं हुई हैं, तभी से खेल जगत में इसे एक बड़े अचीवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है. यकीनन, भारत इस वक़्त स्पोर्ट्स रेवोलूशन से गुज़र रहा है. खेल जगत में जबसे ग्लैमर और पैसे का तड़का लगा है, तभी से हर बड़ा आयोजक हर खेल की कायापलट करने में लगा है. क्रिकेट के टी–20 और आईपीएल संस्करण इस बात की तस्दीक कर ही रहे हैं.

इस आयोजन का थोड़ा–बहुत श्रेय भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए) के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी को भी जाता है. ग़ौरतलब है कि उन्होंने ही भारत में फॉर्मूला–1 रेस कराने के लिए वर्ष 2007 में बर्नी एकल्सटन को आमंत्रित किया था. एकल्सटन फॉर्मूला–1 मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्य कार्याधिकारी हैं. उन्होंने भारत आकर यहां की स्थितियों का जायज़ा लिया, उसके बाद इस आयोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ी. एकल्सटन के मन मुताबिक़ ही 5.14 किलोमीटर का बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ट्रैक डिजाइन किया गया है. यह रेसिंग सर्किट ट्रैक 865 एकड़ ज़मीन पर है. इसके लिए 300 इंजीनियरों के निर्देश पर क़रीब 6000 कामगारों ने काम किया. नई दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट बनाया गया है. भारत में होने वाली पहली फॉर्मूला–1 रेस 19 रेस वाले सीजन की 17वीं रेस होगी. ग़ौरतलब है कि इस ट्रैक को जर्मन आर्किटेक्ट हेरमान टिल्के ने बनाया है.

एकल्सटन वैश्विक रुझानों की गहराइयों को बहुत बारीकी से समझने की क्षमता रखते हैं. इससे पहले वह मलेशिया, सिंगापुर, चीन, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड में ऐसे आयोजनों को सफलता दिला चुके हैं. अब देखना यह होगा कि उनका यह जादू भारत में भी चलेगा या नहीं. इतना तो तय है कि आयोजक देश को भी इससे फ़ायदे होंगे. ऑस्ट्रेलिया में एफ–1 के 10 सालों के दौरान एक अरब डॉलर का सकल आर्थिक फ़ायदा हुआ और 28,000 नौकरियों के मौक़े भी मिले. वहीं बहरीन में एफ–1 रेस पर्यटन उद्योग के लिए आमदनी के सबसे बड़े स्रोतों में शुमार है. इसलिए संभव है कि ग्रेटर नोएडा के आसपास के सभी होटल रेस के दौरान भर जाएं, लेकिन इसमें थोड़ा पेंच है. ग़ौरतलब है कि यह ट्रैक दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है. ग्रेटर नोएडा एक नया शहर है. इसलिए वहां अच्छे होटलों की संख्या ज़्यादा नहीं है. ऐसे में मेहमानों को दिल्ली में ही रुकना होगा. इस आयोजन में शामिल होने वाली सभी 12 टीमें करीब 100–100 लोगों के दल के साथ आएंगी. इसके अलावा एफ–1 से जुड़े 500 अधिकारियों और 10,000 मेहमानों के भी आने की उम्मीद है.

ज़ाहिर है, इस दौरान 11,500 कमरों की ज़रूरत होगी. अब ऐसे में समस्याओं का होना लाज़िमी है. दिल्ली से ग्रेटर नोएडा का 40 किलोमीटर का सफ़र कई बार तो दो से भी ज़्यादा घंटे में पूरा होता है, क्योंकि इस रास्ते पर ट्रैफिक की हालत बहुत ख़राब है. इसलिए मेहमानों को परेशानी हो सकती है. इसके अलावा हवाई किराए में उछाल भी एक बड़ी समस्या हो सकती है. हाल में किराए में औसतन 25 फ़ीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है. एक और विवाद सामने आया है, कस्टम विभाग और आयोजकों के बीच. सरकार और फॉर्मूला–1 रेस के आयोजकों में इस नई अनबन से आयोजन आशंकाओं में घिर गया है. कस्टम विभाग का कहना है कि फॉर्मूला–1 एयरटेल इंडियन ग्रां प्री के आयोजकों को रेस के लिए आने वाले सभी उपकरणों पर 100 प्रतिशत ड्यूटी अग्रिम चुकानी होगी. जबकि आयोजक इसमें कुछ छूट चाहते हैं. ख़ैर, यह विवाद तो हल हो जाएगा, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इस आयोजन में भी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और क्रिकेट वर्ल्डकप की तरह धन की बरसात होगी.

एक सर्वे के मुताबिक़, इस एफ–1 रेस को 50 करोड़ दर्शक सिर्फ़ टेलीविजन पर मिलेंगे. इस लिहाज़ से यह फुटबॉल वर्ल्डकप से थोड़ा ही पीछे है. क़रीब 24 एशियाई देशों में एफ–1 रेस के प्रसारण का अधिकार ईएसपीएन के पास है. ईएसपीएन के मुताबिक़, हर रेस के दौरान मिलने वाले 800 विज्ञापन सेकेंड का समय लगभग बिक चुका है. इस चैनल ने 10 सेकेंड के स्लॉट के लिए कंपनियों से 1,50,000 रुपये की दर से रकम वसूली है. हालांकि यह क्रिकेट वर्ल्डकप के फाइनल मैच के लिए 6,00,000 रुपये की दर से बेचे गए विज्ञापन स्लॉट के मुक़ाबले काफ़ी कम है, लेकिन एक लाइफ स्टाइल स्पोर्ट्स के लिए यह बुरा नहीं है. वह भी तब, जब यह अपने शुरुआती चरण में हो. कई कंपनियों ने अपने स्लॉट बुक कराए हैं. ख़ास तौर पर सोनी, सैमसंग, एमआरएफ, सेल और टाटा मोटर्स आदि के नाम शामिल हैं. चैनल को उम्मीद है कि इंडियन ग्रां प्री के दौरान दर्शकों की तादाद में कम से कम 20 फ़ीसदी इज़ाफा होगा. इसके टिकटों की कीमत 25,000 से 35,000 रुपये तक रखी गई है. बुकमाईशो डॉट कॉम के सीईओ आशीष हेमरजनी का कहना है कि उनकी वेबसाइट पर पहले 3 घंटे में ही 1.5 करोड़ रुपये के टिकट बिके. ज़्यादातर बुकिंग दिल्ली और उसके आसपास के इलाक़ों से हुई है. इसके अलावा मुंबई और चेन्नई के दर्शकों ने भी अपनी सीट बुक कराई है. अब तक करीब 2500 टिकट बेचे जा चुके हैं. अनुमान है कि टिकट से ही क़रीब 75 करोड़ रुपये की कमाई होगी. इनमें कॉरपोरेट बॉक्स भी शामिल हैं. करीब 55 कॉरपोरेट बॉक्स बनाए गए हैं और प्रत्येक की कीमत 35 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये तक है. जेपीएसआई के मुताबिक, ज़्यादातर की बुकिंग हो चुकी है. बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख ख़ान, जे के टायर और भारती एयरटेल जैसी कंपनियों ने भी बुकिंग कराई है. कुल मिलाकर इस आयोजन में कई लोगों के वारे–न्यारे होंगे.

लेकिन इन सबसे इतर एक बड़ा सवाल यह है कि भारत इस तरह के आयोजन को किस हद तक संभाल पाएगा. इससे पहले हम भारत में कई बड़े आयोजनों में घोटालों की ख़बरें सुनते आए हैं. जब कोई आयोजन इतने बड़े स्तर पर होता है, तो ज़ाहिर तौर पर ज़िम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं. इस पर देश का मान–सम्मान भी दांव पर लग जाता है. यह तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जब ऐसा आयोजन भारत में पहली बार हो रहा हो. इस फॉर्मूला रेस से भारत भी कई तरह की उम्मीदें लगाए बैठा है. जैसे खेल बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा और व्यापार बढ़ेगा, लेकिन अगर आयोजन और सुविधाओं में राष्ट्र मंडल खेलों की तरह कहीं फिर से अनियमितताओं और घोटालों की छाया पड़ी तो विश्व पटल पर भारत की एक बार फिर से भद्द पिट सकती है.

rajeshy@chauthiduniya.com

माल्या की फोर्स इंडिया का जलवा

भारत की एकमात्र फॉर्मूला वन टीम यानी उद्योगपति विजय माल्या की फोर्स इंडिया भी इस खेल में अपना जौहर दिखाएगी. 2007 में बनी यह टीम इस बार के फॉर्मूला रेस आयोजन में विजय माल्या की तरफ़ से भारत का प्रतिनिधित्व करेगी. गौरतलब है कि 29 रेसों में कोई चैंपियनशिप अंक हासिल करने में नाकाम रही फोर्स इंडिया को 2009 में उस वक़्त कामयाबी मिली थी, जब बेल्जियम की ग्रां प्री में जियानकार्लो फिजिकेला दूसरे स्थान पर आए. अभी इस टीम के चालक एड्रियन सुटिल और पॉल डी रेस्टा हैं, जबकि नीको ह्युलकेनबर्ग को अतिरिक्त चालक के तौर पर रखा गया है. फोर्स इंडिया के प्रशंसकों की तरह माल्या को भी 2009 के बेल्जियम की ग्रां प्री याद है, जब उनकी टीम ने पहले तीन में जगह बना ली थी. अब समर ब्रेक के बाद इस महीने के आख़िरी में बेल्जियम से ही फॉर्मूला वन के सीजन की शुरुआत होगी.

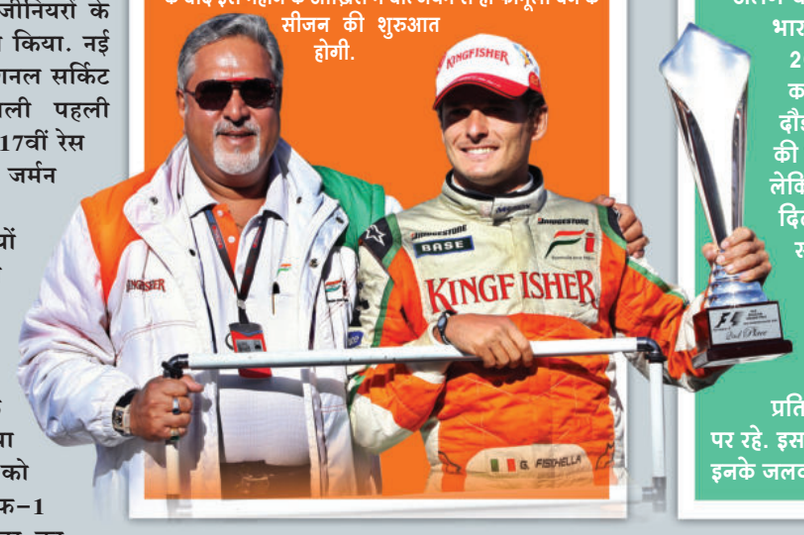

ये हैं भारत के रेसर

वैसे तो फॉर्मूला रेसिंग से भारत का कोई विशेष वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नाम हैं, जो विश्व में फॉर्मूला रेसर भारतीयों का ज़िक्र कराते रहते हैं. यह अलग बात है कि अब तक इनमें से किसी ने भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व नहीं किया. 2005 में जब भारतीय चालक नारायण कार्तिकेयन ने जॉर्डन टीम के लिए गाड़ी दौड़ाई तो भारत में लोगों का ध्यान इस खेल की तरफ गया. जॉर्डन टीम तो अब नहीं रही, लेकिन उसने भारत में फॉर्मूला वन को लेकर दिलचस्पी ज़रूर पैदा कर दी. कार्तिकेयन स्पेन की हिस्पानिया रेसिंग टीम के साथ हुए क़रार के बाद 2011 में सर्किट पर लौटे. भारतीय करुण चंढोक ने भी पिछले साल हिस्पानिया के लिए गाड़ी दौड़ाई, लेकिन वह साल भर में 12 प्रतियोगियों में 11वें स्थान पर रहे. इस बार बुद्ध सर्किट ट्रैक पर इनके जलवों का इंतजार रहेगा.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHI/2009/30467

बॉलीवुड में कपूर खानदान की कई पीढ़ियों को अपनी जगह बनाते देखा गया है. इस खानदान के कई भाई- बहनों ने अपने जलवों से जनता को कायल बनाया है.

खाने की शौक़ीन ज़रीन

बी टाउन में ज़्यादा दिनों तक न टिकने वाली अभिनेत्रियों को अक्सर देखा गया है कि वे सिल्वर स्क्रीन से ग़ायब होने के बाद बिजनेस में अपना हाथ आजमा रही हैं. उनका बिजनेस भी ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ होता है, ताकि वे इस फील्ड से भी जुड़ी रहें और उनका काम भी होता रहे. लेकिन बॉलीवुड में एक ऐसी अदाकारा हैं, जिन्होंने अपने बिजनेस के शौक को तो ज़ाहिर कर दिया है, लेकिन यह शौक है दूसरों से थोड़ा अलग. दरअसल ज़रीन ख़ान रेस्त्रां का बिजनेस करने का शौक रखती हैं, जिसे वह अपने फिल्मी करियर के साथ खड़ा करना चाहती हैं. इसीलिए वह फिल्मों और बिजनेस पर साथ-साथ ध्यान दे रही हैं. उनकी आने वाली फिल्म है साजिद नाडियाडवाला की हाउसफुल का सीक्वल हाउसफुल-2, जो 5 अप्रैल, 2012 को रिलीज होगी. यह एक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें ज़रीन ख़ान के साथ अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, रितेश देशमुख, असिन, जैकलीन फर्नांडिस, रणधीर कपूर, श्रेयस तलपड़े, बोमन ईरानी, चंकी पांडे आदि हैं. संगीत दिया है साजिद-वाजिद ने. देखने वाली बात यह होगी कि इतने सारे कलाकारों वाली इस फिल्म में दर्शक ज़रीन को कितना रिकगनाइज कर पाते हैं और इस फिल्म में उनका क्या रोल होता है. ज़रीन ख़ान खाने-पीने की शौक़ीन हैं और खिलाने की भी. दरअसल उन्हें खिलाने-पिलाने का शौक बचपन से है, जबकि उन्होंने स्वाद पहचानना सीखा था.

खुशियां बांटती रवीना

बहुत कम ऐसी अभिनेत्रियां हैं, जिन्हें हम किताबों के क़रीब पाते हैं, जिन्हें पढ़ने-लिखने में रुचि हो. जब फिल्म करने और किताब पढ़ने में किसी एक को चुनना हो तो कोई भी फिल्म यानी करियर ही चुनेगा और अपना फुल अटेंशन फिल्म को ही देगा, लेकिन रवीना टंडन थोड़ी अलग हैं. सब अपने काम के बाद किताब पढ़ने के लिए वक़्त निकालते हैं, लेकिन रवीना किताब पढ़ने के बाद काम के लिए वक़्त निकाल लेती हैं. उनके पसंदीदा लेखक हैं निकोलस स्पार्कस और उन्हें बीती ज़िंदगी के अनुभवों पर लिखी गई किताब पढ़ने में काफी दिलचस्पी है. उनका मानना है कि इससे मन प्रसन्न हो जाता है और व्यक्ति अपने आपको वास्तविकता के ज़्यादा क़रीब पाता है.

रवीना का किताबों के प्रति प्रेम इतना चर्चित हो चुका है कि अब लोग उन्हें तोहफे में भी किताबें ही देते हैं. रवीना को किताबों से जितना प्रेम है, उतना ही अपने परिवार से भी है. हाल में वह अपने बच्चों को लेकर किटेंस और पप्पीज अडेप्थन गईं, जहां लोग कुत्ते और बिल्ली के छोटे-छोटे बच्चों को गोद ले रहे थे. रवीना को वहां देखकर लोग काफी ख़ुश हुए. रवीना जल्द ही कई फिल्मों में भी नज़र आने वाली हैं. हाल में उन्होंने फिल्म थ्रिलर और अलर्ट की शूटिंग गोवा में ख़त्म की, जिसमें उनके अपोजिट संजय दत्त हैं. एक बार फिर वह कॉमेडी जॉनर की फिल्म में अपनी मौजूदगी का एहसास कराएंगी, जिसमें उनके अपोजिट अर्जुन रामपाल और इरफान ख़ान होंगे. यह मसाला फिल्म होगी. इसके अलावा वह मां-बच्चे की कहानी पर बनने वाली फिल्म मम्मा कहती हैं में भी नज़र आएंगी. कामर्शियल फिल्मों के अलावा रवीना सुदीप्तो चट्टोपाध्याय की फिल्म शोभनाज सेवन नाइट्स में भी नज़र आएंगी, जिसमें उन्होंने ऐसी महिला का किरदार निभाया है, जो एक मशहूर सोसलाइट की पत्नी होते हुए भी टॉय ब्वॉय से प्यार करती है.

दीपिका की मुश्किल

दीपिका पिछले दिनों एक मुश्किल में भी घिर गई थीं. वह अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के साथ नए घर की पार्टी में इतना मशगूल हो गईं कि उन्हें क़ानून और वक़्त का ख्याल नहीं रहा.

तमिल फिल्मों के सुपर स्टार रजनीकांत और बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की तीन भाषाओं में बनने जा रही फिल्म राणा की शूटिंग की तिथियों की घोषणा दिसंबर में की जाएगी. ग़ौरतलब है कि राणा की शूटिंग अभी स्टार्ट होने ही वाली थी कि रजनीकांत को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा. जाहिर है, अगर फिल्म सेट में रजनीकांत नहीं होंगे तो फिल्म की शूटिंग होना भी मुमकिन नहीं है. ऐसे में दीपिका अपने बिजी शेडयूल से थोड़ा फ्री हो गईं. बस इसी फ्री टाइम का फायदा उठाने के लिए दीपिका ने भी कई तरकीबें निकाल लीं. इसी तरकीब के तहत रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण ने संबंध टूटने के बाद भी दोनों ने अयान मुखर्जी की अगली फिल्म में साथ काम करने के लिए हामी भर दी. ऐन वक़्त पर जब कैटरीना फिल्म से अलग हो गईं तो दीपिका ने उनकी जगह ले ली. दीपिका पिछले दिनों एक मुश्किल में भी घिर गई थीं. वह अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के साथ नए घर की पार्टी में इतना मशगूल हो गईं कि उन्हें क़ानून और वक़्त का ख्याल नहीं रहा. देर रात तक चलने वाली पार्टी और शोरशराबे से परेशान होकर पड़ोसियों ने पुलिस को फोन कर दिया और फिर पुलिस ने पार्टी रोक दी. पार्टी में आए अभिनेता इमरान खान, उनकी पत्नी अवंतिका, विजय माल्या, अभय देओल जल्द ही वहां से चले गए. पार्टी में अमिताभ, करण जौहर, सिद्धार्थ माल्या, शाहिद कपूर, प्रियंका चोपड़ा, रितेश देशमुख, रणवीर सिंह एवं अनुष्का शर्मा आदि ने भी शिरकत की.

मोम की करीना

करीना की सफलता की दास्तां पहुंच रही है मैडम तुसाद म्यूजियम, जहां बॉलीवुड की पांच मशहूर हस्तियों के साथ मोम की करीना को भी शामिल कर लिया गया है. सिर्फ़ यही नहीं, देश के बाहर कई देशों में भी उनकी ख्याति सफर करेगी बॉलीवुड एक्जीबिशन के ज़रिए. दरअसल मैडम तुसाद म्यूजियम द्वारा बॉलीवुड हस्तियों की मोम से बनी मूर्तियां विश्व के छह शहरों में प्रदर्शित की गईं, जिनमें लंदन, हांगकांग, बैंकॉक आदि प्रमुख हैं. यह आयोजन दुनिया भर के प्रशंसकों को बॉलीवुड के क़रीब लाने के लिए किया गया है. अब करीना की इस कामयाबी पर कपूर खानदान का ख़ुश होना लाज़िमी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अपनी ख़ुशी को ज़ाहिर किया कपूर खानदान के लाडले रॉक स्टार यानी रणवीर कपूर ने. फिल्म स्टार्स भी पर्सनल और फैमिली लाइफ को उतना ही एंज्वॉय करते हैं जितना आम लोग करते हैं. बॉलीवुड में कपूर खानदान की कई पीढ़ियों को अपनी जगह बनाते देखा गया है. इस खानदान के कई भाई- बहनों ने अपने जलवों से जनता को कायल बनाया है, आने वाले दिनों में दर्शक इस परिवार से जुड़े सितारों को अपने पारिवारिक रिश्ते सिल्वर स्क्रीन पर जीते देख सकते हैं. रणवीर कपूर कहते हैं कि वह अपनी बहन करीना कपूर के साथ फिल्म करना पसंद करेंगे, लेकिन करीना रीयल लाइफ में उनकी फर्स्ट कजिन है, इसलिए वे दोनों एक-दूसरे के अपोजिट रोल नहीं कर सकते, लेकिन भाई-बहन के रिश्ते वाली बढ़िया स्क्रिप्ट पर वह काम ज़रूर करेंगे. उन्होंने कहा कि करीना ने कपूर परिवार का नाम रोशन किया है. अपने बिजी शेड्यूल की वजह से वह अपनी काबिल बहन से ज़्यादा मिल-जुल नहीं पाते, लेकिन जब भी मिलते हैं, आम भाई-बहनों की तरह एंज्वॉय करते हैं. अब रणवीर कपूर जैसे भाई हों जिस बहन के, उसके क़दम तो आसमान पर होंगे ही.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फिल्म प्रीव्यू

बी केयरफुल

यूनाइटेड कलर्स इंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी बी केयरफुल एक कॉमेडी फिल्म है, जिसके प्रोड्यूसर हैं अमृत दुजारी, राजू भाटी एवं राजेश चौराडिया और निर्देशक हैं चंद्रकांत सिंह. फिल्म में रजनीश दुग्गल, जायद खान, तनीशा मुखर्जी, किरण राठौड़, राजपाल यादव, शिल्पी शर्मा, संजय मिश्रा, असरानी, टीकू तल्सानिया, दिनेश हिंगू, हेमंत पांडे, स्नेहिल, शक्ति कपूर और जॉनी लीवर आदि कलाकार हैं. कॉमेडी ड्रामा जॉनर की इस फिल्म में ज़्यादातर कलाकार नए या वैसे हैं, जिन्हें सिल्वर स्क्रीन पर ज़्यादा नहीं देखा गया है. फिल्म की अधिकतर शूटिंग गोवा, बैंकॉक और थाइलैंड में हुई है. शूटिंग के दौरान आई ख़बरों में अभिनेत्री ट्यूलिप जोशी के ख़िलाफ़ निर्माता चंद्रकांत सिंह ने एक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन में शिकायत दर्ज कराई थी. चंद्रकांत के अनुसार, उनकी फिल्म की शूटिंग बैंकॉक में चल रही थी. ट्यूलिप वहां से बिना बिताए मुंबई लौट आईं और अपने साथ प्रोडक्शन कास्ट्यूम भी ले आईं, जिससे उन्हें काफी नुकसान पहुंचा. उस वक्त बैंकॉक में पूरी यूनिट मौजूद थी. अचानक ट्यूलिप ने अपना मन बदला, बैग पैक किया और मुंबई लौट आईं. उन्होंने इस बारे में किसी को नहीं बताया. तब ट्यूलिप की जगह शिल्पी शर्मा को लिया गया और नए कास्ट्यूम ख़रीदने पड़े. शिल्पी के अलावा साउथ ब्यूटी किरण राठौर बी केयरफुल से बॉलीवुड में क़दम रख रही हैं. फिल्म में किरण के दो अवतार हैं. पहले हाफ में वह घरेलू किस्म की लड़की के रूप में दिखाई देंगी, जबकि दूसरे में वह सुपर सेक्सी लेडी होंगी. वैसे साउथ में वह अपने सेक्सी रोल्स के लिए जानी जाती हैं. उम्मीद की जानी चाहिए कि इस सेक्सी बाला का जादू बॉलीवुड के दर्शकों पर भी चलेगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली, 17 अक्टूबर–23 अक्टूबर 2011

www.chauthiduniya.com

नदी जोड़ परियोजना

किसान ख़ुशहाल होंगे

यदि बाढ़ के पानी को संग्रहित किया जाए तो न ही पेयजल का संकट खड़ा होगा और न ही खेतों में लगी फ़सलें पानी के बिना सूखेंगी. इसके अलावा तेज़ी से नीचे जा रहे जलस्तर के गिरावट में कमी आएगी, लेकिन यह तभी संभव है जब नदियों को आपस में जोड़ने की योजना पर गंभीरता से अमल किया जाए. अगर यह परियोजना तैयार हो जाए तो बाढ़ से होने वाली भारी तबाही पर रोक लगाई जा सकती है. इस लिहाज़ से देखें तो नदी जोड़ योजना मौजूदा समय की ज़रूरत है. ख़ासकर महाराष्ट्र व विदर्भ क्षेत्र के लिए यह योजना काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है.

प्रवीण महाजन

मानसून आने के साथ ही देश में भारी बारिश और बाढ़ की ख़बरें भी आने लगती हैं. ऐसा कोई मानसून अब तक ख़ाली नहीं गया जब उस दौरान देश के किसी भाग में बाढ़ न आई हो. बाढ़ आती है तो भारी तबाही मचाती है. खेत–खलिहानों को तबाह करने के साथ ही करोड़ों रुपये की सार्वजनिक व निजी संपत्ति को नुक़सान पहुंचाती है. हज़ारों लोगों को बेघर कर देती है. सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है. इसके अलावा पर्यावरण को भी काफ़ी नुक़सान पहुंचता है और कई संक्रामक बीमारियां फैलती हैं. वहीं दूसरी तरफ़ बारिश न होने से देश के कुछ हिस्सों में सूखे या अकाल जैसे हालात बन जाते हैं. लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता और खेतों में फ़सलें सिंचाई के बिना सूख जाती हैं. इन सबके बीच अरबों घनफुट पानी बेकार चला जाता है, क्योंकि हमारे यहां पानी संग्रहण की समुचित व्यवस्था अब तक नहीं की जा सकी है. यह दृश्य महाराष्ट्र के विदर्भ इलाक़े में भी हर साल दिखाई देता है. यदि बाढ़ के पानी को संग्रहित किया जाए तो न ही पेयजल का संकट खड़ा होगा और न ही खेतों में लगी फ़सलें पानी के बिना सूखेंगी. इसके अलावा तेज़ी से नीचे जा रहे जलस्तर के गिरावट में कमी आएगी, लेकिन यह तभी संभव है जब नदियों को आपस में जोड़ने की योजना पर गंभीरता से अमल किया जाए. अगर यह परियोजना तैयार हो जाए तो बाढ़ से होने वाली भारी तबाही पर रोक लगाई जा सकती है. इस लिहाज़ से देखें तो नदी जोड़ योजना मौजूदा समय की ज़रूरत है. ख़ासकर महाराष्ट्र व विदर्भ क्षेत्र के लिए यह योजना काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है.

महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल 30,7713 किलोमीटर है. सामान्य तौर पर यहां के खोर्यों को पांच विभागों में बांटा गया है. 1. गोदावरी, 2. कृष्णा, 3. तापी, 4. नर्मदा, 5. कोंकण की पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदियां. इन खोर्यों में कुल पानी की उपलब्धता 4,646 अरब घनफुट (1,31,562 दलघमी) है. हालांकि, कई विवादों के चलते महाराष्ट्र के उपयोग में कुल 4,463 अरब घनफुट (126377 दलघमी) आता है. महाराष्ट्र में अमूमन मानसूनी बारिश 1300 मि.मी. है. राज्य में 555.75 लाख एकड़ कृषि योग्य क्षेत्र है. इसी तरह 158.90 लाख एकड़ वनक्षेत्र है. यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.91 प्रतिशत है. विदर्भ के लिहाज़ से देखें तो यहां का भौगोलिक क्षेत्रफल 97,400 चौरस किलोमीटर है. हालांकि, कई जल विवादों के बाद भी विदर्भ के हिस्से में कुल 774 अरब घनफुट (21917 दलघमी) जलसंपत्ति मौजूद है. विदर्भ में अमूमन मानसूनी बरसात 550 से 1700 मि.मी. दर्ज की जाती है. विदर्भ में 140.87 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि है और 93.13 लाख एकड़ वन क्षेत्र है. राज्य के कुल वन क्षेत्र में 58 फ़ीसदी वन परिक्षेत्र विदर्भ में ही है. पूर्व व पश्चिम विदर्भ का मौसम, खेती की ज़मीन और वहां उगाई जाने वाली अलग–अलग फ़सलों के अलावा यहां की संस्कृति में भी काफ़ी अंतर है. इसी तरह पूर्व विदर्भ में वनों का क्षेत्रफल अधिक है. यहां कृषि योग्य भूमि पश्चिम विदर्भ की अपेक्षा कम है, लेकिन इस इलाक़े में जलसंपदा अधिक है. इसके उलट पश्चिम विदर्भ में सिंचाई क्षेत्र कम है.

विदर्भ में जलसंपत्ति का नियोजन

विदर्भ में मौजूद जलसंपत्ति पर ग़ौर करें तो यह क्षेत्र गोदावरी और तापी खोर्या के बीच फैला हुआ है. एक अध्ययन के अनुसार विदर्भ में 774 अरब घनफुट पानी उपलब्ध है. भूजल सर्वेक्षण व विकास संगठन के अध्ययनों के मुताबिक़ यहां 316.7 अरब घनफुट पानी उपलब्ध है. इस प्रकार कुल 1090.7 अरब घनफुट जलसंपत्ति विदर्भ में उपलब्ध है. यहां कई निर्मित और निर्माणाधीन बिजली परियोजनाओं के लिए 563.52 अरब घनफुट पानी का नियोजन किया गया है. इसके अलावा 167.38 अरब घनफुट पानी के नियोजन करने का काम शुरू है. भूगर्भ में मौजूद पानी का 93.11 अरब घनफुट सिंचाई व 11.30 अरब घनफुट पीने के लिए उपयोग करने के पश्चात भी 212.29 अरब घनफुट पानी का नियोजन अब तक नहीं किया गया है. इसका मतलब यह है कि विदर्भ की कुल जलसंपत्ति में से 835.31 अरब घनफुट पानी का नियोजन किया गया है, जबकि 255.39 अरब घनफुट पानी का नियोजन किया जाना बाक़ी है.

गोदावरी खोरे में मुख्यत: पूर्णा (जी–3), वैनगंगा (जी–7), वर्धा (जी–8), प्राणहिता (जी–9), निम्न गोदावरी (जी–10) व इंद्रावती (जी–11) उपखोरी और इसी तरह तापी खोरे में तापी व पूर्णा उपखोरे हैं, जबकि पूर्णा, पैनगंगा, वर्धा व निम्म गोदावरी उपखोरों व तापी खोरे में उपलब्ध जलसंपत्ति का नियोजन लगभग पूरा किया जा चुका है. प्राणहिता, इंद्रावती और गोदावरी के उपखोरों का नियोजन न किए जाने से इसमें उपलब्ध पानी का उपयोग होना बाक़ी है. 167.38 अरब घनफुट पानी के नियोजन का कार्य हाथ में लिया गया है, पर वह अभी प्राथमिक अवस्था में है. इसके अलावा निर्माणाधीन परियोजनाओं में से 122 योजनाएं वन संवर्धन अधिनियम 1980 के प्रावधानों के कारण अधर में लटकी हुई हैं. इन अधूरे प्रकल्पों की सिंचाई क्षमता क़रीब 16 लाख 58 हज़ार 254 एकड़ है. पूरे विदर्भ में जलसंपत्ति की विलुप्ता के साथ ही वनक्षेत्र भी बड़ी मात्रा में होने के कारण यहां सिंचाई करना दिवास्वप्न साबित हो रहा है. गोंदिया, गढ़चिरोली और चंद्रपुर ज़िले में अधिकांश प्रकल्प वनसंवर्धन अधिनियम के कारण अटके पड़े हैं. ये सभी ज़िले अति पिछड़े हैं और यहां के लोगों की वार्षिक आय बहुत ही कम है. इस भाग में अच्छी बारिश होने के बावजूद ख़रीफ़ फ़सल के रूप में सिर्फ़ धान की खेती होती है. अगर चंद्ररुर को छोड़ दिया जाए तो किसी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना नहीं की जा सकी है. यहां के लोगों को ख़रीफ़ के चार महीनों को छोड़कर कोई काम नहीं रहता है. यानी आय के दूसरे साधन उपलब्ध नहीं हैं. इसके चलते इस क्षेत्र में नक्सलवाद पनप रहा है. वैसे देखा जाए तो इस क्षेत्र में पानी साठा निर्माण करने या बारहों माह बहने वाली वैनगंगा, प्राणहिता, वर्धा नदी पर बड़ी मात्रा में उपसा सिंचाई योजनाएं बनाने का विकल्प है. जलसाठा बनाने के लिए इस क्षेत्र के 33 प्रतिशत से अधिक हिस्से में फैले जंगल, आदिवासी जनसंख्या, आय के दूसरे साधन न होना और वन संवर्धन अधिनियम 1980 के क़ानून के प्रावधानों में छूट देने की ज़रूरत है. इतना सब करने के बाद भी विदर्भ के हिस्से की जलसंपत्ति बची रहेगी. इस बची हुई जलसंपत्ति को ध्यान में रखकर ही आंध्रप्रदेश सरकार ने प्राणहिता नदी पर चव्वेला बांध बनाने का नियोजन किया है.

सिर्फ़ केंद्र सरकार द्वारा नदी जोड़ प्रकल्प के अधीन रहने पर इस क्षेत्र का पानी दक्षिण की ओर ले जाने का नियोजन किया गया है. विदर्भ के हिस्से की इस जलसंपत्ति पर हक़ जताने की ज़रूरत है, ताकि उस पानी को विदर्भ के अन्य हिस्सों में ले जाकर उसका उपयोग किया जा सके. यदि पूरे विदर्भ की कुल कृषि भूमि पर ग़ौर करें तो इस पूरे क्षेत्र की सिंचाई के लिए क़रीब 1419.79 अरब घनफुट पानी की ज़रूरत है. इसके अलावा पीने के पानी व औद्योगिक इकाइयों की ज़रूरत पर विचार किया जाए तो यहां क़रीब 400 अरब घनफुट पानी की कमी है. इससे ज़ाहिर होता है कि यहां पानी की कमी है. दूसरी ओर पश्चिम विदर्भ पर ग़ौर करें तो यहां कम बरसात, वनसंपदा की कम, खारा पानी के बड़े भू–भाग हैं. यहां औद्योगिक विकास का घोर अभाव है. इस इलाक़े में खेती योग्य ज़मीन काफ़ी है, लेकिन सिंचाई परियोजनाओं की कमी है. एक आंकड़े के मुताबिक़ इस क्षेत्र में सिंचित खेती का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है. पूरे महाराष्ट्र की तुलना में यह क्षेत्र सिंचाई के मामले में राज्य के अन्य क्षेत्रों के मुक़ाबले काफ़ी पिछड़ा हुआ है. इस वजह से यहां की खेती पूरी तरह मानसून पर निर्भर है. यहां ख़रीफ़ की पैदावार को छोड़कर अन्य फ़सलें नहीं के बराबर होती हैं. हालांकि, एक समय में यह इलाक़ा काफ़ी संपन्न हुआ करता था, लेकिन खेती और किसानों के सामने आने वाली कई परेशानियों के चलते आज यहां के किसान बदहाल हैं. जिस तरह खेती की लागत में वृद्धि हुई, उस हिसाब से फ़सल उत्पादन में बढ़ोत्तरी नहीं हुई. नतीजतन, विदर्भ के किसानों के लिए खेती करना पूरी तरह घाटे का सौदा हो गया है. खेती के लिए लिया गया क़र्ज़ न लौटा पाने के कारण किसान आत्महत्या करने को

शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

विदर्भ में ये उपाय उपयोगी साबित हो सकते हैं

- पूर्ण हुए प्रकल्पों में मौजूद पानी का उपयोग किया जाए.
- अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग कर पानी का सही उपयोग किया जाए. इस तरह अधिक से अधिक भाग को सिंचित क्षेत्र में लाया जाए.
- भूमि के ऊपर व भूगर्भ में उपलब्ध जल का उपयोग किया जाए, ताकि ज़मीन पर उपलब्ध पानी की बचत हो सके.
- प्रकल्पों का निर्माण समय पर किया जाना चाहिए और उसके लिए समय-समय पर धनराशि उपलब्ध कराई जाए.
- वनसंवर्धन अधिनियम 1980 के अंतर्गत लंबित 35 प्रकल्पों को माव्यता मिले.
- वनसंवर्धन अधिनियम 1980 के तहत 87 प्रस्तावित प्रकल्पों को आगे बढ़ाना. जिन प्रकल्पों को मंज़ूरी नहीं मिल सकती, उनमें उपलब्ध जलसंपदा का अन्यत्र उपयोग करना.
- पूर्व विदर्भ में उपलब्ध जलसंपत्ति को पश्चिम विदर्भ की ओर मोड़ना. इसके लिए कन्हान टर्निंग योजना, गोसीखुर्द-नलगंगा टर्निंग योजना, इंद्रावती टर्निंग योजना के अध्ययन को आगे बढ़ाना.
- मध्य प्रदेश में निर्माण कराए जाने वाले जलसाठे के निर्माण का कार्य तत्काल शुरू करना होगा. विदर्भ के हिस्से में आने वाले पानी का पूरी तरह उपयोग करना चाहिए.

चौथी दुनिया

कार्यालय स्थानांतरित

साप्ताहिक चौथी दुनिया के कार्यालय का स्थानांतरण 28 सितंबर को सीताबर्डी स्थित मुरलीधर काम्प्लेक्स में हो गया है. अतः चौथी दुनिया के सभी पाठकों, एजेन्टों व हॉकरो से अनुरोध है कि वे कार्यालयीन कार्य के लिए नीचे दिए पते पर संपर्क करें–

साप्ताहिक चौथी दुनिया

आशीर्वाद पब्लिकेशन

मुरलीधर कॉम्प्लेक्स, बुटीवाड़ा के सामने, होटल गणराज के बाजू में, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी नागपुर

E-mail : chauthiduniyaa@gmail.com

सोन व देव ये दोनों नदियां बाघ वैनगंगा की उपनदियां हैं. ये दोनों नदियां मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ से आकर बाघ नदी में मिलती हैं और आगे बाघ नदी वैनगंगा नदी में आकर समाहित हो जाती है.

अस्पताल में ओवरटाइम करने वाले पुलिस जवानों को अपने स्वास्थ्य की चिंता भी सताने लगी है. आख़िर पूरे दिन रेगुलर ड्यूटी करने के बाद उन्हें अस्पताल में तैनात रहना पड़ता है.

नदी जोड़ परियोजना

किसान ख़ुशहाल होंगे

पृष्ठ संख्या 17 का शेष

मजबूर हैं. जानकारों की मानें तो जब तक इस इलाके में फ़सलों के दोबारा, तिबारा लेने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तब तक किसान क़र्ज़ से मुक्त नहीं होंगे और न ही आत्महत्या करने का सिलसिला थमेगा. इस इलाके में कुछ जलसंपत्ति है जिसका नियोजन पूर्ण होने के बाद भी कई प्रकल्पों के कार्य निर्माणाधीन हैं. निम्न पैनगंगा, जीगांव व उर्ध्वतापी टप्पा-1 जैसे बड़े प्रकल्प अभी बनकर तैयार नहीं हुए हैं. इनके बनने के बाद किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है. विदर्भ में पानी की कमी इन्हीं इलाकों में है. ऐसे में अगर पूर्व विदर्भ की वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और गोदावरी के उपखोरों में उपलब्ध पानी को गोदावरी के दूसरे उपखोरों जैसे वर्धा, पैनगंगा, पूर्णा व तापी खोरा पूर्णा में लाने से इस क्षेत्र में सिंचाई की समस्या का समाधान किया जा सकता है.

विदर्भ के नदी जोड़ प्रकल्प

देश में नदियों को जोड़ने की योजना पर काफ़ी समय से विचार किया जा रहा है. उससे विदर्भ को किसी तरह का लाभ नहीं मिलने वाला है. इसके उलट प्राणहिता नदी का पानी दक्षिण की ओर ले जाने का इरादा है.

1.गोदावरी पानी विवाद और मध्यप्रदेश से विदर्भ को मिलने वाला पानी.

अ. कन्हान प्रकल्प

वैनगंगा की उप नदी है कन्हान. यह नदी मध्यप्रदेश से महाराष्ट्र में प्रवेश करती है. महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश की सीमारेखा तक उपलब्ध जलसंपत्ति 15 अरब घनफुट पानी मानसून के जाने के बाद विदर्भ को मिलता है. इसके लिए ज़रूरी जलसाठे का निर्माण मध्यप्रदेश में महाराष्ट्र को कराना चाहिए. कन्हान नदी पर मध्यप्रदेश के जामघाट में जलसाठे का निर्माण कर उसके द्वारा 10 अरब घनफुट पानी नागपुर शहर और इस क्षेत्र के सिंचाई के लिए उपलब्ध हो सकता है. इसी तरह 5 अरब घनफुट पानी महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश सीमा पर निर्माणाधीन कोची प्रकल्प से उपसा पद्धति से उमरी व केलवद में संग्रहित कर सकते हैं और यह पानी कन्हान उपखोरा व वर्धा उपखोरे में पानी की अत्यंत कमी होने से इसका उपयोग काटोल-नरखेड़ भाग में किया जाना चाहिए. इसी माध्यम से कन्हान नदी पर जामघाट से वैनगंगा उपखोरे का पानी वर्धा उपखोरे होते हुए वेणा प्रकल्प तक ले जाया जा सकता है. इसके द्वारा नागपुर शहर की प्यास बुझाई जा सकती है. इसी तरह कोची प्रकल्प से वैनगंगा उपखोरे से पानी वर्धा उपखोरे में लाया जा सकता है.

ब. सोन नदी व देव नदी

सोन व देव ये दोनों नदियां बाघ वैनगंगा की उपनदियां हैं. ये दोनों नदियां मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ से आकर बाघ नदी में मिलती हैं और आगे बाघ नदी वैनगंगा नदी में आकर समाहित हो जाती है. इन दोनों नदियों पर महाराष्ट्र सरकार जलसाठा निर्माण कर मानसून के दरम्यान 15 अरब घन फुट पानी वैनगंगा से धापेवाड़ा बैरेज में लाया जा सकेगा. धापेवाड़ा बैरेज से उपसा पद्धति द्वारा भंडारा व गोंदिया ज़िले के क़रीब 1,87,720 एकड़ क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराया जा सकता है. इस योजना से संपूर्ण भंडारा व गोंदिया ज़िले के सभी भागों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना ज़रूरी है.

स. उर्ध्वतापी टप्पा-1

महाराष्ट्र के अमरावती व मध्यप्रदेश के बुरहानपुर ज़िले की सीमा पर प्रवाहित होने वाली तापी नदी पर धारणी के पास खाटियाधुटी घाट पर जलसाठा निर्माण करने और उसमें संग्रहित होने वाले पानी का दोनों राज्यों द्वारा उपयोग किए जाने की योजना है, लेकिन इस योजना के डूबित क्षेत्र में मेलघाट बाघ प्रकल्प के आने से अब बांध स्थल को और नीचे ले जाने की योजना है. पहले के प्रस्ताव में पूरा पानी विदर्भ व मध्यप्रदेश के मध्य बंटना था, लेकिन इस योजना से विदर्भ को ख़ास फ़ायदा होता नहीं दिख रहा है. इस योजना से सबसे अधिक लाभ खानदेश को मिलेगा. हालांकि डूबित क्षेत्र के लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं. इस दौरान तापी नदी का पानी पूर्णा उपखोरे में लाने का अध्ययन किया जा रहा है. मगर इस खोरे से महाराष्ट्र के हिस्से में ज़रूरत से कम पानी मिलने की संभावना है.

2. वैनगंगा/इंद्रावती का पानी वर्धा, पैनगंगा और गोदावरी व पूर्णा का पानी तापी खोरा से मिलाना

अ. वैनगंगा-नलगंगा टर्निंग योजना

वैनगंगा नदी पर गोसीखुर्द प्रकल्प का निर्माण कार्य शुरू है. नहरों और पुनर्वास का काम क़रीब-क़रीब पूरा हो गया है. इस प्रकल्प से उपलब्ध होने वाली कुल जलसंपत्ति में क़रीब 2721 दलघमी पानी बक़ाया है. अगर इस पानी को सीधे नदी में छोड़ें तो उस पर महाराष्ट्र-विदर्भ का हक़ पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा. इन हालात में यहां बचे पानी को उपसा पद्धति से लेकर गोदावरी खोरा से वर्धा उपखोरे व तापी खोरे से पूर्णा उपखोरे में पहुंचाना चाहिए. इसके मद्देनज़र यह पानी वैनगंगा से लेकर 478 किमी दूर बुलढाणा ज़िले की नलगंगा तक पहुंचेगी. इससे क़रीब 10 लाख 21 हज़ार 962 एकड़ कृषि क्षेत्र को लाभ मिलेगा. यह प्रकल्प कार्यान्वित होने पर महाराष्ट्र में सबसे अधिक सिंचन क्षेत्र वाला प्रकल्प हो जाएगा यानी पश्चिम विदर्भ में सिंचाई का अनुशेष दूर करने में बड़ी मदद मिलेगी. यह संभव है, पर इसके लिए राजनीतिक व प्रशासकीय इच्छाशक्ति की ज़रूरत है.

ब. इंद्रावती टर्निंग योजना

गोदावरी खोरा व इंद्रावती उपखोरे से विदर्भ के हिस्से में 41 अरब घनफुट जलसंपदा उपलब्ध है, लेकिन इस उपखोरे के अंतरराज्यीय होने से भोपालपट्टम के साथ अन्य जलविद्युत परियोजनाओं के इस भाग (गढ़चिरोली ज़िला) में वनसंपदा, अभ्यारण्य आदि होने के कारण इसका कार्य हाथ में लेना मुश्किल है. जिस खोरे में ज़्यादा पानी है, उसका पानी कम जलसंपदा वाले खोरे में लाकर किसानों को उपलब्ध कराया जा सकेगा.

नामंज़ूर प्रकल्पों की जलसंपत्ति का उपयोग

गोदावरी जल विवाद के मद्देनज़र प्रस्तावित प्रकल्पों के रुके रहने तक वहां उपलब्ध पूरे पानी का उपयोग करने का अधिकार महाराष्ट्र -विदर्भ को है. इस तरह के प्रकल्पों में वैनगंगा/प्राणहिता उपखोरा में आसोलामेंढा, घोड़ाझरी व नलेश्वर ब्रिटिश काल में पूर्ण हो गए थे. इसके बाद गोसीखुर्द व निम्न चुलबंद प्रकल्प का निर्माण कार्य प्रगति पर है. इसी तरह चंद्रपुर ज़िले के हुमन प्रकल्प वन विभाग से मंज़ूरी मिलने के बाद भी एनपीवी व पर्यायी वन लगाने के लिए निधि उपलब्ध न हो पाने से आज तक अटका हुआ है. इसी तरह चंद्रपुर ज़िले के ही बुटीनाला व गराडी प्रकल्प का पुनः नियोजन किया जा रहा है. इसी ज़िले के निंबुघाट प्रकल्प डूबित क्षेत्र में वनसंपदा होने के कारण रुका हुआ है. इस प्रकल्प से लाभांवित होने वाले क्षेत्र को अब गोसीखुर्द प्रकल्प से भी लाभ होगा. ऐसे में निंबुघाट के पानी का उपयोग कहां किया जाए इस पर विचार करना होगा. चंद्रपुर ज़िले के अंधारी व गढ़चिरोली ज़िले के तुलतुली प्रकल्प के प्रस्ताव को केंद्र सरकार के वन व पर्यावरण मंत्रालय ने नामंज़ूर कर दिया है. इसी तरह गढ़चिरोली ज़िले के खोब्रागड़ी, सती, पोहार, चेन्ना, कारवाफा प्रकल्प वनसंवर्धन अधिनियम 1980 के तहत लंबे समय से अटके हुए हैं. भविष्य में इनका कार्य कब शुरू होगा, यह कहना मुश्किल है. विदर्भ में इस तरह कई कारणों से अधर में लटके प्रकल्पों की संख्या 87 है. इनसे क़रीब 29911 एकड़ वनक्षेत्र प्रभावित हो रहा है. दूसरी ओर विदर्भ में 92,13,100 एकड़ वन परिक्षेत्र है जिसका प्रकल्प क्षेत्र में आने वाले जंगल मात्र 0.32 प्रतिशत है. वनों के कारण रुके पड़े प्रकल्पों की सिंचाई क्षमता 5,21,920 एकड़ है. इन रुके हुए प्रकल्पों को यदि प्रभावित वन परिक्षेत्र उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी इस प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की 38.27 प्रतिशत वनसंपदा बचती है, जो 33 प्रतिशत वनक्षेत्र से अधिक है. इसके अलावा 35 प्रकल्पों को केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय से कुछ शर्तों के साथ मंज़ूरी मिलने से 11,36,333 एकड़ क्षेत्र को सिंचाई का लाभ होने की संभावना है. इनमें यवतमाल ज़िले का निम्न पैनगंगा, बुलढाणा ज़िले का जीगांव, वर्धा ज़िले का आजनसरा और चंद्रपुर ज़िले का हुमन प्रकल्प शामिल हैं. इन बड़े प्रकल्पों की सिंचाई क्षमता 9,84,235 एकड़ है. ऐसे हालात में यहां कार्य तत्काल शुरू किया जाना चाहिए. इसके लिए धनराशि उपलब्ध कराना राज्य व केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है.

feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र व विदर्भ की तुलना

अनु क्र.	विवरण का प्रतिशत	महाराष्ट्र	विदर्भ	महाराष्ट्र से विदर्भ
1	भौगोलिक क्षेत्र लाख हेक्टेयर	307.713	97.400	31.65
2	खेती योग्य क्षेत्र लाख हेक्टेयर	225.000	57.034	25.35
3	वन क्षेत्र लाख हेक्टेयर	64.335	37.300	57.98
4	जनसंख्या (2001) करोड़	9.69	2.06	21.26
5	मानसूनी बारिश	500 से 3000	550 से 1700	
6	पानी की उपलब्धता अ.घ.फू.			
अ)	गोदावरी	1317.25	677.75	51.45
ब)	कृष्णा	1001.92	-	-
क)	तापी	246.39	96.00	38.96
ड)	नर्मदा	11.12	-	-
ई)	कोंकण की पश्चिमी नदियां	2069.42	-	-
	कुल पानी की उपलब्धता अ.घ.फू.	4646.10	773.75	16.65
7	जनसंख्या के प्रमाण में प्रति दिन पानी की उपलब्धता घ.मी./व्यक्ति	1357.7 घ.मी.	1063.9 घ.मी.	78.36
8	निर्माण हुआ जलसाठा अ.घ.फू.	1172.85	267.79	22.83
9	निर्माण सिंचाई क्षमता लाख हेक्टेयर (स्थानीय स्तर छोड़कर)	46.30	10.60	22.89
10	प्रत्यक्ष निर्माण हुआ सिंचाई (लाख हेक्टेयर) जून 2009 अखेर	25.42	4.31	16.96
11	प्रत्यक्ष सिंचाई की निर्मित सिंचाई क्षमता प्रतिशत में	54.90	40.66	
12	सभी प्रकल्प द्वारा (भविष्य में) निर्माण होने वाली सिंचाई क्षमता (लाख हेक्टेयर में)	126.00	36.73	29.15
13	प्रति हेक्टर पानी की उपलब्धता घ.मी./हेक्टर	4275 घ.मी.	2250 घ.मी.	52.64

कांग्रेस में वंशवाद हावी

युधिष्ठिर जोशी

कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी भाई-भतीजावाद के चक्रव्यूह से युवा कांग्रेस को निजात दिलाने के लिए प्रयासरत हैं. इसके लिए राहुल गांधी का अभिनंदन किया ही जाना चाहिए, लेकिन उनके इस प्रयत्न में महाराष्ट्र के प्रभावशाली नेता गले की फांस बन गए हैं. राहुल गांधी ने जो प्रयत्न किया है उसे एक रोचक नाटकीय घटना ही कहना उचित रहेगा. भाई-भतीजावाद का जाल जानबूझकर उन्हीं के पूर्वजों ने बुना है. राहुल के परनाना और इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में उनके जो सहयोगी थे, वे उनके जैसे ही कर्तव्यमान, त्यागी और निरपेक्ष रूप से देश प्रेमी थे. उस समय में पंडित नेहरू के जितने सहयोगी थे उनमें से अधिकांश एक को छुपाओ और दूसरे को सामने लाओ के सिद्धांत को तवज्जो देते थे. इसी वजह से वह खुलकर कभी इंदिरा गांधी को सामने नहीं लाए. देश की भावी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम के उच्चारण को कटाक्ष मान कर टाल देते थे. फिर भी नेहरू के मन की भावना दब नहीं रही थी. लालबहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी ही देश की प्रधानमंत्री बनी थीं. पंडित नेहरू के समान इंदिरा गांधी ने कभी भी लुकाछुपी का खेल नहीं खेला था. इंदिरा गांधी के बहुत से सहयोगी नेहरू के साथ काम करने वाले थे. उम्र में और अनुभव से भी बड़े थे. इसी वजह से इंदिरा गांधी को प्रारंभ में पार्टी के कामकाज में अड़चनों का सामना करना पड़ा था. इसलिए ख़ुद उनको कांग्रेस पार्टी को विभाजित करने की योजना बनानी पड़ी और पार्टी तोड़ने का खेल खेलना पड़ा. पार्टी के विभाजित होने के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस में लोकशाही प्रक्रिया को ख़त्म करने की नीति पर अमल किया. गांधी परिवार के बिना कांग्रेस पार्टी में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है. यह मानसिकता पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं में योजनबद्ध तरीक़े से पैदा की गई. प्रादेशिक नेतृत्व को अप्रत्यक्ष रूप से ख़त्म कर दिया गया. पार्टी के पदाधिकारियों को चुनने के लिए होने वाले चुनाव बंद हो गए थे. प्रदेशाध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्यों का चयन हाईकमान की अनुमति के बिना होना बंद कर दिया गया था. सभी अधिकार हाईकमान के पास केंद्रीभूत होने से कांग्रेस पार्टी अपाहिज-सी हो गई थी.

इंदिरा गांधी ने सबसे पहले संजय गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी को अपना उत्तराधिकारी प्रचारित किया. इसी वजह से इंदिरा गांधी की आकस्मिक मृत्यु के बाद मंत्रिमंडल के किसी भी वरिष्ठ सहयोगी को प्रधानमंत्री पद की शपथ न दिलाते हुए राजीव गांधी को शपथ दिलाई गई थी. उन्हीं के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा गया. राजीव गांधी ही कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा बन गए. राजीव गांधी की मौत के बाद पार्टी में काफी परिवर्तन देखने को मिलाा. प्रधानमंत्री पद पर नरसिंहराव की ताजपोशी की गई, लेकिन पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण नेता सोनिया गांधी ही बनी रहीं. वह पार्टी की सर्वेसर्वा हो गईं. उसके बाद कांग्रेस पार्टी नेताओं की नज़र सोनिया की पुत्री प्रियंका और पुत्र राहुल गांधी पर जाकर टिकी. हालांकि मौजूदा समय राहुल गांधी को कांग्रेस के सर्वेसर्वा के रूप में देखा जाने लगा है. वैसे भी राहुल गांधी पार्टी के महासचिव हैं. युवा कांग्रेस के वे कर्ताधर्ता ही हैं.

कांग्रेस पार्टी के इतिहास का जिक्र करने के पीछे क्या कारण है? इस तरह का प्रश्न पाठकों के मन में उठ रहा होगा. इसका कारण यह है कि युवा कांग्रेस में व्याप्त भाई-भतीजावाद बंद हो, नये ख़ून और नये नेतृत्व को अवसर मिले. देश में चुनाव निष्पक्ष हों इसके लिए भारत के पर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जे.एम लिंग्दोह को युवक कांग्रेस के चुनाव की ज़िम्मेदारी सौंपी गई. इसके पीछे राहुल गांधी की मंशा निश्चित रूप से अच्छी थी. पार्टी में नये चेहरों को आगे लाने के लिए भाई-भतीजावाद को ख़त्म करना अति आवश्यक है. राहुल गांधी के इस प्रयास की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है, लेकिन गांधी परिवार ने पिछले चालीस साल से जो बोया वही काट रहा है. महाराष्ट्र युवक कांग्रेस का चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ है. चुनाव में युवक कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए विश्वजीत क़दम और उपाध्यक्ष सत्यजीत तांबे चुने गए. विश्वजीत क़दम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वनमंत्री पतंगराव क़दम के सुपुत्र हैं, तो सत्यजीत तांबे राज्य के महसूल मंत्री बालासाहब थोराट के भांजे हैं. अध्यक्ष पद के चुनाव में राज्य के रोज़गार गारंटी योजना मंत्री नितिन राउत के पुत्र कुणाल और चंद्रपुर के पूर्व सांसद नरेश पुगलिया के पुत्र राहुल भी मैदान में उतरे थे. वहीं प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे के पुत्र को भी यवतमाल ज़िला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुना गया हैं. वर्धा के सांसद व पूर्वमंत्री दत्ता मेघे के पुत्र समीर मेघे नागपुर के अध्यक्ष बने हैं. संजय दत्त, विधायक ठाकुर दशरथ भगत, रामप्रसाद बोर्डीकर, रजनी पाटिल, कादिर बापू पाटिल इन सभी के सुपुत्र युवक कांग्रेस के चुनाव में विजयी हुए हैं. इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी के इरादे पर महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेताओं ने पूरी तरह पानी फेर दिया. किस तरह एक बार सत्ता और अधिकार मिलने पर उनकी कई पीढ़ियां बदल जाती इसे मौजूदा राजनीति में देखा जा सकता है. राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण भी पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रेमलाबाई चव्हाण के पुत्र हैं. वहीं दूसरी तरफ़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी परिवारशाही चरम पर है. पार्टी अध्यक्ष शरद पवार की सुपुत्री सुप्रिया सुले और भतीजा अजीत पवार राज्य में पार्टी की कमान संभाले हुए हैं. अजीत दादा तो पूरी तरह से राकांपा को अपनी अपनी मुट्ठी में रखा है. उनके इशारों के बिना पार्टी का पत्ता भी नहीं हिलता है. मंत्री गणेश नाईक के पुत्र सांसद तो भतीजा नई मुंबई के महापौर है. उसी तरह मंत्री छगन भुजबल का भतीजा सांसद तो पुत्र विधायक हैं. राकांपा में परिवारशाही की परंपरा हर जगह देखने को मिलती है. दरअसल, राजनीति में वंश परंपरा की दीक्षा कांग्रेस पार्टी ने ही सभी नेताओं को दी है. उसी के रास्ते पर भाजपा, अकाली दल, मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी, द्रमुक, आरपीआई, शिवसेना जैसे दल उसका अनुकरण कर रहे हैं. इन परिस्थितियों में राजनीतिक पार्टियों में नया ख़ून आयेगा कहां से?

feedback@chauthiduniya.com

पोषण आहार वितरण में राजनीति

अजंता भौमिक

जनहित की योजनाएं विफल की जाती हैं या हो जाती हैं? इस सवाल का जबाव हर व्यक्ति का अलग-अलग हो सकता है. मगर एक बात कॉमन होती है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण हर योजना भ्रष्टाचार के भंवर में फंस जाता है और यह तो कड़वी सच्चाई है कि जिस योजना के क्रियान्वयन में राजनीति आड़े आने लगी उसका बेड़ा गर्क होना तय माना जाता है. महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों, गर्भवती महिलाओं व कुपोषित बच्चों को वितरित किये जाने वाले पोषण आहार के मामले में भी राजनीति आड़े आने लगी है. इस बार पोषण आहार वितरण में राजनीतिक ग्रहण लगाने का कार्य हो रहा है.

ग़ौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद राज्य में पिछले 6 माह से तीन साल के उम्र के क़रीब 40 लाख बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और ग्रेड तीन व चार के कुपोषित बच्चों के लिए टेक होम योजना शुरू है. योजना के तहत राज्य के सभी बच्चों, गर्भवती महिलाओं व कुपोषित बच्चों को पौष्टिक आहार की आपूर्ति किया जाना अनिवार्य है, लेकिन कुछ विधायकों द्वारा पौष्टिक आहार आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों का पक्ष लेकर योजना के क्रियान्वयन में हस्तक्षेप करने से महिला व बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों में निराशा व्याप्त है. वहीं इस मामले में विधानसभा में विपक्ष के नेता एकनाथ खड़से ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को पत्र लिख कर कहा है कि कुछ ठेकेदार राजनेताओं का वरदहस्त प्राप्त कर अनुबंधकर्ताओं के हित में योजना को बंद करवाने का प्रयास कर रहे हैं. इसलिए पूरे मामले की जांच कराई जानी चाहिए. विशेष बात यह है कि टेक होम योजना को उच्चतम न्यायालय के आदेश पर केंद्र सरकार ने पौष्टिक आहार वितरण से जुड़ी विविध सामाजिक संस्थाओं और खड़गपुर आईआईटी के विशेषज्ञों के सहयोग से तैयार की है. योजना में पौष्टिक आहार के तौर पर उपमा, हलवा, कांजी आदि खाद्य पदार्थ तैयार कर एयरप्रूफ पैकेट में बंद कर देने का नियम है. इस योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को सीधे उनके घर पर जाकर पौष्टिक आहार देने का नियम है, ताकि वे अपनी सुविधा के अनुसार पका कर उसका सेवन कर सकें. इस योजना से राज्य में स्थित 94 हज़ार आंगनवाड़ियों में आने वाले तक़रीबन 40 लाख बच्चों सहित गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और अन्य ग़रीब बच्चों के लाभान्वित होने की संभावना थी, जो पौष्टिक आहार के अभाव में कुपोषण की चपेट में आ जाते हैं. इस संबंध में बताया जाता है कि ठेकेदारों के फ़ायदे के लिए योजना के तहत पौष्टिक आहार के लिए मंगाई गई निविदा में दिए गए नियमों और शर्तों को हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दाख़िल की गई थी, लेकिन न्यायालय ने उक्त याचिका को ठुकरा दिया. इसके बाद भी मनसे के दो विधायक इस योजना में तरह-तरह की खामियां बता कर अडंगे डाल रहे हैं.

अब सवाल यह है कि योजना राज्य के अत्यंत ग़रीब बच्चों और महिलाओं के हित में चलाई जा रही है. इसमें किसी जनप्रतिनिधि को क्या एतराज हो सकता है, लेकिन यहां मामला कुछ और है. यहां पौष्टिक आहार की आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों के हितों को संरक्षण देने की है. इस योजना से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि कभी-कभार ही कोई अच्छी योजना आती है. टेक होम योजना ग़रीबों के लिए एक अच्छी योजना है. इसका क्रियान्वयन भी न्यायालय के निदेर्शों के मद्देनजर भली-भांति तरीक़े से किया जा रहा है. लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि विधायक योजना की खामियों को दूर करने के लिए सुझाव देने की बजाय उसे बंद कराना चाहते हैं इसलिए वे अड़ंगे डाल रहे हैं. इस मामले में भाजपा नेता एकनाथ खड़से का कहना है कि इस तरह ठेकेदार और कुछ नेता मिलकर इस योजना को ही बंद कराना चाहते हैं. विधायकों को यह समझना चाहिए कि इस योजना से लाखों ग़रीब बच्चे, गर्भवती महिलाएं और कुपोषित लोगों के स्वास्थ्य प्रभावित होंगे. हां, यदि कहीं भ्रष्टाचार का मामला आता है तो हम उनका साथ देंगे, लेकिन योजना के क्रियान्वयन में किसी तरह की बाधा डालना उचित नहीं है. उन्हें ठेकेदारों के हितों को चिंता छोड़कर उन ग़रीबों की चिन्ता करनी चाहिए जिनके लिए यह योजना बनी है. उसकी खामियों को दूर करने की ओर ध्यान देना चाहिए न कि योजना को ही बंद कराने की कोशिश करनी चाहिए. विधायकों के अनावश्यक हस्तक्षेप से महिला बाल कल्याण विभाग के अधिकारी भी नाराज़ हैं. अब यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह ग़रीबों के हित में संचालित इस योजना को बग़ैर किसी अवरोध के कैसे संचालित करती है.

feedback@chauthiduniya.com

सुनहरा अवसर

चौथी दुनिया

पत्रकारिता में रूचि रखने वालों के लिए 'साप्ताहिक चौथी दुनिया' से जुड़ने का सुनहरा अवसर

1– वार्ड प्रतिनिधि : नागपुर के सभी वार्डों के लिए

2– कॉलेज प्रतिनिधि : नागपुर के सभी कॉलेज के लिए

वार्ड व कॉलेज प्रतिनिधि बनने के उम्मीदवार अपने बायोडाटा व दो पासपोर्ट फोटो के साथ आवेदन कर सकते हैं.

संपर्क साप्ताहिक चौथी दुनिया

आशीर्वाद पब्लिकेशन

मुरलीधर कॉम्प्लेक्स, बुटीवाड़ा के सामने, होटल गणराज के बाजू में, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी नागपुर

E-mail : chauthiduniyaa@gmail.com

चाहे जनता भाड़ में जाए

आबा के गृह मंत्रालय के मातहत आने वाला पुलिस विभाग में कुछ भी हो सकता है. आख़िर जनाब आबा जो ठहरे आबा पाटिल. अपनी भले मानुष की छवि को बनाए रखने के लिए वे हर जतन करते हैं पर उनके मातहत आने वाले विभाग के कर्ताधर्ता जब-तब ऐसा कुछ कर बैठते हैं कि लोगों को उलाहना देने का अवसर मिल जाता है. अब इसके लिए बेचारे आबा जी क्या कर सकते हैं. आलम यह है कि जिस पुलिस महकमे पर राज्य के जानमाल की ज़िम्मेदारी है, वह नेताओं और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के रिश्तेदार की सुरक्षा में तैनात है. हाल में एक वाकया ऐसा ही सामने आया है. एक वरिष्ठ आईपीएस ने मुंबई इलाज कराने आए अपने ससुर जी की सेवा में सुरक्षा के नाम पर पूरी पुलिस टीम ही लगा दी है. भई, ससुर की सेवा करने का अवसर कम ही लोगों को मिलता है. ससुर की सेवा में अपने पद का इस्तेमाल न करेंगे तो कब करेंगे? जनता का क्या है? सवा अरब की आबादी में अगर किसी हादसे में 10-20 हलाक भी हो गए तो क्या फ़र्क़ पड़ता है? आख़िर कोई पहाड़ तो नहीं टूट पड़ेगा, लेकिन ससुर तो एक ही है, इसलिए पहले उनकी सुरक्षा करना पहली प्राथमिकता है. जनता जाए भाड़ में, हमें क्या पड़ी है. उसकी सेवा के लिए तो हम हमेशा ही किया करते हैं. ससुर की सेवा का अवसर तो भाग्यशाली दामाद को ही मिलता है. इसलिए तो पुलिस वायरलेस विभाग के आईजी आर.के. सहाय ने अपने ससुर केशव प्रसाद के कैंसर अस्पताल टाटा मेमोरियल में भर्ती होते ही न केवल उनके वीआईपी उपचार की व्यवस्था की, बल्कि उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतज़ाम भी किया है. उन्होंने अपने ससुरजी की सुरक्षा में 15 पुलिस वालों का एक दल 24 घंटे की ड्यूटी पर टाटा मेमोरियल अस्पताल में तैनात किया है. यहां तैनात जवानों में दो पुलिस उपनिरीक्षक भी शामिल हैं. तैनात पुलिस दल को अस्पताल में आने-जाने वाले लोग जिज्ञासु नज़र से देखते हैं. इसकी वजह यह है कि अस्पताल में कभी भी किसी मरीज की इतनी सख्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं देखी गई थी, लेकिन जब दामाद हो थानेदार तो उसका रंग भला कैसे न दिखे. शायद यही वजह है कि ससुर की सेवा-सुरक्षा में पुलिस तैनाती की अधिकृत अनुमति न लेने के बाद भी आई.जी. सहाय अपने पद के रुतबे का उपयोग सभी नियम-क़ायदे को ताक पर रख कर किया है. गृह मंत्रालय तो पहले से ही सुस्त रवैया अपना रहा है. यहां तैनात पुलिस जवानों का भी अपना दर्द है. उनका दर्द यह है कि सामान्य ड्यूटी करने के उपरांत उन्हें आई.जी. सहाय के निर्देश में अस्पताल में ओवरटाइम करना पड़ रहा है. इसके अलावा पुलिस जवान को सहाय के ससुर के लिए दवाइयां लाने, समय पर भोजन देने, दवाइयां खिलाने से लेकर पूरी तीमारदारी करनी पड़ रही हैं. अस्पताल में ओवरटाइम करने वाले पुलिस जवानों को अपने स्वास्थ्य की चिंता भी सताने लगी है. आख़िर पूरे दिन रेगुलर ड्यूटी करने के बाद उन्हें अस्पताल में तैनात रहना पड़ता है. इसके चलते न समय पर खाना खा पाते हैं और न सो पाते हैं जिसका उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ना स्वाभाविक है. इन परिस्थितियों में तो अपने गृहमंत्री आर.आर. पाटिल उर्फ आबा ही बता सकते हैं कि उनके राज में यह क्या हो रहा है? जनता के जानमाल की सुरक्षा में तैनात होने वाले पुलिस दल को कोई आईपीएस कैसे मनमाना उपयोग कर सकता है? किस नियम-क़ायदे के तहत ससुर की सुरक्षा में पुलिस बल को सहाय ने टाटा मेमोरियल हास्पिटल में तैनात किया है? ओवर टाइम करने पर पुलिस दल के जवानों को जो वेतन दी जाएगी उसका भुगतान क्या सहाय अपनी जेब से करेंगे? आबा साहब क्या राज्य की सुरक्षा कर सकेंगे आप? आपका का डर तो आपके मातहत विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को भी नहीं है. वे तो पुलिस जवानों को अपने नौकर की तरह उपयोग करते हैं. क्या ऐसे ही अधिकारियों के बल पर राज्य की सुरक्षा हो सकेगी? यह विचारणीय सवाल है. इस सवाल पर ग़ौर कीजिए और मंथन करें कि क्यों आपको गृहमंत्रालय में अयोग्य कहा जा रहा है?

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र हलचल

पुणे स्थित श्री गणेश कला क्रीड़ा मंच द्वारा आयोजित वनराई महोत्सव में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह उपस्थित लोगों का अभिवादन करते हुए. उनके साथ हैं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और वनराई के अध्यक्ष पद्मभूषण डॉ. मोहन धारिया व अन्य.

खड़कवासला उपचुनाव में भाजपा-शिवसेना-आरपीआई के संयुक्त उम्मीदवार भीमराव तापकीर के समर्थन में पत्रकारों को संबोधित करतीं शिवसेना विधायक नीलमताई गोन्हे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार, महासचिव विनोद तावड़े व अन्य.

मुंबई स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित करते पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, कांग्रेस सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दायमा, पूर्व मंत्री शोभा बच्छाव व अन्य कांग्रेसी नेता.

पुसद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए. उनके साथ हैं पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मधुकरराव पिचड़, मंत्री मनोहर नाईक, विधायक संदीप बाजोरिया व अन्य राकांपा कार्यकर्ता.

नागपुर स्थित साईं सभागृह में वरिष्ठ विचारक भा.ल. भोले की स्मृति में व्याख्यानमाला को संबोधित करते दिव्य भास्कर के संपादक कुमार केतकर और मंच पर आसीन भास्कर समूह के संपादक प्रकाश दुबे.

राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर में मौलाना अब्दुल करीम पारेख स्मृति व्याख्यानमाला को संबोधित करते राज्यसभा के उप सभापति के. रहमान और मंच पर आसीन अन्य वक्तागण.

केंद्रीय मंत्री जी.के वासन को अपने बांद्रा स्थित आवास पर गणपति की मूर्ति भेंट करते मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह व श्रीमती मालती देवी सिंह.

Postal Regn. No. RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 17 अक्टूबर–23 अक्टूबर 2011

महाराष्ट्र के गृहमंत्री नक्सली आंदोलन को रोक पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं. नक्सली गुट सुनियोजित हमले कर पुलिस व आदिवासियों की हत्या कर रहे हैं.

गढ़चिरोली में नक्सलियों का क़हर

काग़ज़ी साबित हुआ एक्शन प्लान

भारत की आंतरिक सुरक्षा दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है. उसे सुधारने के लिए हम चरणबद्ध तरीक़े से प्रयत्न कर रहे हैं. कुछ ऐसा ही कहना है भारत के गृहमंत्री पी. चिदंबरम का. उन्होंने स्वीकार किया है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा ख़तरे में है. चिदंबरम साहब की मानें तो देश को सीमा पार से हो रहे आतंकवादी हमलों से ज़्यादा ख़तरा नक्सलियों से है. हालांकि गृहमंत्री की अपनी दलील है, लेकिन मौजूदा समय में आतंकवाद और नक्सलवाद के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने जो नीति बनाई है वह पूरी तरह दोषपूर्ण है. नतीज़तन नक्सलवाद ख़त्म होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है. सरकार नक्सलवाद को बलपूर्वक ख़त्म करना चाहती है, जबकि होना यह चाहिए कि नक्सलवाद पनपने की मूल वजह को तलाशा जाए और उसका समाधान बंदूकों के सहारे न करके सामाजिक स्तर पर किया जाए. आख़िर क्या वजह है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में वर्ष 1990 के बाद नक्सलवादी गतिविधियों में तेजी आई. वामपंथी उग्रवाद पनपने की मूल वजह जल, जंगल और ज़मीन है. इसके अलावा बेरोज़गारी, आर्थिक असमानता और सामाजिक ग़ैर-बराबरी ने इसे फलने-फूलने के लिए भरपूर मौक़ा दिया, लेकिन सरकार इसकी पड़ताल करने की बजाय पूरी हिकमत के साथ उसे कुचलना चाहती है. केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित महाराष्ट्र के गढ़चिरोली और गोंदिया, आंध्रप्रदेश के दो जिले, बिहार के सात जिले, छत्तीसगढ़ के दस जिले, झारखंड के चौदह जिले, मध्यप्रदेश के आठ जिले, उड़ीसा के पंद्रह जिले और पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में एक एक्शन प्लान बनाया है. इसके तहत सरकार ने वर्ष 2010-11 में सभी जिलों को को 25 करोड़ रुपये दिए हैं, ताकि नक्सल प्रभावित इन राज्यों में उग्रवादियों से निपटा जा सके.

ग़ौरतलब है कि हर साल राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रदेश के पुलिस महानिदेशकों के साथ नक्सलवाद से निपटने के लिए चर्चा करते हैं. इस बैठक में कई तरह की योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन राजधानी में बैठक ख़त्म होने के बाद फिर वही पुराना खेल शुरू हो जाता है. हर साल इस बाबत केंद्र सरकार से करोड़ों की धनराशि उग्रवाद प्रभावित राज्यों को दी जाती है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है. यहां ध्यान देने योग्य बात है कि नक्सल प्रभावित कई राज्यों में सुरक्षाकर्मियों से बेहतर हथियार नक्सलियों के पास उपलब्ध है. सुरक्षाकर्मियों को एक गोली चलाने के लिए जवाब देना होता है, लेकिन नक्सलियों को गोली चलाने के लिए कोई इजाज़त नहीं लेनी पड़ती. पिछले कुछ वर्षों में नक्सलियों की कार्रवाई में जितने सुरक्षाकर्मी मारे गए उनकी मौत का ज़िम्मेदार सही मायनों में सरकार ही है. इसके अलावा केंद्र सरकार और नक्सल प्रभावित राज्यों के बीच कई मामले में सहमति का भी अभाव देखा जा रहा है. मिसाल के तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की विवादास्पद सलवा जुडूम को लेकर यूपीए सरकार के साथ विरोध है. इसके अलावा बिहार और झारखंड सरकार नक्सलियों से निपटने के लिए जो नीति बनाई है, उस पर केंद्र सरकार को आपत्तियां भी है. ऐसे में यह कैसे संभव है कि जब सरकारें ही आपस में लड़ रही है तो नक्सलवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई कैसे संभव है. एक तरफ़ झारखंड में नक्सली सरकार के ख़िलाफ़ बग़ावत कर रहे हैं. वहीं जनवादी नेताओं की दलील है कि राज्य के आदिवासी इलाक़ों की उपेक्षा आज़ादी के बाद से ही हो रही है. यही वजह है कि इन क्षेत्रों में नक्सली सक्रिय हैं. छत्तीसगढ़ में स्थानीय आदिवासियों ने स्वरक्षा के लिए सलवा जुडूम (गोंडी भाषा में शांति यात्रा) संगठन बनाया है. इस संगठन के पक्ष और विपक्ष में लगातार आवाजें उठती रही हैं. दरअसल भारत में जिस तेजी से नक्सलवाद पनप रहा है वह देश के लिए एक बड़ी चुनौती है. सरकार बलपूर्वक इसका समाधान करना चाहती है, जबकि कई समाजशास्त्री मानते हैं कि इस समस्या की मूल वजह है वंचितों के बीच सामाजिक न्याय का आभाव. समाज का एक वर्ग लगातार अमीर होता जा रहा है, जबकि दूसरा हिस्सा दिनोंदिन कमज़ोर होता जा रहा है. आज जिनके पास ज़मीन है उसी के पास नौकरी है, जो भूमिहीन हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है. खासकर बिहार और झारखंड जैसे राज्य में जहां नक्सलवाद पनपने की मूल वजह है ज़मीन का असमान वितरण. जमींदारी ख़त्म होने के बाद राज्य में जो लैंड सीलिंग एक्ट लागू हुआ उसमें तमाम तरह की कमियां हैं. बिहार में आज भी ऐसे कई भू-स्वामी हैं, जिसने पास सैंकड़ों एकड़ ज़मीन है. यही वजह था कि कुछ वर्ष पहले मध्य बिहार में कई नरसंहार हुए हैं.

गढ़चिरोली में ख़ूनी खेल

गढ़चिरोली के धानोरा तहसील के झरी गांव में मंगलवार 20 सितंबर 2011 की रात माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर चुकी दो युवतियों की गोली मार कर हत्या कर दी. मृतका के नाम जासवंता उर्फ देवी आतला और रानू उर्फ किरन पोटावी हैं. दो साल पहले इन्होंने नक्सलियों का दामन छोड़कर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था. ख़बरों के मुताबिक़ स्थापना दिन के उपलक्ष्य में माओवादियों ने जिले में बंद का आयोजन किया था. दो दिन पहले जासवंता आतला व रानू पोटावी का गांव से अपहरण किया उसके बाद रात में धानोरा तहसील के झरी गांव ले जाकर दोनों को गोली मार कर हत्या कर दी गई. इस घटना से आसपास के इलाक़ों में दहशत का माहौल है. पुलिस अभी तक हत्यारे को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है. इसके बावजूद गढ़चिरोली में नक्सलियों का उत्पात अभी भी जारी है. नक्सली हमले में बेवजह निर्दोष लोगों की बलि चढ़ रही है. सबसे हैरत पुलिस की भूमिका को लेकर है. पुलिस गरीब आदिवासियों को नक्सलियों का समर्थक करार देकर गिरफ्तार कर रहे हैं. दूसरी तरफ़ नक्सली इन आदिवासियों को पुलिस का मुखबिर समझकर मार रही है. गढ़चिरोली, चंद्रपुर, गोंदिया, भंडारा जिले के आदिवासियों की हालत सरौते में फंसी सुपाड़ी जैसी हो गई है. अगर सरकार ने नक्सलियों से निपटने के लिए जल्द कोई क़दम नहीं उठाती है तो हालात बेकाबू हो सकते हैं.

विदर्भ में नक्सलवाद पूरी तरह फैल चुका है. इसकी पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा है. यहां वर्ष 1980 के बाद शुरू हुआ हिंसक आंदोलन दिन-ब-दिन अधिक घातक बनता जा रहा है. वर्ष 2011 में अब तक 13 पुलिस जवान नक्सली हमले में शहीद हो चुके हैं. हर साल ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं. माओवादियों ने महाराष्ट्र की सीमा से सटे आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश राज्य में आवागमन की सुविधा सुचारू न हो पाने की वजह से नक्सल गतिविधियों में तेजी आई है.

सीआरपीएफ के 5000 जवान तैनात

महाराष्ट्र के गृहमंत्री नक्सली आंदोलन को रोक पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं. नक्सली गुट सुनियोजित हमले कर पुलिस व आदिवासियों की हत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी हुई है. तमाम ख़ुफ़िया शाखाएं भी ठोस जानकारी देने में विफल हैं. वहीं इसके बरअक्स नक्सलियों की ख़ुफ़िया व्यवस्था अधिक सक्षम है. नक्सलियों को क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी पुलिस से कहीं ज़्यादा है. गढ़चिरोली में नक्सलियों का सफाया करने के लिए सी-60 के जवान तैनात हैं. इसके अलावा सरकार ने सीआरपीएफ के 5000 जवानों को भी तैनात कर रखा है, लेकिन इन दोनों में सही तालमेल नहीं होने की वजह नक्सली संगठन पुलिस पर हावी हो रहे हैं.

संयुक्त अभियान की ज़रूरत

गढ़चिरोली में नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती है. यहां वे पुलिस के ख़िलाफ़ गुरिल्ला लड़ाई में माहिर हैं. नक्सली पुलिस के बारे में हर छोटी-बड़ी सूचनाएं स्थानीय लोगों से हासिल करते हैं और उसके बाद अपनी रणनीति तैयार करते हैं. यही वजह है कि नक्सली हमले में पुलिस को ज़्यादा नुक़सान पहुंचता है. ग़ौरतलब है कि नक्सल प्रभावित इलाक़ों के लिए केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपये ख़र्च कर एक्शन प्लान बनाया है, लेकिन इस योजना की ज़मीनी हक़ीक़त निराश करने वाली है. बहरहाल अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है. नक्सली भी अपने ही देश के नागरिक हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं. लिहाज़ा सरकार को चाहिए कि वह हर स्तर से नक्सलियों से बातचीत करे और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश करे. बंदूक़ के बल पर शांति की उम्मीद करना बेमानी है. केंद्र सरकार को चाहिए कि वह नक्सल प्रभावित महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें.

कई शहर हैं नक्सलियों के निशाने पर

महाराष्ट्र के नक्सलियों की सक्रियता सिर्फ़ विदर्भ तक ही सीमित नहीं है. सूत्रों की मानें तो मुंबई, पुणे और नासिक में भी नक्सलियों ने अपना नेटवर्क फैला रखा है. इसकी तस्दीक केंद्रीय गृहमंत्रालय की रिपोर्ट से भी होती है. झारखंड को छोड़कर नक्सल प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र में नक्सली हमलों में इज़ाफ़ा हुआ है. आतंकवाद निरोधक दल ने चार महीने पहले पुणे के कुछ युवक-युवतियों को नक्सलियों से संबंध होने के आरोप में गिरफ्तार किया था.

बिग्रेडियर हेमंत महाजन
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिन्दी का पहला साप्ताहिक अखबार
महाराष्ट्र

सदस्यता फार्म (वार्षिक)

सदस्यता शुल्क- २५० /- रुपये

मैं "चौथी दुनिया" साप्ताहिक समाचार पत्र का सदस्य बनना चाहता/चाहती हूँ।

मेरा नाम श्री./ श्रीमती .....

मेरा पता .....

जिला.....राज्य .....पिन कोड.....

फोन (आ).....(का).....मोबाईल.....

ई -मेल.....

मैं रु. वार्षिक सदस्यता के लिए चेक क्रमांक.....

दिनांक .....बैंक.....शाखा..... द्वारा भेज रहा/ रही हूँ

नोट- यह सदस्यता शुल्क भारत में ही मान्य है तथा यह योजना सीमित अवधि के लिए है। समाचार पत्र केवल साधारण डाक द्वारा भेजा जाएगा।

सदस्यता शुल्क केवल चेक द्वारा आशीर्वाद पब्लिकेशन प्रा. लि. नागपुर के पक्ष में सदस्यता फार्म के साथ निम्नलिखित पते पर प्रषित करे या फिर हमारे प्रतिनिधी को फार्म कलेक्ट करने के लिए फोन पर सूचित करे.

कार्यालय

"चौथी दुनिया"- महाराष्ट्र,
आशीर्वाद पब्लिकेशन प्रा.लि.,
मुरलीधर कॉम्प्लेक्स, बुटीवाडा के सामने,होटल गणराज के बाजू में, टेम्पल बाजार रोड,सीताबर्डी, नागपुर.
फोन नं.-०७१२-२५४३१११ फैक्स- ०७१२-२५४७१११
Email: chauthiduniyaa@gmail.com

पाठक ध्यान दें

जिन पाठको कों चौथी दुनिया की वार्षिक सदस्यता चाहिए वे फार्म भरकर भेजें या कार्यालय में संपर्क करें.

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 17 अक्टूबर–23 अक्टूबर 2011

www.chauthiduniya.com

Website : sanjeevanibuildcon.in

"संजीवनी का है ऐलान, झारखण्ड-बिहार में हो सबका मकान"

AISHWARIYA RESIDENCY
Argora-Kathalmore Road, Ranchi
PLOT 6 LAC | DUPLEX 18 LAC

THE DYNASTY
Sidhu Kanhu Park, Kanke Road
PLOT 13 LAC | DUPLEX 25 LAC

SANJEEVANI HIGHWAY
Ranchi Patna Highway Road
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

SANJEEVANI TOWNSHIP
4 Lane, Kanke Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

SANJEEVANI STATION
BIT Pithoria, Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

9661337777 / 9472722024

9472727767 / 9162779209

फिर पड़ी बिजली की मार

बसाने के वादे और उजाड़ने की ज़िद. यह कहानी है बिहार में औद्योगीकरण के सपने की. अन्य सुविधाओं को भूल भी जाएं तो अकेले बिजली सरचार्ज को लेकर चल रहे तमाशे ने उद्योगपतियों के साथ-साथ आम आदमी के सिर पर इतना बोझ बढ़ा दिया कि लोग इसे आफ़त की बिजली कहने लगे हैं.

सरोज सिंह

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड महंगी बिजली ख़रीद के बहाने अल्प समय के अंतराल पर नियमित रूप से विद्युत ईंधन अधिभार लगा रहा है. इस अविवेकपूर्ण निर्णय से राज्य में बिजली की कीमत पड़ोसी राज्यों की तुलना में काफ़ी अधिक हो गयी है. परिणामत: घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं और उद्योग-धंधों की कमर टूटने लग गयी है. सामान्य विद्युत उपभोक्ता असंगठित होने के कारण इसका खुला विरोध तो नहीं कर पा रहे हैं पर इस मुद्दे को लेकर उनमें जो आक्रोश पनप रहा है, वह कभी भी विस्फोटक रूप लेकर राजग सरकार को मुसीबतों में डाल सकता है. इससे इतर उद्योग-व्यवसाय की धड़कनें बंद करने वाले विद्युत बोर्ड के इस कड़े क़दम के ख़िलाफ़ छोटे-बड़े तमाम व्यवसायी और उद्यमी संगठन आग उगलने लगे हैं. उद्योगपतियों के संगठन सरकार से अपनी नाराज़गी व्यक्त करने लगे हैं. राज्य सरकार की विकासपरक नीतियों की सराहना करने वाले और राज्य में उद्योगों के विकास के प्रति समर्पित रहने वाले संगठनों बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि ईंधन अधिभार को उद्योग विरोधी बता इसे वापस लेने या फिर सरकार द्वारा इसका भुगतान करने की मांग कर रहे हैं. इनकी यह मांग भी है कि सरकार बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यकलापों की जांच कराये. साथ ही पता करवाये कि इसे विद्युत संचरण एवं वितरण तथा चोरी के कारण कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है. इन संगठनों का स्पष्ट मानना है कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की इस मनमानी पर अंकुश नहीं लगा तो राज्य के बचे-खुचे उद्योग-धंधे भी चौपट हो जायेंगे. आम उपभोक्ता भी इस अधिभार से त्रस्त हैं. इस पहल ठगा-ठगा महसूस कर रहे हैं. राजग को दोबारा सत्ता में लाने वालों को नीतीश सरकार से यह उम्मीद नहीं थी. पूर्व में सरकार ने अक्टूबर 2008 से दिसम्बर 2008 तक का अधिभार विद्युत बोर्ड को ख़ुद दे दिया था. उपभोक्ताओं पर कोई बोझ नहीं पड़ा था. कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने उस समय दूसरे राज्यों में ईंधन अधिभार लागू होने की जानकारी मांगी थी जो शायद उपलब्ध नहीं करायी गयी. उस वक़्त जब ईंधन अधिभार का मामला उभरा था तब राज्य के मुख्य विपक्षी दल राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने की बात कही थी. संभवत: इसी के मद्देनजर सरकार ने ख़ुद भरपाई कर दी थी. अभी इस पर न विपक्ष का मुंह खुल रहा है और न सरकार ही राहत प्रदान करने वाली कोई कारगर पहल कर रही है. लगता है कि दोबारा सत्ता में आने के बाद राजग का आम जनता के प्रति नीयत और नज़रिया बदल गया है. ऐसा नहीं है तो फिर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की इस मनमानी पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा है?

जानकार बताते हैं कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को हो रहे घाटे की भरपाई के लिए इसने जो रवैया अपनाया है, उससे उद्योगों के बंद होने के हालात पैदा हो गए हैं. इसलिए कि ईंधन अधिभार सामान्य और औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं के लिए आवर्ती समस्या बन गयी है. पिछले तीस महीनों के दौरान तीन बार विद्युत दर बढ़ाये जाने के बावजूद सात बार ईंधन अधिभार का बोझ डाला गया. ऐसा आज तक अन्य किसी राज्य में कभी नहीं हुआ. यहां दिसम्बर 2010 से फरवरी 2011 तक 99 पैसे, मार्च एवं अप्रैल में 1.35 रुपए, मई में 0.45 पैसे, जून 2011 के लिए 1.18 रुपए प्रति यूनिट ईंधन अधिभार लगा दिया था. फिर, बेहिचक जुलाई 2011 के लिए 79 पैसे का ईंधन अधिभार लगा दिया है. इसके बावजूद अगस्त 2001 के लिए अधिभार लगाने की तैयारी में है. फ़िलहाल, यह व्यवसायिक उपभोक्ताओं से 200 यूनिट के ऊपर 7.32 रुपये प्रति यूनिट की दर से अधिभार वसूल रहा है. उद्योगपतियों के संगठनों के नेताओं के अनुसार ईंधन अधिभार लगने से पूर्व जिन औद्योगिक इकाइयों को औसतन एक लाख रुपया विद्युत विपत्र का भुगतान करना पड़ता था, उनके समक्ष अब 10 लाख रुपया अदा करने की विवशता आ गयी है. उनके मुताबिक़ बिहार विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत दर में की गयी औसतन 19 फ़ीसदी वृद्धि की सिफ़ारिश को 1 मई 2011 से लागू करने के बावजूद भूतलक्षी प्रभाव या मासिक आधार पर ईंधन अधिभार लगाने का कोई औचित्य नहीं है. राज्य के अधिसंख्य उद्यमियों का मानना है कि विद्युत बोर्ड आम उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी कर मनमाने ढंग से ईंधन अधिभार लगा रहा है. उनके मुताबिक़ विद्युत नियामक आयोग के पांच पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को नज़रअंदाज़ कर वह 99 पैसे प्रति यूनिट वसूल रहा है, जबकि वास्तविक ख़र्च 49 पैसा ही है. उनके मुताबिक़ ईंधन अधिभार में विद्युत बोर्ड के घाटे का अधिभार भी जोड़ा जा रहा है. ऐसा और किसी राज्य में नहीं हुआ करता है. इस सन्दर्भ में ग़ौर करने वाली बात यह भी है कि सर्वप्रथम नौ महीने के लिए ईंधन अधिभार लगाया गया था. उपभोक्ताओं ने विद्युत बोर्ड के वास्तविक ख़र्च 39 पैसे की तुलना में 69 पैसे की दर से लगाये गये अधिभार का भुगतान कर दिया था.

ईंधन अधिभार से सीमेंट एवं लौह-स्टील उद्योग ज्यादा प्रभावित हुआ है. बिजली इन उद्योगों के लिए कच्चा माल है. ख़ासकर लौह-स्टील उद्योग के लिए. उस पर 135 प्रतिशत ईंधन अधिभार का बोझ पड़ा है. स्टील मैन्युफेक्चर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर इस बोझ से इन उद्योगों को बचाने का अनुरोध किया है.

ईंधन अधिभार से सीमेंट एवं लौह-स्टील उद्योग ज़्यादा प्रभावित हुआ है. बिजली इन उद्योगों के लिए कच्चा माल है. ख़ासकर लौह-स्टील उद्योग के लिए इस पर 135 प्रतिशत ईंधन अधिभार का बोझ पड़ा है. स्टील मैन्युफेक्चर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर इस बोझ से उन उद्योगों को बचाने का अनुरोध किया है. स्टील मैन्युफेक्चर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुभाष के. पटवारी का कहना है कि लौह-स्टील उद्योग बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को राजस्व देने वाला बहुत बड़ा क्षेत्र है. ईंधन अधिभार लगाये जाने से इस इद्योग पर करोड़ों का आर्थिक बोझ पड़ गया है. कुछ इकाइयों को तो 10-10 करोड़ तक का भुगतान करना पड़ जा सकता है. ऐसी स्थिति में उनकी आर्थिक रीढ़ टूट सकती है. बिहार में कामधेनु टीएमटी बनाने वाली दादी जी स्टील लि. के प्रबंध निदेशक रमेश चंद्र गुप्ता का भी कहना है कि ईंधन अधिभार की मासिक मार इसी रूप में पड़ती रही तो न सिर्फ़ सीमेंट एवं लौह-स्टील उद्योग चरमरा जायेगा बल्कि अन्य उद्योगों पर भी इसका घातक असर पड़ेगा. वैसी स्थिति में नए निवेश की संभावनाएं तो समाप्त हो ही जाएंगी. जानकारों के मुताबिक़ बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में हो रहे भारी घाटे के लिए वह ख़ुद ज़िम्मेवार है. संचरण और वितरण घाटा 60 प्रतिशत है. बल्कि, कहा यह जाता है कि बोर्ड के अधिकारियों-कर्मचारियों की मिलीभगत से ही बिजली की खुलेआम चोरी होती है. बिहार विद्युत नियामक आयोग 29 फ़ीसदी संचरण एवं वितरण घाटा की इजाज़त देता है. पर, विद्युत बोर्ड इसे 38 फीसदी दर्शाता है, जबकि वास्तविक घाटा 60 फ़ीसदी है. इसे घटा दिया जाये तो अधिभार के रूप में राजस्व वसूली गयी राशि से दो गुना से अधिक आय होगी. बिहार विद्युत नियामक आयोग भी बोर्ड को संचरण एवं वितरण घाटा कम करने की सलाह देता रहा है. लेकिन, विद्युत बोर्ड के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते और ईंधन अधिभार लगाकर ईमानदार उपभोक्ताओं की जेबें खाली करते हैं. कहते हैं कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने पिछले चार वर्षों से विद्युत का ऑडिट नहीं कराया है. आयोग द्वारा मांगे जाने पर भी वह डाटा उपलब्ध नहीं करा रहा है. यह भी कहा जाता है कि विद्युत बोर्ड ने बिजली ख़रीद दोगुना कर दी है. पर, संग्रह मात्र 25 प्रतिशत ही है. फलत: पूर्व की तुलना में घाटे का गैप चार सौ प्रतिशत हो गया है. बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष एस.पी. सिन्हा और बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ओ.पी. साह ने ईंधन अधिभार न लगाने के अलावा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के क्रियाकलापों की उच्चस्तरीय जांच के साथ इस बात का भी पता लगाने की मांग की थी कि कितनी राशि की बिजली चोरी होती है. आश्चर्य है कि बिहार और झारखण्ड दोनों राज्य एनटीपीसी से बिजली ख़रीदते हैं. झारखंड में उपभोक्ताओं पर ईंधन अधिभार नहीं लादा गया है. बिहार में वसूला जा रहा है. झारखंड में उद्योगों का जाल बिछा हुआ है. इसके बावजूद वहां एक अगस्त 2011 से लागू होनेवाली नयी विद्युत दर बिहार में एक मई 2011 से लागू विद्युत दर से लगभग 20 प्रतिशत कम है. इस पर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड और राज्य सरकार को ग़ौर करना चाहिए. उद्योग संघों का यह भी कहना है कि देश के पांच राज्य ऐसे हैं जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा बिजली है. वे सस्ती दर पर इसे बेचना चाहते हैं. लेकिन, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एनटीपीसी से बिजली ख़रीदता है, जो अपेक्षाकृत अधिक महंगी है.

ईंधन अधिभार भूतलक्षी प्रभाव से वसूले जाने के कारण उद्यमियों को घाटा हो रहा है. जॉनसन पेंट्स के निर्माता उद्योगपति कृष्णा प्रसाद का कहना है कि पूर्व की तारीख़ से अधिभार लेने की सूचना उद्यमियों को नहीं रहती. वे अपने उत्पाद पर निर्माण ख़र्च और लाभ का अंश जोड़ इसे बेच लेते हैं. तब फिर पीछे की अवधि से अधिभार का भुगतान करने पर उन्हें सीधा नुकसान हो रहा है. चर्चित उद्योगपति दशरथ कुमार गुप्ता दुख व्यक्त करते हैं कि ईंधन अधिभार से त्रस्त उपभोक्ताओं के दर्द को कोई सुनने और समझने को तैयार नहीं है. उनके मुताबिक़ बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ईंधन अधिभार के रूप में रंगदारी टैक्स वसूल रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर अंकुश लगाने के लिए ठोस पहल करनी चाहिए अन्यथा बिहार में निवेश की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी.

feedback@chauthiduniya.com

उम्र के तकाजे ने भले ही इनको वकालती पेशे से अलग कर दिया है लेकिन क़ानून की किताबों का अध्ययन और सामाजिक सरोकार के न्यायादेशों की समीक्षा असगर साहब का मशग़ला है.

बार-बार मिल रही शिकायत के ही आधार पर खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, मुंगेर सहित अन्य सीमावर्ती इलाकों की पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है.

मार्टिन रेल की ज़मीन पर राजनीति

20वीं सदी की शुरुआत में पश्चिम बंगाल की कंपनी ऊषा मार्टिन द्वारा शाहाबाद की धरती पर शुरू की गयी लाइट रेलवे की महत्वाकांक्षी योजना अब रोहतास के राजनीतिक तबके में आपसी जोर आजमाइश का मुद्दा बन गयी है. सासाराम-आरा लाइट रेलवे के नाम से 1909 में शुरू हुई योजना जब 80 के दशक के अंत में आकर बंद हुई, तभी से इसकी जमीन पर कई दिग्गजों की कुदृष्टि लग गयी. अंत में सफलता मिली विधान पार्षद कृष्ण कुमार सिंह को जो फिलहाल जदयू के झंडावरदार हैं. जब कंपनी की तरफ से इनके परिजनों के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी की डील हुई तब ये राजद के खेमे में थे. समय ने करवट बदली और जदयू की सरकार बनने के साथ ही सिंह सत्ताधारी दल में शामिल हुए. उधर 2001 में त्रिस्तरीय पंचायत राज गठन के बाद रोहतास जिला परिषद में मार्टिन रेल की जमीन को लेकर

चर्चा और राजनीति शुरू हुई. कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रहे मामले को जानने के लिए जिला पार्षदों का दल भी वहां तक गया. कहा तो यह भी जाता है कि रोहतास जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी की नाप-तौल भी इसी जमीन के कारण कई बार की गयी. अब रोहतास जिले में ऊषा मार्टिन की इस जमीन को लेकर कैसर-ए-हिन्द की लड़ाई लड़ने के लिए एनडीए गठबंधन के अलावा अन्य विपक्षी दलों ने गोलबंदी शुरू की है. 8 सितम्बर को रोहतास जिले के राजद-लोजपा, सपा सहित अन्य वामपंथी दलों ने एकजुट होकर विधान पार्षद कृष्ण कुमार सिंह के सवाल पर राज्य सरकार को घेरने का प्रयास किया. इसके लिए समाहरणालय परिसर के सामने जनप्रदर्शन एवं धरना कार्यक्रम भी आयोजित हुए. सभी दलों ने नेताओं ने एक स्वर से विधान पार्षद पर राज सत्ता का दुरुपयोग कर कैसर-ए-हिन्द की जमीन जबरन दखल करने का आरोप लगाया. जिसमें नीतीश कुमार को भी घेरे में लेने का प्रयास किया गया. विरोधी दल के नेताओं ने इस जमीन को 1909 से पहले शाहाबाद जिला परिषद की संपत्ति बताकर 2009 से पूर्व 99 वर्ष पूरे होने पर इसे पुन: वापस लौटाने की वकालत की. विधान पार्षद के परिजनों द्वारा जमीन को लेकर ऊषा मार्टिन कंपनी के साथ की गयी डील को कानूनन अवैध करार देते हुए कहा कि अरबों रुपये के इस जमीन घोटाले में विधान पार्षद अकेले नहीं सत्ताधारी दल के कई विधायक व मंत्री भी पर्दे के पीछे से राजनीति कर रहे हैं. फिलहाल मामले को विरोधी दलों ने अपने हाथो में ले लिया है. आंदोलन की शुरूआत हुई है. इसी बहाने विधानसभा में राज्य सरकार को घेरने की तैयारी भी चल रही है. देखना यह है कि इस पूरे नाटक का पटाक्षेप कब तक हो पाता है.

ममता चौहान
feedback@chauthiduniya.com

सपनों को फिर कुचलेगी नीतीश की यात्रा

नीतीश कुमार ने लालू-राबड़ी शासन के ख़िलाफ़ पहली यात्रा चंपारण में दस जुलाई दो हज़ार पांच के दिन बगहा के अनुमण्डलीय मैदान से शुरू की थी. देश के सभी चैनलों और प्रिंट मीडिया ने इस यात्रा को हाईलाइट किया. उस मंच पर शरद यादव, सुशील कुमार मोदी, प्रभुनाथ सिंह, चंद्रमोहन राय, नरेंद्र सिंह, वृषिण पटेल जैसे नेता मौजूद थे.

जनाकांक्षा पूरा करने के लिए चम्पारण के भूमि से भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर ने यात्रा करके देश में कई जन आंदोलन किए. जिससे देश में धार्मिक, राजनीतिक कई परिवर्तन हुए. नीतीश कुमार भी चंपारण की भूमि से अब तक चार यात्रा कर चुके हैं और अब पांचवी की तैयारी में लग चुके हैं. चारों यात्राओं से इनकी आकांक्षाओं की पूर्ति हुई है. पहली बार सत्ता परिवर्तन के लिए न्याय यात्रा की शुरूआत की, दूसरी विकास यात्रा, तीसरी धन्यवाद यात्रा, चौथी विश्वास यात्रा. सभी यात्राओं से उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी हुई है, पर इनके राजनीतिक महत्वकांक्षाओं के आगे जनमानस के आकांक्षाओं की बलि चढ़ती गयी. जनमानस इस विश्वास पर अपनी आकांक्षाओं को बलि चढ़ाता गया कि देर सबेर नीतीश कुमार द्वारा जनाकांक्षा पूरी कर दी जायेगी. छांचवी बार के लिए नीतीश कुमार की यात्रा शुरू होने वाली है. इस यात्रा में कौन सी आकांक्षा हावी हो रही है, अब तो होने वाली यात्रा बतलाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं इस बार की यात्रा में भी जनाकांक्षा की बलि चढ़ जाए.

नीतीश कुमार जनाकांक्षा का ध्यान रखते हुए बड़ी होशियारी से अपनी यात्रा का आग़ाज करते हैं. इसलिए हर दूसरी बार स्थल परिवर्तन करके यात्रा की शुरुआत करते हैं. यात्रा के साथ ही पहली जनकांक्षा गौण पड़ जाती है. नीतीश कुमार अपनी दूसरी यात्रा में चंपारण से विकास यात्रा की शुरुआत की थी, जिसमें एक हजार करोड़ से ज्यादा का शिलान्यास किया गया था. डिग्री कॉलेज, पॉलीटेक्निक कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, स्टेडियम, बगहा को जिला बनाने आदि की घोषणा की, पर सभी घोषणाएं उनकी राजनीतिक महत्वकांक्षा के सामने बौनी होती गईं. अब पांचवी यात्रा की शुरुआत होने वाली है. नीतीश कुमार लालू राबड़ी शासन के ख़िलाफ़ पहली यात्रा चम्पारण की भूमि से दस जुलाई दो हजार पांच के दिन बगहा के अनुमण्डलीय मैदान से शुरू की थी. देश के सभी चैनल और प्रिंट मीडिया ने इस यात्रा को हाइलाईट किया. इस मंच पर शरद यादव, सुशील कुमर मोदी, प्रभुनाथ सिंह, चंद्रमोहन राय, नरेंद्र सिंह, वृषिण पटेल जैसे सरीखे नेता मौजूद थे. इन सब के बीच स्थानीय विधायक पूर्णमासी राम ने सत्ता परिवर्तन के लिए मुकुट पहना तलवार थमाकर राजतिलक किया. इसके बदले में नीतीश कुमार ने बगहा को पुलिस जिला से राजस्व जिला बनाने, चीनी मिल से किसानों का गन्ना बकाया का भुगतान, मजदूरों को रोजी रोटी के लिए बिहार से बाहर न जाने की घोषणा सरकार बनने से पहले की. 2005 के दिसम्बर में विधान सभा का चुनाव पूरा हुआ. लालू राबड़ी शासन का अन्त हुआ नीतीश का शासन शुरू हुआ. लोक सभा चुनाव आते देखकर दो साल बाद विकास का नारा देकर चम्पारण की भूमि से विकास यात्रा की शुरूआत नीतीश ने की. विकास यात्रा के दौरान उन्होंने कई घोषणाएं कीं. लेकिन सभी यात्राएं सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रहीं. अब नीतीश बाबू की दोबारा सरकार बन गयी और अब तक चम्पारण का विकास

चंपारण

अधूरा पड़ा हुआ है. इस बार पांचवी यात्रा की शुरुआत होने जा रही है. नीतीश बाबू की यात्रा और चम्पारण के अधूरे पड़े विकास पर बगहा व्यवहार न्यायलय के वरीय अधिवक्ता काशी नरेश सिंह बतलाते हैं कि चम्पारण का सबसे बड़ा विकास है कि यहां अपराध बंद हैं. अधूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा कारगर कदम उठाये जा रहें है. विकास के प्रश्न पर सामाजिक कार्यकर्ता अरमानी खां कहते हैं कि अपराध पर सरकार का नियंत्रण ख़त्म हो गया हैं. अपराधी और माओवदियों के गठजोड़ से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत कायम हो गया है. पुरानी स्थिति लौट आयी है. नीतीश कुमार को चम्पारण के लोगों ने अपराध नियंत्रण करने पर वोट दिया है नहीं तो विकास का नारा तो चम्पारण के लिए छलावा है. यहां पर विकास नहीं हुआ है. लेकिन अभी तक किसी भी योजना के लिए सरकार के पास जमीन भी उपलब्ध नहीं हुई है. यात्रा की शुरुआत से पहले ही प्रश्नों से बचने के लिए केवल सेमरा में किराए के मकान में आईटीआई कॉलेज का बोर्ड नीतीश ने लटकवा दिया है. यहां पढ़ाई नहीं हो रही हैं. विकास के प्रश्न पर बगहा के राकेश सिंह बताते हैं कि इस क्षेत्र में टूटी सड़कें, अस्पताल, विद्यालय बने हैं. पढ़ाई हो रही है. बगहा नगरपरिषद के वॉर्ड आयुक्त अवध नरेश सिंह कहते हैं कि लालू के जमाने में चीनी मिल के शोषण करने पर कार्यवाही होती थी पर इस सरकार में तो पूंजीपतियों के विरुद्ध में कोई बात भी नहीं सुनी जा रही है. बगहा चीनी मिल बगहा स्थित पंजाब नेषनल बैंक से किसानों के नाम पर 39 करोड 90 लाख रुपये लोन ले लिया है. किसानों को जानकारी नहीं हैं. इसकी जानकारी प्रशासन जनता दलयू के सांसद विधायक को है. पर कोई कार्यवही नहीं हो रही है. बाल्मीकिनगर के चंदन शर्मा बताते हैं कि घड़ारी की ज़मीन पर दबंगों का कब्जा है. निजात के लिए राजस्व मंत्री और मुख्यमंत्री के जनता दरबार का कई फेरा लगा चुका हूं, पर कुछ नहीं हुआ. किसान परशुराम तिवारी बताते हैं कि पिछले वर्ष मक्का बोने के समय में बीज कंपनियों ने किसानों को चूना लगाया. सरकार ने मुआवजे देने के लिए कहा लेकिन बहुत से किसान वंचित रह गये. धान की खेती हुई है. धान के खेती में फिर मक्कावाली बात दिखाई पड़ने लगी है. किसानों को फिर रोना आएगा. यूरिया के लिए किसानों में हाहकार मचा हुआ है.

बहरहाल एक बार फिर नीतीश कुमार की पांचवी यात्रा चम्पारण के बेतिया से नवम्बर माह की शुरुआत में होने जा रही है. इसके पहले मुख्यमंत्री से बगहा को खुद को राजस्व जिला बनराना, हरनाटांड़ में प्राथमिक स्वास्थ केंद्र खुलवाना, सेमरा और रामनगर में आईटीआई कॉलेज खुलवाना, लौरिया और बगहा में खेल के लिए स्टेडियम बनवाना, बगहा में अनुमंडल डिग्री कॉलेज, बेतिया में मेडिकल कॉलेज खुलवाना, कुमारबाग में इस्पात कारखाना का चलवाना, वनपटिया में चीनी मिल आदि यक्ष प्रश्न बीते हुए पांच वर्षों से इंतजार कर रहे हैं. अब देखना यह है कि इस यात्रा का क्या परिणाम निकलेगा.

डॉ. अरविंद नाथ तिवारी
feedback@chauthiduniya.com

कामिनी से दूर-दूर बहुत दूर रहो

मुन्ना सिंह

अनुताप करो, किन्तु स्मरण रखो जिससे पुन: अनुतप्त न होना पड़े. जब भी अपने कुकर्म के लिये तुम अनुतप्त होंगे, तभी परमपिता तुम्हें क्षमा करेंगे और क्षमा मिलने पर ही समझोगे, तुम्हारे हृदय में पवित्र सांत्वना आ रही है और तभी तुम विनीत, शान्त और आनन्दित होगे. जो अनुतप्त होकर भी पुन: इसी प्रकार के दुष्कर्म में रत होता है, समझना कि वह शीघ्र ही अत्यन्त दुर्गति में पतित होगा. सिर्फ मौखिक अनुताप तो अनुताप है ही नहीं, बल्कि वह अन्तर में अनुताप आने का और भी बाधक है. प्रकृत अनुताप आने पर इसके सभी लक्षण ही थोड़ा-बहुत प्रकाश पाते हैं. जगत में मनुष्य जो कुछ भी दु:ख पाता है, उनमें अधिकांश ही कामनी-कांचन की आसक्ति से आते हैं, इन दोनों से जितनी दूर हटकर रहा जाए, उतना ही मंगल. भगवान श्री श्रीरामकृष्णदेव ने सभी को विशेष रूप से कहा है, कामिनी-कांचन से दूर-दूर बहुत दूर रहो. कामिनी से काम हटा देने से ही ये मां हो पड़ती हैं. विष अमृत हो जाता है. और मां, मां ही है, कामिनी नहीं. मां शब्द के अन्त में गी जोड़कर सोचने से ही सर्वनाश. सावधान! मां को मागी (बंगला में बदचलन औरत को मागी कहते हैं) सोच न मरो. प्रत्येक की मां ही है जगत जननी! प्रत्येक नारी ही है. अपनी मां का विभिन्न रूप, इस प्रकार सोचना चाहिए. मातृभाव हृदय में प्रतिष्ठित हुए बिना स्त्रियों को स्पर्शन नहीं करना चाहिए- जितनी दूर रहा जाये इतना ही अच्छा, यहां तक कि मुखदर्शन तक नहीं करना और भी अच्छा है. मेरे काम-क्रोधादि नहीं गये, नहीं गये-कहकर चिल्लाने से वे कभी नहीं जाते. ऐसा कर्म, ऐसी चिन्ता का अभ्यास कर लेना चाहिए जिसमें काम क्रोधादि की गन्ध भी नहीं रहे-मन जिससे इन सबको भूल जाए. मन में काम क्रोधादि का भाव नहीं आने से वे कैसे प्रकाश पायेंगे? उपाय है- उच्चतर उदार भाव में निमंजित रहना. सृष्टितत्व, गणितविद्या, रसायन शास्त्र, इत्यादि की आलोचना से काम-रिपु का दमन होता है. कामिनी-कांचन सम्बन्धित किसी प्रकार की आलोचना ही उनमें आसक्ति ला दे सकती है. इन सभी आलोचनाओं से जितनी दूर रहा जाए, उतना ही अच्छा.

श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी द्वारा लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण से उद्धत

feedback@chauthiduniya.com

बच्चों का विशेष ध्यान रखें : डॉ. जे.एस. कश्यप

डॉ. जे.एस. कश्यप

आने वाले जाड़े के मौसम में बच्चे कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं. इस सिलसिले में चौथी दुनिया ने डेहरी ऑन सोन के जाने माने शिशु विशेषज्ञ डॉ. जे एस कश्यप से बात की. प्रस्तुत है ख़ास अंश.

नवजात बच्चों के लिए जाड़े में क्या उपाय करना चाहिए?

नवजात बच्चे कह त्वचा बहुत सेन्सेटिव होती है क्योंकि वह 9 महीने के बाद वह मां के गर्भ से बाहर आता है. इस समय वह नये वातावरण में प्रवेश करता है जिस कारण तापमान फ्लेक्चुएट होता है. इस वक़्त बच्चे पर खास ध्यान रखना चाहिए. बच्चे के सारे कपड़े समय-समय पर बदलते रहना चाहिए, कपड़े को डिटॉल से धोकर तथा सुखा कर रखना चाहिए, ताकि बैक्टीरिया फ्री रहे.

जाड़े में बच्चों को कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं और इससे बचने के क्या उपाय हैं?

बच्चों को जाड़े में अधिकतर निमोनिया ही होता है जिससे बचने के लिए बच्चों का विशेष ध्यान रखें. साथ ही उन्हें फ्रिज का पानी न पीने दें. बाहर ज्यादा देर तक न रखें. गरम कपड़े में रखें, बच्चों को ज़्यादा समय तक बाहर ठंढ में खेलने से भी मना करें. कमरे को गर्म रखने की कोशिश करें. कमरे से बाहर अचानक न निकलें. कपड़ों पर विशेष ध्यान दें. कहा जाता है कि आप तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब तक कि आप बचाव के उपायों पर ध्यान देंगे. सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप को यदि लगे कि बच्चे को निमोनिया या ठंड लग गयी है तो तुरंत अपने नज़दीकी अच्छे चिकित्सक से ज़रूर दिखाएं.

नीरज कुमार सिंह
feedback@chauthiduniya.com

हथियारों के जखीरे जमा हो रहे हैं

राजेश सिन्हा

कोसी के दियारा इलाक़े में व्यापक पैमाने पर न केवल हथियारों का ज़खीरा जमा किया जा रहा है बल्कि अवैध हथियार निर्माण का कार्य भी चल रहा है. लगातार हथियार निर्माण कर इसके जमा करने के पीछे अपराधियों या नक्सलियों की मंशा क्या है, यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा लेकिन यह भी तय है कि अगर इस मामले को अविलंब गंभीरता से नहीं लिया गया तो पुलिस के लिए नई मुसीबत पैदा होने की संभावनाओं से कतई इंकार नहीं किया जा सकता है. वैसे इस तरह की स्थिति को देखकर आस-पास के लोग सहमे-सहमे हैं. जानकार बताते हैं कि इस इलाक़े में अवैध हथियार निर्माण करने का सिलसिला पहले तो कुख्यात अपराधियों के द्वारा शुरू किया गया था, अब इस कार्य में माओवादियों की संलिप्तता भी काफ़ी हद तक बढ़ गई है. बीते कुछ माह पूर्व खगड़िया-मुंगेर ज़िला सीमा स्थित हरिणमार दियारा में अपराधियों तथा माओवादियों के बीच जिस तरह से गोलीबारी हुई और माओवादियों को अपराधियों ने मौत के घाट उतारा, वह अभी भी लोगों के ज़ेहन में है. अब जिस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, इसे देखकर हरिणमार दियारा, तौफिर दियारा, भूरिया दियारा सहित अन्य इलाक़े के लोग ख़ासे भयभीत हैं. लोगों का कहना है कि खगड़िया-मुंगेर सीमा का तौफ़ीर दियारा तथा भूरिया दियारा पहले से अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना रहा है. वर्षों पूर्व इस इलाक़े में घटित भीषण नरसंहार की घटना को अब भी भूलाना आसान नहीं है. पुलिस के द्वारा लगातार ऑपरेशन चलाकर हार्डकोर नक्सलियों के साथ-साथ अपराधियों को भी हथियारों सहित गिरफ्तार किया जा रहा है. बावजूद इसके पुलिस को बड़ी सफलता नहीं मिल पायी है. पुलिस मानती है कि दियारा इलाक़े में अवैध हथियार का निर्माण कर उन्हें पहले नाव फिर बाद में ट्रेन के द्वारा अन्य ज़िलों के साथ-साथ इसे दूसरे प्रदेशों में भी खपाया जा रहा है. लेकिन शायद पुलिस सच्चाई से या तो मुंह मोड़ रही है या ख़ुफ़िया तंत्र इस मामले में पूरी तरह असफल साबित हो रहा है. तभी तो इन इलाक़ों में अपराधियों के साथ-साथ माओवादियों की बढ़ती सक्रियता के कारण पुलिस प्रषासन को दिन में ही तारे देखने पड़ रहे हैं. इलाके की भौगोलिक बनावट के कारण पुलिस न ही अपराधियों पर नकेल कस पा रही है और न ही माओवादियों की करतूत पर विराम लगाम लगा पा रही है. बात अलग है कि खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा और मुंगेर पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई किए जाने के कारण कुछ छोटे-बड़े अपराधी असलहों के साथ पुलिस के हत्थे चढ़े हैं. लेकिन हक़ीक़त यही है कि अपराधी सुशासन पर भारी पड़ रहे हैं. हालात यह है कि किसी एक घटना का पटाक्षेप हो भी नहीं पाता है कि किसी दूसरी घटना को अंजाम देकर अपराधी और माओवादी सनसनी पैदा कर देते हैं.

सूत्रों की मानें तो मुंगेर ज़िले के बंदूक कारखाने में बतौर कारीगर कार्य कर चुके लोगों को अपराधियों के साथ-साथ माओवादियों द्वारा प्रलोभन देकर अपने साथ कर लिया गया है और दियारा इलाके में हथियारों का निर्माण कर इन्हें जमा किया जा रहा है. मुफलिसी के दौर से गुज़र रहे इस तरह के कारीगरों को अपराधिक गिरोह तथा माओवादियों के संगठन द्वारा या तो अच्छी खासी तनख्वाह दी जा रही है या प्रत्येक निर्मित हथियार के एवज में उन्हें अच्छी खासी रकम दी जा रही है. इस इलाके में निर्मित हथियारों को खपाने के लिए कई महादलित और गरीब परिवार के सदस्यों को भी लगाया जा चुका है. यहां के दक्ष कारीगरों के हाथों निर्मित हथियार की गुणवत्ता अन्य

दियारा

जगहों पर निर्मित हथियार से बेहतर है. इसीलिए कोसी के दियारा इलाकों में निर्मित हथियारों की मांग भी बेहद अधिक है. मुंगेर जिले के कई गांवों में अवैध हथियार निर्माण का धंधा परवान पर रहने के कारण जब पुलिस की दबिश अधिक बढ़ गई तब इस धंधे से जुड़े लोग दियारा की ओर रुख कर गए. बहिष्कृत हितकारी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष संजीव कुमार डोम का कहना है कि अवैध कार्यों से जुड़े लगभग एक दर्जन महादलितों को खगड़िया के तत्कालीन पुलिस कप्तान डॉक्टर कमल किशोर सिंह ने समाज की मुख्यधारा से जोड़कर रोजगार की ओर मुखातिब किया था. समाज की मुख्यधारा से जुड़ने वाले महादलितों को बहिश्कृत हितकारी संगठन के द्वारा रोजगार भी उपलब्ध कराए गए. फिलवक्त इस तरह की योजना शासन प्रशासन के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चलाई जा रही है. इसलिए अपराधी वर्ग के लोग गरीबी से तड़प रहे महादलितों को तरह-तरह के सब्जबाग दिखाकर अपराध की ओर मोड़ रहे हैं. संजीव के मुताबिक पुलिस को सर्वप्रथम दियारा इलाके में एक अभियान शुरू कर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना होगा, तभी स्थिति पर काबू पाया जा सकता है. दूसरी तरफ खगड़िया के पुलिस कप्तान मिठ्ठू प्रसाद का कहना है कि यह बात सही है कि कोसी के दियारा इलाके में अवैध हथियारों का निर्माण किया जा रहा है. लेकिन निर्मित हथियारों को तस्करी के बाबत अन्य जिलों के साथ-साथ दूसरे प्रदेशों में भेजा जा रहा है. पुलिस के द्वारा कई बार मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए निर्मित और अर्द्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए थे. एसपी के मुताबिक तीन नवनिर्मित देसी हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए खगड़िया जिला अंतर्गत मानसी थाना क्षेत्र के मटिहानी निवासी जितेंद्र कुमार यादव ने भी स्वीकार किया है कि वह लोग दियारा में निर्मित हथियारों को अन्यत्र बेचकर अच्छी खासी कमाई करते हैं. बार-बार मिल रही शिकायत के ही आधार पर खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, मुंगेर सहित अन्य सीमावर्ती इलाकों की पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है. खगड़िया के पुलिस कप्तान मिठ्ठू प्रसाद भी मानते हैं कि मुंगेर और खगड़िया के बीच अपराधियों की सक्रियता बढ़ी है. हथियार तस्करी और अवैध हथियार निर्माण की खबरें भी लगातार मिल रही है. इस तरह की स्थिति पर नियंत्रण पाने के बावत सभी थानाध्यक्षों को सख्त कदम उठाने का आदेश जारी किया गया है. पिछले दिनों में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कई अपराधियों को हथियारों के जखीरा सहित गिरफ्तार किया गया है. कई अपराधियों ने कई सनसनीखेज तथ्यों की जानकारी भी दी है. मुंगेर सहित अन्य सीमावर्ती जिले की पुलिस के सहयोग से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं. कई बार चलाए गए ऑपरेशन के दौरान दर्जनों अपराधी हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए हैं. बहरहाल, पुलिस अपने अभियान में कितना सफल हो पाती है, यह तो आने वाला वक़्त ही बताएगा.

feedback@chauthiduniya.com

हमारा भी देश सुपर पावर होता

अशरफ अस्थानवी

असगर हुसैन साहब कोई मामूली आदमी नहीं हैं. जिस उम्र को लोग जीवन का आख़िरी पड़ाव कहते हैं, उस इम्र में भी कानून की किताबों के साथ उठना-बैठना इनकी दिनचर्या में शामिल है. ग़जब की याद्दाश्त वाले 99 वर्षीय असगर हुसैन ने 1940 में पटना लॉ कॉलेज से एल.एल.बी. की डिग्री हासिल करने के बाद 1942 में पटना हाईकोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की और कुछ ही वर्षों में इज्जत और शोहरत की उन बुलन्दियों को छू लिया, जो बिरले लोगों को नसीब होती है. इसके पूर्व उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इंगलिश ऑनर्स किया और पूरे विश्वविद्यालय में टॉप किया. वे मगध विश्वविद्यालय बोधगया में लॉ फेकल्टी के 10 वर्षों तक डायरेक्टर भी रहे.

असगर हुसैन साहब पटना हाईकोर्ट के वरीय न्यायाधीश जस्टिस सैयद शह नैयर हुसैन के पिता ही नहीं कई नामी कानूनविदों के उस्ताद भी हैं. स्व. जस्टिस सरवर अली, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायीश जस्टिस राफत आलम, सुप्रिम कोर्ट के न्यायाधीश आफताब आलम और वी.पी.सिंह के अतिरिक्त पटना हाई कोर्ट के कई जज और नामी अधिवक्ता इनसे कानून का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं. इनमें मशहूर वकील और बिहार विधन परिषद् के अध्यक्ष ताराकांत झा, बिहार के महाअधिवक्ता रामबालक महतो, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश जस्टिस एस.के.कटरियार, जस्टिस एस. नाथ, जस्टिस अहसनुद्दीन अमानुल्लाह और लोकायुक्त आर.एन.प्रसाद के नाम उल्लेखनीय हैं. उम्र के तकाजे ने यद्यपि इनको वकालती पेशे से अलग कर दिया है लेकिन कानून की किताबों का अध्ययन और सामाजिक सरोकार के न्यायादेशों की समीक्षा असगर साहब का मशग़ला है. आज भी ये सिविल के एक्पर्ट माने जाते हैं.

पिछले रमज़ान के महीने में इन्होंने सात बार कुरान शरीफ की तलावत मुकम्मल की. अंग्रेजी, उर्दू एवं हिन्दी साहित्य से इन्हें गहरा लगाव है. उर्दू और हिन्दी समाचार पत्र खूब पढ़ते हैं किन्तु उर्दू पत्रकारिता के स्तर को उठाने की जरूरत को शिद्दत से महसूस भी करते हैं. हिन्दी पत्रकारिता से वे काफी प्रसन्न हैं. परन्तु निष्पक्ष पत्रकारिता न होने से वे दुखी हैं. अंग्रेजी पत्रकारिता को स्तरीय मानते हुये इसे अन्य पाठकों को पढ़ने के लिये कहते हैं. वैश्वीकरणी के इस दौर में अंग्रेजी समाचार पत्रों की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता. फिर भी वे हिन्दी और उर्दू की तुलना में वे अंग्रेजी समाचार पत्रों को संतुलित और निष्पक्ष मानते हैं.

अपने वकालती पेशे के आरम्भिक दिनों को याद करते हुये असगर साहब हिन्दुस्तान के हिस्से-बखरे की दुखद घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना नहीं भूलते हैं. कहते हैं मैनें जिस समय प्रैक्टिस शुरू की थी स्वतंत्राता संग्राम अपनी आखिरी मंजिल में था. मैं दो कौमी विचारधरा का कट्टर विरोधी था. कुछ लोगों की वजह से देश विभाजित हो गया. पढ़े-लिखे और क्रीम मुसलमानों का एक तबका मौलाना अबुल कलाम आजाद के लाख समझाने-बुझाने के बावजूद पाकिस्तान चला गया. अगर देश नहीं बंटता, भाई-भाई नहीं बंटते और आंगन में दीवारें नहीं उठती तो आज हमारा देश भी सुपर पावर कहलाता. जो लोग पाकिस्तान गये उनकी हालत तो अच्छी नहीं ही है, वे महाजिर हैं. खुद पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़ा हुआ महसूस हो रहा है.

अपने सीनियर्स का जिक्र करते हुये असगर साहब बड़े प्रसन्न दिखते हैं. कहते हैं कि याकूब यूनुस साहब के पिता हुसैन यूनुस साहब और बैरिस्टर खलीक साहब बड़े और नामचीन कानूनविदों में शुमार होते थे. वे लोग मुझ से बड़ा स्नेह रखते थे. उस जमाने में उनका सिक्का चलता था. वैसे लोग मेरे रहनुमा रहे हैं. मैं इस मायने में बड़ा भाग्यशाली हूं. आज के दौर के वकीलों की जब बात चलती है तो असगर साहब थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं. फिर कहते हैं कि आज कल लोग मेहनत नहीं करते हैं. कानून की किताबों को पढ़ने अपने फील्ड में महारत हासिल करने के बजाए रातों-रात करोड़पति बन जाने की फिराक में लगे रहते हैं. अपने सीनियर्स से सलाह नहीं लेते. यही वजह है कि जजों को अपनी दलीलों से प्रभावित नहीं कर पाते हैं. वकालत में कामयाबी के लिए महारत और हाजिर जवाबी जरूरी है. अब यह खूबी बहुत कम लोगों में रह गई है. वकालत जैसे पवित्र पेशे के साथ भी अब नाइंसापफी होने लगी है.

असगर हुसैन साहब पटना हाईकोर्ट के वरीय न्यायाधीश जस्टिस सैयद शाह नैयर हुसैन के पिता ही नहीं कई नामी क़ानूनविदों के उस्ताद भी हैं. स्व. जस्टिस सरवर अली, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायीश जस्टिस राफत आलम, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आफताब आलम और वी.पी.सिंह के अतिरिक्त पटना हाईकोर्ट के कई जज और नामी अधिवक्ता इनसे क़ानून की शिक्षा ले चुके हैं.

feedback@chauthiduniya.com